

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

आक्स

वर्ष : 21 | अंक : 01

01 से 15 अक्टूबर 2022

पृष्ठ : 48

मूल्य : 25 रु.



संघ का कौम जोड़ी अभियान

मुस्लिम कट्टरपंथियों से लड़ने के लिए आउटरीच का हिस्सा है मोहन भागवत का मस्जिद दौरा

भागवत का उमर इलियासी से मुलाकात करना हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयासों के लिए विशेष

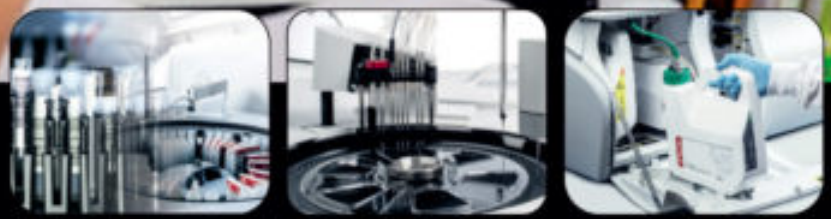
ANU SALES CORPORATION



We Deal in Pathology & Medical Equipment



BioSystems
The Highest Flexibility



Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

☎ 9329556524, 9329556530 ✉ Email : ascbhopal@gmail.com

● इस अंक में

हकीकत

9 | पटवारी सबसे अधिक घूसखोर

मप्र में सरकार जीरो टॉलरेंस पर जितना जोर दे रही है, प्रदेश में भ्रष्टाचार उतना जोर पकड़ता जा रहा है। अगर यह कहें कि मप्र में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रदेश में बिना रुपए दिए कोई...

राजपथ

10-11 | 114 सीटों पर होगा घमासान

मिशन 2023 को लेकर इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिशन मोड में काम कर रही हैं। भाजपा की कोर कमेटी और प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के साथ ही आला नेताओं के बीच हुए मंथन के बाद यह साफ हो गया है...

राजतंत्र

14 | मंत्री बनने की चाह में रोड़ा

मप्र में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेजी से चल रही हैं। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय, सामाजिक, जातिगत फॉर्मूले के अनुसार विस्तार करेगी। ऐसे में कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है...

कैम्पस

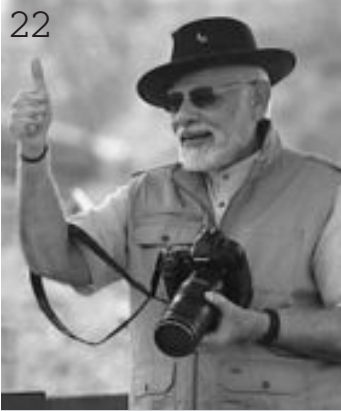
20 | 1330 करोड़ का कारोबार

वर्तमान में प्रदेश में कोचिंग कारोबार 1330 करोड़ के पार हो चुका है। आश्चर्य यह है कि इनमें 703 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी उन बच्चों की है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बच्चों के लिए निजी स्कूलों की पढ़ाई काफी नहीं है, अगर है तो वे क्यों इस जाल को...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28



भारत तेजी से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बनने के बाद से भारत के प्रति विदेशियों का नजरिया बदल रहा है। ऐसे में देश के अंदर कई बदलाव की जरूरत है। इनमें सबसे पहला है हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत करना। दरअसल, भारत में पिछले कुछ सालों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। इससे विदेशों में भारत की छवि धूमिल हो रही है। इसको देखते हुए संघ ने कौम जोड़ो अभियान शुरू किया है, जिसका मुसलमानों ने भी समर्थन किया है।



राजनीति

30-31

दिल्ली अभी दूर है

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली इस यात्रा से राहुल गांधी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। लेकिन यह यात्रा 2024 में कांग्रेस की किस्मत बदल पाएगी इस पर...

महाराष्ट्र

35

शिंदे गुट पर निर्भरता...

महाराष्ट्र में 22 जून को शिवसेना में हुई बगावत के बाद भाजपा के सहयोग से बनी एकनाथ शिंदे की सरकार को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन सरकार की स्थिरता को लेकर भाजपा असहज है और अपने दम पर सरकार को स्थिर करने की रणनीति बनाने में जुटी है।

बिहार

38

नीतीश कुमार का 'मिशन दिल्ली'

सबको मालूम है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और उनके निशाने पर क्या है। बीते महीने बिहार में पार्टनर बदलकर उनके गैर भाजपाई सरकार का सरदार बन जाने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अब तक वो स्वयं...

6-7 अंदर की बात

41 महिला जगत

42 अध्यात्म

43 कहानी

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य



9 दिन ही नहीं आजीवन बचें पाप कर्म से...

हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है...

अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयति प्रज्ञा भुशीलत्वदमौ श्रुतं च।
परक्रमश्चबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च॥

यानी आठ गुण मनुष्य को भुशोभित करते हैं - बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्म-संयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इन गुणों का पालन हम केवल नवरात्रि जैसे पावन अवसरों पर ही करते हैं। इस समय शास्त्रीय नवरात्रि का समय चल रहा है। बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक पूजा-पाठ, व्रत, ध्यान, दान आदि में लीन हैं। इन दिनों अधिकतर लोग न तो कोई नशा कर रहे हैं और न ही ऐसे कर्म जो पाप की श्रेणी में आते हैं। भवाल उठता है कि आखिर हम 9 दिन ही पाप कर्म से क्यों बचते हैं। अगर आजीवन पाप कर्म से बचने की कोशिश करें तो हमारा पूरा जीवन पावन, पवित्र हो सकती है। हिंदू धर्म में हर त्योहार से जुड़ी कई परंपराएं व मान्यताएं हैं। ऐसी ही कुछ परंपराएं नवरात्रि पर्व से भी जुड़ी हैं। इस बार 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक शास्त्रीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान सभी प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। नवरात्रि में सभी भक्त अपने-अपने तरीकों से देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जैसे इस दौरान क्या न करें? मान्यता है कि नवरात्रि में कुछ विशेष काम करने से देवी नाराज हो जाती हैं और उसके अशुभ फल हमें निकट भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान हम तामसिक भोजन से बचते हैं। जैसे मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि। नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से मन पर नियंत्रण रखते हैं। सिर्फ तन से ही नहीं मन और वचन से भी इस व्रत का पालन करते हैं। जैसे तो जीवन में कभी-भी किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए और नवरात्रि के दौरान तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे तो नशा करना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए जीवन में कभी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर कोई घर पर कुछ मांगने आता तो हम उसे ब्राह्मी हाथ नहीं लौटाते हैं। ऐसे में भवाल उठता है कि आखिरकार हम इन नियमों का पालन केवल 9 दिन ही क्यों करते हैं। अगर वाकई हमें अपना जीवन सफल बनाना है, सुखी और स्वस्थ रहना है तो नियमों का पालन पूरे जीवन करना चाहिए। केवल 9 दिन तप, तपस्या, पूजा-पाठ करने से न तो हमारा भव सुधरेगा, न ही सुख और सफलता मिलेगी। इसलिए हमें जीवन में सारी वर्जनाओं से ताउम्र दूर रहना चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि हम शास्त्रीय और चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अपने आपको पावन और पवित्र रखने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद उन सारे अपकर्म में जुट जाते हैं, जो वर्जित हैं। ऐसे में न तो हम अपना वर्तमान और न ही भविष्य सुधार पाते हैं। नवरात्रि के ये पावन पवित्र दिन हमें बड़े संदेश देते हैं। जिस तरह हम इन दिनों में हर तरह के गलत काम करने से बचते हैं। उसी तरह जीवनपर्यन्त रहना चाहिए। इससे न केवल आदिशक्ति की कृपा हम पर बरसेगी बल्कि हमारे सारे दुख, दारिद्र्य दूर होंगे। अतः हमें आजीवन बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्म-संयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान करना चाहिए। ताकि हमारी राह की सारी बाधाएं दूर हो सकें। यह काम अगर इस नवरात्रि से ही शुरू कर दिया जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा।

- राजेन्द्र आगाल

पाठक
अक्षर

वर्ष 21, अंक 1, पृष्ठ-48, 1 से 15 अक्टूबर, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जेन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफैक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPEPL/642/2021-23

ब्यूरो

कोलकाता:- इंद्रकुमार, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संपादकता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव

089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी

075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्क्लेव मायापुत्री

फोन : 9811017939

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,

फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,

भिलाई, मोबाइल 094241 08015

इंदौर : नवीन खुशवंशी, खुशवंशी कॉलोनी, इंदौर,

मो.-9827227000

देवास : जय सिंह, देवास

मो.-7000526104, 9907353976

स्वाधिकाारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जेन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



नाथ के हाथ में कांग्रेस

कमलनाथ राज्य में कांग्रेस को अपने हिस्सा से चला रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पंद्रह साल बाद सत्ता में वापस लौटी तो कमलनाथ ने इसे अपनी रणनीति की जीत के तौर पर लिया। आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कमलनाथ अपने हिस्सा से सबकुछ देख रहे हैं।

● हेमंत शिवहरे, इंदौर (म.प्र.)

मजदूरी में देरी

कोरोना के संक्रमणकाल में जहां एक तरफ शहरों से लोग गांवों में पलायन करने को मजबूर थे। वहीं गांव के लोगों के मनरेगा संजीवनी बनकर उभरी थी। लेकिन मनरेगा द्वारा मजदूरों को भुगतान करने में देरी हो रही है। जिससे गरीबों को जीवन-यापन करने में परेशानी हो रही है।

● दिनेश शर्मा, सीहोर (म.प्र.)

ग्रामीणों में जागरूकता लाएं

प्रदेश में ग्रामीण आबादी में साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद आधुनिक चिकित्सा के प्रति भरोसा उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। गांवों में जागरूकता अभियान को गहन करना होगा। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के साथ ही उन्हें जागरूक करना चाहिए।

● प्रणव कुमार, भोपाल (म.प्र.)



कांग्रेस को मजबूत करने निकले राहुल गांधी

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 13 सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस निगम-भारत को अपने पक्ष में एकजुट करना चाहती है। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उसकी यह आकांक्षा और प्रयास स्वाभाविक हैं। इस नाते और भी ज्यादा कि वह नब्बे के दशक में निगम-भारत की बुनियाद डालने वाली पार्टी है। यात्रा के उद्देश्य भले ही जनहितैषी हैं लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने और कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का जोरिम उठाया है। राहुल की इस यात्रा के परिणाम क्या होंगे, यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन सत्तापक्ष के माथे पर बल जरूर पड़ गया है।

● नैना कुमारी, जबलपुर (म.प्र.)

महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही

मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर उत्पाद शुल्क इतना बढ़ा दिया है कि इससे उसका राजस्व 2014-15 में लगभग 99,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 3.73 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन इसका सारा बोझ आम आदमी के कंधों पर आ गया है। एक तो पहले से ही आम आदमी कोरोना से उभरने में जूझ रहा है। लोगों के काम-धंधे छिन चुके हैं। उसके ऊपर पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

● करमवीर सिंह, नई दिल्ली



बिजली की मार

प्रदेश में जल विद्युत प्रोजेक्टों की क्षमता 921 मेगावाट है। इसके मुकाबले केवल 300 मेगावाट ही उत्पादन किया जा रहा है। यह उत्पादन भी मप्र जेनको के स्वामित्व वाली जल विद्युत इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली की लागत महज 25 पैसा प्रति यूनिट आती है, जबकि उसे लगभग 4 रुपए प्रति यूनिट में बेचा जाता है। ऐसे में इस बिजली से 3.75 रुपए तक प्रति यूनिट तक की बचत होती है।

● प्रमोद शर्मा, ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में कलह

सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस को जम्मू-कश्मीर में एक और बड़ा झटका लग सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि महाराजा हरि सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 'मैंने वर्ष 1967 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, लेकिन आज पार्टी से मेरे रिश्ते न के बराबर हैं। वर्किंग कमेटी से भी मुझे बाहर कर दिया गया। हां, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मेरा कोई संपर्क नहीं है। कोई मुझसे किसी भी चीज के लिए बात नहीं करता। मैं अपना काम करता हूँ। मेरे पार्टी से रिश्ते न के समान हैं।' कर्ण सिंह के इस बयान को उनकी ओर से कांग्रेस छोड़ने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर रियासत के आखिरी महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह 1967 से 1973 तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे। हालांकि बीते कई सालों से वह उपेक्षित चल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की तरह ही कर्ण सिंह से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे रिश्ते हैं। हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका विमोचन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और कर्ण सिंह की इस मौके पर जमकर तारीफ की थी। कर्ण सिंह ने भले ही अपने अगले प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन उनके पार्टी छोड़ने के कयास लगने लगे हैं।

नीतीश की नींद उड़ाएगी भाजपा!

बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल के बीच भाजपा ने नीतीश की नींद उड़ाने की तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को घेरने के लिए भाजपा नेता 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन राज्यभर में 15 मिनट का मौन धरना देंगे। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना स्थित भाजपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरकर कहा कि बिहार में महागठबंधन की नई सरकार आने के बाद अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसके खिलाफ 2 अक्टूबर को भाजपा नेता राज्यभर में 15 मिनट का मौन धरना देंगे। साथ ही 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े में भाजपा के कई कार्यक्रम होंगे। राज्य की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में राज्य विधानसभा चुनावों को लेकर गंभीर है। इसके लिए वह अभी से नीतीश की नींद उड़ाने में जुट गई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डीजीपी के साथ हाईलेवल मीटिंग बुलाई। साथ ही पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया समेत 11 जिलों में एसपी ग्रामीण के पद भी सृजित किए गए हैं। गौरतलब है कि सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है।



भाजपा को मजबूती देने में जुटे राजभर

राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अधोषित रूप से भाजपा के साथ घुल-मिल चुके सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर इन दिनों बिहार में सक्रिय हैं। वह बिहार सरकार पर जातिवार जनगणना कराने का दबाव रैलियों के माध्यम से बनाते हुए अति पिछड़ों में पैठ बनाने की कोशिश में हैं। राजभर की बिहार में सक्रियता के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका बिहार अभियान अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को मजबूत करने के लिए है। ठेट पुरबिया और खड़ी बोली व भोजपुरी की खिचड़ी से लोगों को संबोधित करने के कारण ओम प्रकाश राजभर को उनका समाज पूरे मनोयोग से सुनाता है। उप्र में पूर्वांचल में जमीन तलाशने के बाद राजभर ने अपना रुख अचानक पूर्वांचल से सटे बिहार की तरफ कर दिया है। पिछले करीब एक महीने से दो-चार दिनों के अंतराल पर बिहार में एक रैली कर रहे हैं। इन रैलियों के माध्यम से वह सीधे पिछड़ा समाज से आने वाले वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं। राजभर अपनी रैलियों के माध्यम से दोनों नेताओं को जातिवार जनगणना कराने की याद दिला रहे हैं। राजभर बिहार के मंचों से सीधे-सीधे यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तक दोनों नेता जातिवार जनगणना में भाजपा को आड़े हाथों लेते थे।

दिल्ली मॉडल से जीतेगी दिल!

साल के अंत में होने वाले गुजरात, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 'दिल्ली मॉडल' के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। भाजपा के मुकाबले राज्य में कमजोर राजनीतिक ताकत होने के बाद भी दृष्टिकोण की लड़ाई में केजरीवाल भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने हर स्तर पर अपनी चाक-चौबंद रणनीति से एक बार फिर गुजरात फतेह की तैयारी करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में कथित शराब घोटाला भी गुजरात में चर्चा में है और यह आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी घुसपैठ कर राजनीतिक लड़ाई को बदलने की कोशिश में है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात पर अपना जोर लगा रही है, ताकि भविष्य में केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत कर सके। 'आप' की चुनावी रणनीति को लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दिल्ली मॉडल के जरिए आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में भी जनता का दिल जीतना चाहती है।

कौन होगा कांग्रेस का कप्तान ?

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की है। थरूर ने मिस्त्री से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया और चुनावी नियम के बारे में जानकारी ली। इस मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि थरूर ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। साथ ही मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अब तक तीन नेताओं के नाम उभरकर सामने आने से तमाम कयासों के बीच अशोक गहलोत ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बीच सोनिया गांधी ने भी साफ कर दिया है कि वह पार्टी के अगले अध्यक्ष के लिए आगामी चुनाव में किसी का पक्ष नहीं लेंगी। कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से भी यही बात कही थी।

पर्चेबाजी के पीछे कौन ?

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों जमकर पर्चेबाजी हो रही है। दो-तीन तरह के पर्चे अफसरों, मीडिया कर्मियों और नेताओं के बीच बांटे गए हैं। इन पर्चों में से एक में प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। पर्चे में बड़े साहब के साथ ही उनके करीबी कुछ अफसरों की तथाकथित काली करतूतों को गिनाया गया है। इस पर्चे की हकीकत क्या है, यह तो कोई नहीं जानता लेकिन उसमें की गई आंकड़ेबाजी देख और पढ़कर लोग अर्चभित हो रहे हैं। पर्चे को लेकर तरह-तरह की कयासबाजी भी चल रही है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कोई इसे सही ठहरा रहा है तो कोई आधी हकीकत, आधा फसाना बता रहा है। दरअसल, बड़े साहब जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में यह पर्चेबाजी किसी सुनियोजित रणनीति के तहत की जा रही है। इस पर्चेबाजी के पीछे असली चेहरा कौन है, यह किसी को नहीं पता है, लेकिन सेवानिवृत्त हो चुके तीन एसीएस को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जबकि जानकारों का कहना है कि उन बेचारों का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। उधर, खबर यह है कि कुछ खबरचियों ने बड़े साहब के खिलाफ की जा रही इस पर्चेबाजी की तह में जाने के लिए पड़ताल शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में अफसरों की कमाई और निजी संबंधों को लेकर अक्सर पर्चेबाजी होती रहती है।

प्रमुख सचिव पर भारी अपर सचिव

प्रदेश के एक सबसे बड़े विभाग में प्रमुख सचिव की कुर्सी संभाल रहे एक आईएएस अधिकारी पर उन्हीं के विभाग का प्रमोटी अपर सचिव भारी पड़ रहा है। गौरतलब है कि 1996 बैच के उक्त आईएएस अधिकारी अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। आलम यह है कि वे विभागीय मंत्री को भी घास नहीं डालते हैं। लेकिन अब साहब के सामने जैसे को तैसे वाली स्थिति आन खड़ी हुई है। यानी अभी तक दूसरों को परेशान करने वाले साहब अब अपने मातहत से ही परेशान हैं।



दरअसल, अपर सचिव भी कोई ऐरे-गैरे नहीं हैं। उनका राजनीतिक रसूख काफी बड़ा है। उनकी पत्नी विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक पहुंच काफी ऊपर तक है। इसलिए साहब अपने रसूख की छाया में प्रमुख सचिव को रत्तीभर भी भाव नहीं देते हैं। आलम यह है कि बड़े साहब पूरब चलने को कहते हैं तो छोटे साहब पश्चिम की ओर चलने लगते हैं। दरअसल, बहुत दिनों बाद छोटे साहब को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। अब बड़े साहब की समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें भी तो क्या करें। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वे छोटे साहब का बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। अब देखना यह है कि दोनों अफसरों की दिशाएं आपस में मिलती हैं कि नहीं।

मंत्रीजी का सखा प्रेम

प्रदेश मंत्रिमंडल में ग्वालियर-चंबल अंचल से आने वाले एक मंत्रीजी सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं। कभी अपने उटपटांग बयानों के कारण तो कभी अपनी उल्टी-पुल्टी करतूतों के लिए हाल ही में साहब प्रशासनिक मुखिया से टकराव के कारण चर्चा में रहे थे। यह मामला प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में जमकर चला था। हालांकि बाद में सरकार के हस्तक्षेप के बाद मंत्रीजी नरम पड़े। कभी नरम तो कभी गरम रहने वाले मंत्रीजी वैसे तो कई कारणों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वे अपने सखा प्रेम के कारण चर्चा में हैं। मंत्रीजी का सखा प्रेम इस कदर है कि वे सरकार के मुखिया के दिशा-निर्देशों को भी दरकिनार कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में मंत्रीजी ने जिसे अपना विशेष सहायक बना रखा है, वे नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। ये महाशय मंत्रीजी के साथ पढ़ाई के साथ खेले-कूदे भी हैं। इसलिए मंत्रीजी की इन पर विशेष कृपा बरसती है। इसी कृपा का परिणाम है कि इनके रिटायर होने के बाद भी इन्हें अपना विशेष सहायक बनाकर रखा है। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पत्थर पर भी दूब उगा लेते हैं। इसलिए मंत्रीजी ने इन्हें सरकार के दिशा-निर्देशों को दरकिनार करते हुए अपने साथ रखा है, ताकि ये उजाड़ में भी मंत्रीजी के लिए हरियाली की व्यवस्था कर सकें। बताया जाता है कि मंत्रीजी के सखा इन दिनों दोनों हाथों से लक्ष्मीजी की कृपा बटोर रहे हैं, जिससे मंत्रीजी भी उन पर न्यौछावर हैं।

बरस रही भाभीजी की कृपा

राजधानी के एक पड़ोसी जिले के डीएसपी पंडितजी पुलिस मुख्यालय से लेकर राज्य मंत्रालय तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। साहब ने कोई तीर नहीं मारा है, बल्कि अपनी कारस्तानियों के कारण चर्चा में हैं। दरअसल, साहब जिस जिले में पदस्थ हैं, वहां धड़ाधड़ जमीनों का सौदा कर रहे हैं। साहब के जमीन प्रेम की बातें उस जिले से होते हुए राजधानी की प्रशासनिक वीथिका में पहुंच गई हैं। लेकिन उनका रसूख ही ऐसा है कि कोई उनसे सवाल-जवाब करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दरअसल, साहब के ऊपर प्रदेश की सबसे दमदार महिला का हाथ है। ऐसा खुद साहब बखान करते हैं। दरअसल, कभी साहब की उक्त भाभी ने उन्हें राखी बांधी थी। साहब ने उस बात का जिक्र करके अपनी धाक इस कदर जमाई है कि बड़े से बड़ा अफसर भी उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अब साहब अगले माह रिटायर होने वाले हैं। लेकिन बिना किसी डर के वे अपने नाम से संपत्ति खरीद रहे हैं। जब कोई उनसे इस बारे में कहता है तो वे कहते हैं कि मेरे ऊपर भाभी का हाथ है। मुझे कायदे-कानून की कोई परवाह नहीं है।

महिला निरीक्षक सब पर भारी

बुंदेलखंड क्षेत्र के एक जिले में एक महिला निरीक्षक सब पर भारी पड़ रही है। दरअसल, यह महिला निरीक्षक जिले के एसपी की सबसे खास मातहत बनी हुई हैं। आलम यह है कि एसपी साहब भी इस महिला निरीक्षक के सामने परत पड़े हुए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में आईजी की शिकायतों के बाद उक्त महिला को उसकी पसंदीदा जगह से हटा दिया गया। इसके बाद भी उक्त महिला अधिकारी पूरे जिले की प्रभारी बनी हुई है। जिले की पुलिस व्यवस्था में हस्तक्षेप के साथ ही इस महिला का साहब के घर में भी हस्तक्षेप बढ़ गया है। इस कारण साहब के घर में गृहयुद्ध की नौबत आ गई है। बताया जाता है कि अपनी सेवाभाव से उक्त महिला अधिकारी ने साहब को इस कदर अपने वश में कर लिया है कि एसपी साहब का उससे मोह भंग नहीं हो पा रहा है। साहब की इस कमजोरी का उक्त महिला अधिकारी जमकर फायदा उठा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जिले में वे जो चाहती हैं वह करवा लेती हैं। यहां बता दें कि साहब भी कोई ऐरे-गैरे नहीं हैं, बल्कि वे देश के एक बड़े मीडिया घराने के दामाद भी हैं।



राजस्थान में जो कुछ भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ है। मैंने कभी आलाकमान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है और न कभी उठाऊंगा। राज्य में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसा चाहेंगे कांग्रेस में वही होगा।

● अशोक गहलोत



पीएफआई पर केंद्र सरकार ने उचित समय पर प्रतिबंध लगाकर बड़ा काम किया है। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन लगातार देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे। इससे देश का माहौल बिगड़ रहा था। मप्र में सिमी की तरह पीएफआई भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो गया है।

● नरोत्तम मिश्रा



इस समय भारतीय क्रिकेट टीम विश्व में सबसे मजबूत टीम है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव आया है। इसी का असर है कि आज भारत की बेंच भी कई देशों की क्रिकेट टीम से मजबूत है। दरअसल, बीसीसीआई ने आईपीएल के माध्यम से भारतीय क्रिकेट को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है।

● मोंटी पनेसर



मेरी प्रेग्नेंसी के शुरुआती महीने बेहद मुश्किल थे। लोग मॉर्निंग सिक्नेस के बारे में बात करते हैं, पर मैं पूरे दिन बीमार रहती थी। उस समय मैं अपने बिस्तर पर होती थी या वॉशरूम में। मैं बहुत मुश्किल से ही कुछ खा पाती थी और इस वजह से मेरा वजन भी बहुत कम हो गया था। प्रेग्नेंसी के दौरान मुझे किसी भी चीज की इंटेंस क्रेविंग नहीं हुई। बस कभी-कभी कुछ स्नैक्स खाने का मन होता, लेकिन मैं मीठा की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। यूं तो मेरे लिए कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे, पर ये सब चैलेंजिंग जरूर रहा।

● बिपाशा बसु



चीन और मुझे लेकर विगत दिनों कुछ अफवाहें उड़ी थीं। मुझे बहुत हैरानी हुई कि कुछ दिन मेरा स्वास्थ्य क्या खराब हुआ सोशल मीडिया ने मुझे नजरबंद करा दिया। मैं सोशल मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि अगले महीने मेरे तीसरे कार्यकाल पर भी मुहर लगेगी।

● शी जिनपिंग

वाक्युद्ध



2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। अपने आपको देश के सबसे मजबूत नेता मानने वाले और उनकी पार्टी दोनों का सफाया हो जाएगा। अगला प्रधानमंत्री विपक्ष का कोई नेता बनेगा। मैं अगले प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। लेकिन यह दावा कर सकता हूँ कि भाजपा सत्ता से बाहर होगी।

● नीतीश कुमार

सुशासन बाबू जिस डाल पर बैठे थे, उसे ही काट डाले। अब वे ऐसी डाल पर बैठे हैं, जहां से उन्हें कभी भी गिराया जा सकता है। उनकी प्रधानमंत्री बनने की मनोकामना तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। अब उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाने वाली है। अच्छा है कि वे समय रहते संन्यास लेकर राजनीति से अलग हो जाएं।

● सुशील मोदी



पटवारी सबसे अधिक घूसखोर

म प्र में सरकार जीरो टॉलरेंस पर जितना जोर दे रही है, प्रदेश में भ्रष्टाचार उतना जोर पकड़ता जा रहा है। अगर यह कहे कि मप्र में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रदेश में बिना रुपए दिए कोई काम नहीं होता।

इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 4 साल में 277 से अधिक घूसखोर अफसर पकड़ाए हैं। इनमें आधे से अधिक पटवारी हैं। इससे यह तथ्य सामने आया है मप्र में पटवारी सबसे अधिक भ्रष्ट हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था में रिश्वतखोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा लेकिन मप्र के सरकारी सिस्टम में रिश्वत को किसी अधिकार की तरह वसूला जाता है। मप्र का सचिवालय हो या जिलों में स्थित कोई छोटा सा दफ्तर हर जगह रिश्वतखोरी चरम पर है। मप्र लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। मगर सिस्टम में सुधार नहीं है। छोटे-छोटे काम के लिए लोगों को चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं। स्थानीय अधिकारी लोगों की शिकायत नहीं सुनते। सरकारी दफ्तर में बाबू लोगों को टरकाते रहते हैं। पैसे देते हैं तो काम होते हैं।

प्रदेश में राजस्व विभाग में पदस्थ 277 संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एएसएलआर, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और राजस्व विभाग में पदस्थ लिपिक, भृत्य करप्शन के गंभीर मामलों में उलझे हैं और लोकायुक्त तथा अन्य आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एजेंसियां इनके विरुद्ध केस दर्ज कर चुकी हैं। सबसे अधिक मामले जबलपुर और रीवा जिले में पदस्थ रहे अफसरों कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज हैं। वहीं झाबुआ में एक भी केस किसी भी कैटेगरी के अफसर कर्मचारी पर दर्ज नहीं है। यह स्थिति प्रदेश में पिछले करीब साढ़े चार साल के अंतराल में लोकायुक्त और अन्य करप्शन जांच करने वाली एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आई है।

सरकार द्वारा राजस्व विभाग के उच्चतम पदों पर कार्य कराने वाले अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर से लेकर बाबू तक की जानकारी लोकायुक्त और अन्य जांच एजेंसियों से मांगी गई थी। इसके बाद यह पता चला है कि रिश्वत के मामले में प्रदेश में सबसे अधिक 154 करप्शन के मामले पटवारियों के विरुद्ध दर्ज हैं। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर स्तर के 11 अधिकारियों और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एएसएलआर कैडर के अफसरों के विरुद्ध 15 मामले पंजीबद्ध होकर विवेचना और चालान की प्रक्रिया में हैं। राजस्व निरीक्षकों के विरुद्ध 33 मामले अलग-अलग जिलों में घूस लेने को लेकर दर्ज हैं। इसके अलावा 64 लिपिक और भृत्य भी घूस लेने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।



भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच धीमी गति से

करप्शन पर एक्शन में मप्र देश में भले ही छठवें नंबर पर हो, लेकिन कोर्ट में पेंडेंसी के साथ ही लोकायुक्त पुलिस और ईओडब्ल्यू की जांच में रफतार दिखाई नहीं देती। कोर्ट में ट्रायल और दोनों संस्थानों में जांच की पेंडेंसी 1300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। हालांकि पिछले तीन साल में प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस और ईओडब्ल्यू ने पिछले तीन सालों में 719 प्रकरण ट्रैप के साथ ही अनुपातहीन सम्पत्ति और अन्य केस दर्ज किए हैं। यह खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस वाले मप्र में भ्रष्ट पर नकेल के मामले में जांच धीमी गति से चल रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में एनसीआरबी की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में बताया कि 584 दर्ज मामलों में जांच चल रही थी। जबकि वर्ष 2021 में 250 केस रजिस्टर्ड किए गए। जबकि वर्ष 2021 शुरू हुआ था तब लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में 529 शिकायतें पेंडिंग में थी। इसके बाद साल खत्म होते-होते लंबित जांचों की संख्या में 55 मामले और जुड़ गए। हालांकि दर्ज प्रकरणों के अनुसार देश में मप्र का नंबर छठवां है। इधर अदालतों में भी भ्रष्टाचारियों के प्रकरणों की पेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। वर्ष 2021 की शुरुआत में 608 प्रकरण ट्रायल में थे, जबकि वर्ष के अंत तक यह संख्या बढ़कर 803 हो गई। जबकि इस वर्ष इस तरह के 195 मामले कोर्ट में भेजे गए। प्रदेश में वर्ष 2021 में ट्रैप के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इसमें 200 प्रकरण बनाए गए। जबकि अनुपातहीन सम्पत्ति के मामले सिर्फ 23 की दर्ज हुए। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य 27 मामले दर्ज किए गए।

विधानसभा में भी यह मामला आया जिसमें भाजपा विधायक यशपाल सिसोदिया ने सभी राजस्व अफसरों, कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की विस्तृत जानकारी शासन से मांगी थी। इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि आदिवासी अंचल के जिलों में ट्रैप के नाम मात्र प्रकरण हैं। झाबुआ जिले में एक भी शिकायत नहीं है तो बड़वानी, अलीराजपुर जैसे जिलों में एक-एक मामले दर्ज हैं। इसी तरह की स्थिति कुछ अन्य आदिवासी जिलों की भी है। विधायक यशपाल सिसोदिया बताते हैं कि अधिकारी तो वही हैं लेकिन इन अंचलों में ऐसे केस कम आने के पीछे मुख्य वजह लोगों में जागरूकता की कमी है। इसी कारण आदिवासी जिलों के रहवासी पैसे देने के बाद काम पर जोर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन जिलों में सर्वाधिक केस टेप हुए हैं, उन जिलों में लोगों की जागरूकता के कारण ऐसा हुआ है। मुफ्त और नाम मात्र शुल्क लेने की सरकार की सेवाओं में रिश्वत लेने की अफसरों की इस कोशिश को टेप के जरिए खत्म करने का काम

यहां तेजी से हुआ है।

राजस्व विभाग में रिश्वतखोरों का आंकलन किया जाए तो यह तथ्य सामने आया है कि द्वितीय श्रेणी के अधिकारी सबसे अधिक दागदार हैं। रिश्वत लेते हुए ट्रैप होने वाले अफसरों में जिनके प्रमुख नाम सामने आए हैं, उसमें संयुक्त कलेक्टर डीआर कुरें, प्रदीप सिंह तोमर, अनिल सपकाले, डिप्टी कलेक्टर दीपक चौहान, मनीष कुमार जैन, आशाराम मेश्राम, आरके वंशकार के नाम शामिल हैं। इसी तरह तहसीलदार नन्हे लाल वर्मा, शारदा, आलोक वर्मा, लक्ष्मण प्रसाद पटेल, आदर्श शर्मा, संजय नागवंशी, नायब तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा, रोहित रघुवंशी, किरण गहलोत, भगवान दास तनखानिया, रविशंकर शुक्ल, गौरव पांडेय, भुवनेश्वर सिंह मरावी भी लोकायुक्त और अन्य मामलों में जांच के घेरे में हैं। हालांकि तहसीलदार शारदा का कहना है कि उन पर जो केस दर्ज था वह लोकायुक्त पुलिस की जांच में साबित नहीं हुआ और उन्हें क्लीनचिट मिल गई है।

● राकेश प्रोवर

6

2023 में भाजपा और कांग्रेस का लक्ष्य साफ है कि हर हाल में सरकार बनाना है। इसके लिए दोनों पार्टियां रणनीति बना रही हैं। फिलहाल दोनों पार्टियों का फोकस 114 विधानसभा सीटों पर है। जहां भाजपा 2018 में हारी हुई 114 सीटों पर फोकस किए हुए है, वहीं कांग्रेस भी अपनी जीती हुई 27 सीटों के साथ ही भाजपा, सपा और बसपा की जीती हुई 87 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी दोनों पार्टियां 114 के फेर में अटकी हुई है।

9



114 सीटों पर होगा घमासान

मिशन 2023 को लेकर इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिशन मोड में काम कर रही हैं। भाजपा की कोर कमेटी और प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के साथ ही आला नेताओं के बीच हुए मंथन के बाद यह साफ हो गया है कि अब पार्टी ने उन 114 सीटों पर विशेष फोकस करने का फैसला किया है, जिन पर पार्टी प्रत्याशियों को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 109 सीटों पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में 114 सीटें गई थीं, हालांकि उपचुनाव के बाद तस्वीर बदल गई और भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीत ली थीं। इसके बाद भी पार्टी ने बोते विधानसभा चुनाव को आधार बनाकर इन विधानसभा क्षेत्रों में हार के कारण, कमियों को तलाशने के लिए प्रभारी बनाए हैं। गत दिनों इन प्रभारियों की बैठक प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी शामिल हुए। बैठक में प्रभारियों से कहा गया कि वे मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित कर कार्यकर्ताओं से संवाद करें और हार के कारण तलाशें ताकि उन्हें दूर किया जा सके। प्रभारियों को बूथवार जानकारी जुटाने को भी कहा गया है। विधानसभा प्रभारी कार्यकर्ताओं के अलावा समान विचारधारा वाले लोगों और बुद्धिजीवियों से भी चर्चा कर अपनी रिपोर्ट संगठन को देंगे। इसके अलावा बूथ विस्तारकों से भी संगठन नेताओं ने चर्चा की और उनसे बूथ स्तर पर किए गए कामों की जानकारी ली।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भले ही अभी सवा साल का समय बाकी है, लेकिन भाजपा

और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों पार्टियों की कोशिश है कि 2023 में उनकी सरकार बने। लेकिन इस बीच विधायकों की खराब परफॉर्मेंस ने भाजपा और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, दोनों पार्टियों के अंदरूनी सर्वे में उनके अधिकांश विधायकों की स्थिति खराब बताई गई है। ऐसे में पार्टियों में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है, वहीं विधायक हार के डर से सुरक्षित सीट तलाशने लगे हैं। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन विधायकों का टेंशन बढ़ गया है जिनका पार्टी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस खराब निकला है। भाजपा और कांग्रेस के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। कांग्रेस में ऐसे 27 और भाजपा में भी ऐसे ही कई विधायकों का टिकट संकट में पड़ गया है। ये विधायक अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। इन्हें डर है कि इस बार कहीं टिकट ही न कट जाए।

भाजपा ने 2023 में होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नए प्रभारियों और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। मप्र के प्रभारी पी. मुरलीधर राव और सह प्रभारी पंकजा मुंडे को बनाए रखा गया है जबकि सांसद रामशंकर कठेरिया को उनके साथ अब शामिल किया गया है। विश्वेश्वर टूडू की जगह रामशंकर कठेरिया को तैनात किया गया है। यानी मप्र में मिशन 2023 और 2024 के लिए मुरलीधर, पंकजा और कठेरिया की तिकड़ी रणनीति बनाकर वीडी और शिव को ताकत देने का काम करेगी। बताया जाता है कि प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साधने के लिए इस तिकड़ी को प्रदेश की कमान सौंपी

संगठन की कसावट में जुटे नाथ

मिशन 2023 पर काम कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अब संगठन में कसावट लाने में जुटे हैं। संगठन में कसावट के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। इसी को देखते हुए सख्त फैसले भी लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एनपी प्रजापति से मंडपम, सेक्टर का प्रभार वापस ले लिया है। अब यह जिम्मेदारी ग्वालियर के कद्दावर नेता अशोक सिंह को दी गई है। दिग्विजय सिंह के करीबी अशोक सिंह पार्टी में कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नाथ का प्रयास रहा है कि मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर तक नए सिरे से संगठन खड़ा किया जाए। सक्रिय नेताओं को वरीयता दी गई। इसी को ध्यान में रख काम शुरू हुआ था। पार्टी ने मंडलम, सेक्टर और बूथ स्तर तक पदाधिकारी बनाए थे, लेकिन निकाय चुनाव में नजर नहीं आए। प्रत्याशियों ने शिकायत भी की थी। आरोप लगा कि कई जगह निष्क्रिय लोगों को पदाधिकारी बना दिया गया। आखिरकार नाथ ने एनपी से मंडलम, सेक्टर के प्रभार की जिम्मेदारी वापस ले ली।

गई है। राव पिछले महीनों से प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसलिए सरकार और संघ में तालमेल और दलितों को साथ लाने के लिए रामशंकर कठेरिया की नियुक्ति बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि मप्र में ओबीसी और दलित वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं। ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने दलित वोटों को साधने के लिए उग्र के बड़े अनुसूचित जाति वर्ग के नेता सांसद रामशंकर कठेरिया को मप्र भाजपा का सहप्रभारी बनाया है। संघ के प्रचारक रहे कठेरिया काफी समय तक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इस नाते उनका मप्र के अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में प्रवास होता रहा है। आगरा से दो बार और इटावा से मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया को भाजपा का बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। उनके द्वारा दलित चेतना पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने मप्र में कठेरिया की नियुक्ति की है। इसे प्रदेश के करीब 80 लाख दलित वोटों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। बता दें कि मप्र में एससी वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। फिलहाल कांग्रेस के पास 35 में से 14 सीटें हैं। वहीं भाजपा के खाते में एससी वर्ग की 21 सीटें हैं। प्रदेश में करीब 16 फीसदी दलित आबादी है। 50 सीटों पर दलित वोटर्स का दबदबा है। गौरतलब है कि मप्र में एससी और एसटी वोटों को सत्ता की चाभी माना जाता रहा है। दोनों वर्गों के लिए प्रदेश की 82 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इनके वोटों की बात की जाए तो इनकी संख्या 40 फीसदी है। ऐसे में जिस दल को इन वर्गों का साथ मिलता है, उसका सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। पिछले 2018 विधानसभा चुनावों में इन दलों ने कांग्रेस का साथ निभाया था। आदिवासी क्षेत्रों की अधिकतर सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि भाजपा ने अगले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मप्र के दलित वर्ग को साधने के लिए कठेरिया को जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल कठेरिया का मप्र की सीमावर्ती उन क्षेत्रों में खासा प्रभाव है, जहां दलित वर्ग चुनावी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से कई विधानसभा क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व है। ऐसे में भाजपा इन्हें क्षेत्र के वोटों को अपने साथ करने के लिए रणनीति के तहत प्रयास कर रही है और उसी प्रयास के लिए कठेरिया को मप्र का सह प्रभारी बनाया गया है।

मप्र कांग्रेस में व्यापक बदलाव किया जा रहा



जल्द मोर्चे पर तैनात होंगे सहप्रभारी

प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने सत्ता और संगठन का पूरा फीडबैक तैयार कर लिया है। वहीं सहप्रभारी पंकजा मुंडे भी पहले से ही जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अब दूसरे सहप्रभारी रामशंकर कठेरिया भी जल्द मोर्चा संभालेंगे। जानकारों की मानें तो रामशंकर कठेरिया जल्द ही भोपाल प्रवास पर आएंगे। इसके पहले वे 17 सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर मौजूद रह सकते हैं। भोपाल में संगठन प्रभारी पी. मुरलीधर राव के साथ पदाधिकारियों से औपचारिक मुलाकात करने के बाद कठेरिया अपना पूरा फोकस मप्र की अनुसूचित जाति बाहुल्य सीटों पर रखेंगे। उनकी इन क्षेत्रों में सभाएं और बैठक शुरू होगी, जिसका सिलसिला विधानसभा चुनाव तक अनवरत जारी रहेगा। कठेरिया ने 13 साल की उम्र में आरएसएस प्रचारक के रूप में काम शुरू किया। वे संघ के विभाग प्रचारक पद पर भी रहे और उन्हें वर्ष 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। वे 2014 से 25 मई 2016 तक मानव संसाधन विभाग के राज्यमंत्री रहे।

है। प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने इसके संकेत दे दिए हैं। सभी 52 जिलों के संगठन प्रभारी बदलने के बाद कमलनाथ अब जिलों के अध्यक्षों को बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार जिन पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है उन्हें बदला जा सकता है। बताया जाता है कि करीब 25 से 30 जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के निशाने पर हैं। इनकी जगह पार्टी परिणाम देने वाले और मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका देगी। पीसीसी के सूत्रों के अनुसार आधे जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों को बदला जा सकता है। इनमें निष्क्रिय जिलाध्यक्षों के साथ ही ऐसे जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्होंने निकाय चुनाव में पार्टी के साथ गड़बड़ी की। ऐसे कांग्रेस नेताओं की छुट्टी तय है। दरअसल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है। मप्र कांग्रेस ने कांग्रेस संगठन को मजबूती देने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में 5 नगर निगमों में कांग्रेस को मिली कामयाबी से कार्यकर्ताओं के हौंसले भी बुलंद हुए हैं। इसके बाद कमलनाथ ने प्रदेश में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली है। वे विधायकों से जिलाध्यक्षों का प्रभार भी वापस ले रहे हैं। उनके स्थान पर पार्टी के फुल टाइम वर्कर को कांग्रेस

जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है।

प्रदेश में कांग्रेस की बूथ से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सर्वममति से सभी ब्लॉक और जिलाध्यक्षों का चयन कर लिया गया है। मप्र कांग्रेस संगठन चुनाव के प्रोविंशियल रिटर्निंग ऑफिसर (पीआरओ) आरसी खूंटिया जिलाध्यक्षों के नामों की सूची जारी करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में आधे से ज्यादा कांग्रेस जिलाध्यक्षों को बदला जाना तय है। जानकारी के मुताबिक ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर ब्लॉक कार्यकारिणी और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिला कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न कराकर रिपोर्ट पीआरओ को सौंप चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर से शुरू होगा। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि पार्टी जल्द से जल्द निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों और जिलाध्यक्षों की सूची जारी करने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। यदि कोई नामांकन दाखिल करता है, तो 487 प्रदेश प्रतिनिधि वोटिंग के जरिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

● कुमार राजेन्द्र

मप्र कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देनी शुरू

कर दी है। इसी कड़ी में उन्होंने जिला प्रभारियों को फ्री हैंड देते हुए कहा है कि जिला प्रभारी जिले के कमलनाथ हैं, जिलों में संगठन संबंधी सभी

निर्णय आपको करना है। जैसे मुझे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, वैसे ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आपको जिलों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। आप वही करें, जो पार्टी के हित में हो।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रदेश प्रभारी से मिले फ्री हैंड के बाद जिला प्रभारियों में उत्साह है। गौरतलब है कि गत दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जिला प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 13 महीने बचे हैं। इस अवधि में चुनाव की तमाम तैयारियों सहित हमें संगठन को मजबूत करना है। जिला प्रभारियों के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है। आप वही करें, जो पार्टी के हित में हो। उन्होंने कहा कि हमारे पर समय कम है और काम ज्यादा। जिला प्रभारी अपने-अपने प्रभार के जिलों का दौरा शुरू करें। वे जिले के सभी पदाधिकारियों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर संगठन में मौजूद हैं। कामकाज में तेजी लाएं और चुनाव की रणनीति पर काम शुरू करें।

बैठक में जिला प्रभारियों ने जिलों की स्थिति बताई। अधिकतर जिला प्रभारियों का कहना था कि जिलों में संगठन की हालत चिंताजनक है। मंडलम, सेक्टर, पोलिंग बूथ के गठन का काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। उन्होंने जिलों में पार्टी नेताओं द्वारा काम में सहयोग नहीं किए जाने की बात भी कही। कुछ जिला प्रभारियों ने जिलों के कार्यकारी अध्यक्षों के कारण संगठन को नुकसान पहुंचने की बात कही। ग्वालियर के जिला प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि हम जिलों में संगठन संबंधी कोई निर्णय करते हैं, तो उस पर अमल की क्या गारंटी है। हम वहां कोई आश्वासन देकर आएँ, तो उस पर क्रियान्वयन होना चाहिए, तभी हमारे होने का कोई मतलब है। बैतूल की जिला प्रभारी सविता दीवान ने कहा कि पार्टी में महिलाओं की भागीदारी में कमी आ रही है, जिससे संगठन बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बैठक में वे अकेली महिला

कांग्रेसियों को फ्री हैंड



किसी के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी

कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के लिए पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि किसी के कांग्रेस छोड़कर जाने से पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी। कोई जाना चाहता है, तो हम उसे रोकेंगे नहीं। जो लोग भाजपा में भविष्य देखकर जाना चाहते हैं, तो जाएं। मैं उन्हें अपनी कार दूंगा कि जाइए। उन्होंने कहा कि मैं किसी की खुशामद में विश्वास नहीं करता। जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, वे पार्टी के प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं। नाथ का कहना है कि भाजपा प्रेशर, पैसे का प्रलोभन दे सकती है। जिसे जाना है, वो जाएगा ही। क्या मैं उसके घर जाऊं उसे रोकूँ? दबाव डालूँ? मैं किसी को दबाकर नहीं रोकना चाहता। मैं क्या कर सकता हूँ? दुख की बात ये है कि मप्र में ऐसा कानून नहीं है, जो झूठे केस बनाने और गवाही देने वालों पर कार्रवाई हो सके।

बैठक में प्रदेश सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी, सीपी मित्तल व कुलदीप इंदौरा भी मौजूद थे। बैठक से पूर्व अग्रवाल ने पार्टी कार्यालय में विभागों, प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर संगठन के कामकाज और चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की।

पिछले 5 महीने से मप्र कांग्रेस के संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। साथ ही प्रदेश प्रतिनिधि भी चुने जा चुके हैं, लेकिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नामों की घोषणा अब तक नहीं की जा सकी है। इससे दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 24 सितंबर से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की बूथ से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सर्वममति से सभी ब्लॉक और जिलाध्यक्षों का चयन कर लिया गया है। ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर ब्लॉक कार्यकारिणी और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिला कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न कराकर रिपोर्ट संगठन चुनाव के प्रोविंशियल रिटर्निंग ऑफिसर (पीआरओ) आरसी खुंटिया को सौंप चुके हैं। जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा खुंटिया को

करना थी, लेकिन एक दिन पूर्व कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधियों की बैठक में प्रस्ताव पारित कर संगठन चुनाव संबंधी सभी अधिकार पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को दे दिए गए हैं, इसलिए जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करेगी।

वहीं प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा- मैं जिंदा कांग्रेस देखना चाहता हूँ। अगर कोई फेसबुक, व्हाट्सएप पर चार लोगों के साथ फोटो भेज देंगे तो ये नहीं चलेगा। जमीन पर काम करना पड़ेगा। सड़क पर आएंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे तब कांग्रेस जिंदा होगी। दिल्ली से आने वाले कार्यक्रम सड़कों पर दिखना चाहिए न कि बंद कमरों में। उन्होंने कहा कि मैं हर जिले में जाकर एक-एक व्यक्ति को पहचानूंगा। मैं खुद देखूंगा कि जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे विधायक और पदाधिकारी क्या काम कर रहे हैं। कौन क्या काम कर रहा है। कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारी मप्र में सरकार नहीं गिरती लेकिन कुछ जयचंदों के कारण सरकार चली गई। कोई बात नहीं राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनौतियां आती रहती हैं। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम मप्र में फिर से सरकार बनाएंगे।

● अरविंद नारद

म प्र में राशन दुकानों पर गरीबों को एक रुपए किलो अनाज तो मिल ही रहा है, लेकिन अब प्रदेश की जनता को खुले बाजार में भी सस्ता गेहूँ का आटा मिलेगा। आटे की कीमत 3 रुपए प्रति किलो होगी, जो मुख्यमंत्री शक्ति

पौष्टिक आहार के रूप में वितरित किया जाएगा। यह आटा पूरी तरह प्रोटीनयुक्त होगा। प्रारंभिक चरण में भोपाल, इंदौर सहित 17 जिलों में आटे की बिक्री को मंजूरी दी गई है। इसके बाद इसका दायरा बढ़ाकर अन्य जिलों में भी किया जाएगा। गौरतलब है कि मप्र सहित पूरे देश में लगातार आटे की कीमत में भारी वृद्धि हो रही है। पैकेटबंद गेहूँ का आटा 150 से 180 रुपए प्रति 5 किलो मिल रहा है। ऐसे में मप्र सरकार द्वारा सस्ते आटे की बिक्री की यह पहल प्रदेश के लाखों लोगों को एक सौगात की तरह है।

कुपोषण खत्म करने के लिए अब प्रदेश में कुपोषण के लिहाज से सेंसेटिव जिलों में फोर्टिफाइड चावल के बाद फोर्टिफाइड आटा भी बांटा जाएगा। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत प्रदेश के धार, झाबुआ, बैतूल सहित 17 जिलों से की जाएगी। इन जिलों में पीडीएस की दुकानों से 5-5 किलो के आटे के पैकेट दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस आटे से महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्याओं से बचाया जा सकेगा। प्रदेश में कुपोषण से निपटने किए जा रहे प्रदेश सरकार के प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल में तारीफ कर चुके हैं।

जानकारी के अनुसार शुरुआत भोपाल, इंदौर सहित 17 जिलों में की जाएगी। प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। डबल फोर्टिफाइड आटा से जहां कुपोषण नियंत्रित होगा, वहीं खाद्यान्न की कालाबाजारी भी रुकेगी। आटा तैयार करने तीन से चार जिलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके बाद टेंडर जारी होंगे। फ्लोर मिलों को गेहूँ और प्रोटीन-विटामिन खाद्य विभाग उपलब्ध कराएगा, जिसे फ्लोर मिल आटे में मिलाकर पांच-पांच किलो का पैकेट तैयार करेंगे। बताया जाता है कि मप्र के स्थापना दिवस नवंबर से गरीबों को आटा उपलब्ध कराने की शुरुआत की जाएगी।

गेहूँ के बदले फ्लोर मिलर सरकार को आटा देंगे। इसके लिए सरकार उन्हें प्रति सौ किलो पर

शक्ति आहार योजना मिलाएगी कुपोषण



10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित

प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में कुपोषण की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है, हालांकि वर्तमान में प्रदेश सरकार कुपोषण मिटाने के लिए जो प्रयास कर रही है उनकी प्रधानमंत्री मोदी भी सराहना कर चुके हैं, लेकिन अभी इस दिशा में और कदम उठाए जाने की जरूरत है। पिछले विधानसभा सत्र में दिए गए सरकार के जवाब के मुताबिक प्रदेश में 0 से 5 साल की उम्र के 65 लाख 2 हजार से ज्यादा बच्चे हैं, इनमें से 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं।

पांच किलो गेहूँ देगी। इसी में वे पिसाई और एयर और वाटर प्रूफ बैग में भरकर सिलाई करेंगे। बैग के बदले सरकार मिलर्स को बारदाना देगी। मिल तक गेहूँ परिवहन के खर्च का भुगतान सरकार करेगी। प्रदेश में करीब 29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का पीडीएस में वितरण होता है। वितरण करने में दो से तीन रुपए प्रति किलो अतिरिक्त आर्थिक भार आने का अनुमान है। आटा तैयार करने वाली निजी कंपनियों को आयरन, विटामिन डी सहित अन्य पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। पोषक तत्व की व्यवस्था सरकार

करेगी।

प्रदेश के कुपोषण प्रभावित जिलों में फोर्टिफाइड चावल बांटना शुरू कर दिया गया है। अब इसके बाद फोर्टिफाइड आटे का वितरण शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी लेने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि फोर्टिफाइड आटा प्रदेश के रीवा, धार, सागर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, छतरपुर, मंदसौर, बैतूल, दमोह, मंडला, हरदा, अनूपपुर, ग्वालियर में बांटा जाएगा। इन जिलों में आटे के 5-5 किलो के पैकेट तैयार कर पीडीएस की दुकानों से बांटे जाएंगे। सरकार ने शुरुआती दौर में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में पीडीएस में आटा वितरण करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया था। इसके बाद मंत्री और विधायकों ने सरकार पर दबाव बनाकर अपने-अपने जिले का नाम जुड़वा लिया। इसके चलते सरकार को आटा वितरण का प्रस्ताव 17 जिलों के लिए बनाना पड़ा। 11 जिले बढ़ाए जाने से यह प्रस्ताव 6 माह के लिए और लेट हो गया है।

फोर्टिफाइड चावल और आटे का मतलब होता है प्रोटीनयुक्त चावल और आटा। इसमें आम आटे और चावल के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन होते हैं। फोर्टिफाइड आटे में आयरन, विटामिन बी-12, फॉलिक एसिड सहित कई और विटामिन मिलाए जाते हैं, जिससे यह आम आटे की तुलना में ज्यादा पोषक हो जाता है। इसके सेवन से बच्चों और महिलाओं में विटामिन और खून की कमी (एनीमिया) जैसी समस्याएं नहीं आतीं। जिससे मां और बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होते। फोर्टिफाइड आटा बनाए जाने की प्रक्रिया में गेहूँ को पीसकर पहले उसका आटा तैयार किया जाता है। जिसके बाद इसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस फोर्टिफाइड आटे के पैकेट तैयार किए जाते हैं। जिन इलाकों से कुपोषण के मामले ज्यादा सामने आए हैं वहां पहले से ही फोर्टिफाइड चावल भी बांटा जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल को मिल में तैयार किया जाता है। इसमें पहले सूखे चावलों को पीसकर आटा बनाया जाता है और फिर पोषक तत्वों को मिलकर फिर इन्हें चावल का रूप दिया जाता है।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

मंत्री बनने की चाह में रोड़ा

म प्र में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेजी से चल रही हैं। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय, सामाजिक, जातिगत फॉर्मूले के अनुसार विस्तार करेगी। ऐसे में कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वहीं कुछ का कद बढ़ाया जा सकता है। वहीं कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में मंत्री पद के दावेदारों ने सक्रियता बढ़ा दी है। वैसे हर विधायक मंत्री बनने की चाह पाले हुए हैं, लेकिन चुनावी वर्ष में मंत्री बनने वालों का हश्र देखकर अधिकांश पसोपेश में हैं। मंत्री बनने की चाह रखने वाले कुछ विधायकों का कहना है कि 14 महीने में सत्ता, संगठन और जनता को संतुष्ट करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं वे यह भी कहते हैं कि पूर्व में जितने विधायक अंतिम फेरबदल में मंत्री बने हैं उनका हश्र भी हमने देखा है। लेकिन हमें मौका मिलेगा तो हम भ्रांति को तोड़कर दिखाएंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश मंत्रिमंडल में अभी चार पद रिक्त हैं। इन चार पदों के लिए करीब एक दर्जन विधायक दावेदार हैं। इनमें कई वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री तक शामिल हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन व सत्ता दोनों ही इन रिक्त पदों को भरने के पक्ष में बताए जाते हैं। अभी शिवराज कैबिनेट में 30 मंत्री हैं, जिनमें से 23 कैबिनेट और 7 राज्यमंत्री हैं। मंत्रिमंडल में फिलहाल क्षेत्रीय संतुलन कम है। विंध्य अंचल से सर्वाधिक विधायक आते हैं, वहां से सबसे कम मंत्री हैं। यही हाल महाकौशल अंचल में बना हुआ है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य, महाकौशल के अलावा मालवा से भी एक-एक विधायक को जगह दी जा सकती है। इसमें भी एक मंत्री अनुसूचित जाति को जाना तय है।

प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच शिवराज के पिछले 3 कार्यकाल के अंतिम बदलाव का आंकलन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि अंतिम विस्तार में मंत्री बनने वालों के लिए चुनाव शुभ नहीं होते हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान जून 2008 में शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार किया था। इस फेरबदल में रामदयाल अहिरवार, निर्मला भूरिया, नारायण प्रसाद कबीरपंथी और जगन्नाथ सिंह को शामिल किया गया था। 2008 के विधानसभा चुनावों में निर्मला अपनी सीट नहीं बचा सकीं। कबीरपंथी को टिकट नहीं मिला और बचे हुए दोनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। हालांकि, रामदयाल को 2013 के चुनाव के ठीक पहले मंत्रिमंडल में स्थान मिला। दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त 2013 में किया



अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार के चौंकाने वाले आंकड़े

प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब महज 14 महीने बचे हैं। सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को उम्मीद है कि शिवराज जल्द ही मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर नए लोगों को मौका अवश्य देंगे। ऐसे में कुछ ने तो अपनी दावेदारी मजबूत करने दिल्ली तक दौड़ लगा दी है। कुछ विधायक प्रदेश संगठन को साधने का भी प्रयास कर रहे हैं, मगर भाजपा के जो विधायक मग्न में होने वाले प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी उम्मीद से हैं, उनके लिए यह जानकारी उत्साहजनक तो नहीं ही होगी। यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले 3 कार्यकाल में किए गए अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर नजर डालें तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। दरअसल, चुनावी वर्ष में या चुनावों से ठीक पहले जिन-जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया, उनमें से अधिकांश अगला विधानसभा चुनाव हार गए तो कुछ को पार्टी ने उम्मीदवार ही नहीं बनाया। जो नेता जीते, उनमें से केवल एक ही को अगली बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकी।

था। इसमें विजय शाह, अंतरसिंह आर्य, दशरथ लोधी और रामदयाल अहिरवार को शामिल किया गया। अहिरवार को 2013 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लोधी दमोह की जबेरा विधानसभा से चुनाव हार गए। अंतर सिंह आर्य चुनाव तो जीत गए मगर मंत्री नहीं बन सके। केवल विजय शाह मंत्रिमंडल में अपनी जगह बचा सके। इससे पहले सितंबर 2012 में अनूप

मिश्रा को शामिल किया गया था। अगले वर्ष वे भी हार गए। तीसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए गए मंत्रियों के भविष्य के साथ यह खेल 2018 के विधानसभा चुनावों में भी देखा गया। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तीसरी पारी में अंतिम विस्तार फरवरी 2018 में किया था। इस दौरान बालकृष्ण पाटीदार, नारायण सिंह कुशवाहा और जालम सिंह पटेल को मंत्री बनाया गया था। इन 3 मंत्रियों में से केवल जालम सिंह ही विधानसभा चुनावों में अपनी सीट बचा सके। बाकी मंत्री चुनाव ही नहीं जीते। यह बात अलग है कि पार्टी की सरकार बनने के बाद भी जालम सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया है। यही वजह है की कई दावेदारों ने तो अब अपने कदम तक पीछे खींचना शुरू कर दिए हैं।

सत्ता और संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब है। इनमें वे मंत्री शामिल हैं, जिनके पास भारी भरकम विभाग हैं। खबर तो यह भी है कि दो से तीन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री चुनाव के पहले रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ऐसे में मंत्री पद से किसे हटाया जाएगा, यह फैसला केंद्रीय हाईकमान को लेना है। फिलहाल मंत्री पद के दावेदारों में अजय विश्‍नोई, संजय पाठक, राजेंद्र शुक्ला, केदार शुक्ला, रमेश मेंदोला, नागेंद्र सिंह, यशपाल सिंह सिसोदिया और सुलोचना रावत के नाम शामिल हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। यह वे मंत्री हैं, जिन्हें अब तक सत्ता व संगठन नॉन परफॉर्मिंग मान रहा है। इसके पीछे ठोस वजह भी है।

● धर्मेद सिंह कथूरिया

42 दोषी फांसी की कतार में



मप्र में जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार तत्पर है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति यह है कि 42 अपराधी ऐसे हैं, जिन्हें फांसी की सजा मिली है, लेकिन अभी तक फांसी नहीं दी जा सकी है।

इन अपराधों में सजा पाने वाले जीवनभर रहेंगे जेल में

आतंकवादी गतिविधियों में दोषी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) एक्ट के तहत दोषी, दुष्कर्मी, जहरीली शराब बेचने वाले, मादक पदार्थों का निर्माण, भंडारण और परिवहन करने वाले, जिनकी सजा के विरुद्ध अपील न्यायालय में लंबित हो, जिसने केंद्र सरकार की संपत्ति का नाश किया हो आदि। इन बंदियों के अलावा आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 70 वर्ष की अधिक आयु के कैदी, जिन्होंने छुट्टी सहित 12 वर्ष की सजा काट ली हो और 60 वर्ष से अधिक आयु की महिला कैदी, जिन्होंने छुट्टी सहित 10 वर्ष की सजा काट ली हो, वह रिहाई के पात्र होंगे।

हो, तब वह बरी हो जाता है। आम जनता न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा- भाजपा के संगठन से जो अलग होता है उस पर कार्रवाई की जाती है। यही कारण है कि न्याय प्रणाली पर आम आदमी सवाल खड़े करता है।

उधर, दुष्कर्मी, आतंकी गतिविधियों, दो हत्या

करने वाले, जहरीली शराब बेचने वाले और विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराध में सजा पाने वाले कैदियों को पूरा जीवन जेल में ही गुजारना पड़ेगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी वे बाहर नहीं आ पाएंगे। जेल विभाग ने इस संबंध में गत दिनों आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में अति गंभीर अपराधों को रोकने के लिए आजीवन कारावास की सजा में कड़े प्रावधान किए गए हैं। अभी आजीवन कारावास को लेकर 2012 की नीति लागू थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव (गृह एवं जेल) डॉ. राजेश राजौरा की अध्यक्षता में इस संबंध में नए सिरे से नीति बनाने के लिए समिति बनाई गई थी। समिति ने उप्र, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों की नीति का अध्ययन कर नई नीति बनाई है।

अभी प्रदेश में सिर्फ दो दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की रिहाई की जाती है। अब अति गंभीर अपराधों (पोक्सो एक्ट, दुष्कर्मी, आतंकी आदि 14 श्रेणी) को छोड़कर बाकी को इन दो दिन के अलावा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भी छुट्टी मिलेगी। अति गंभीर छोड़ अन्य श्रेणी के अपराधों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की भी जेल से रिहाई तीन स्तर पर परीक्षण के बाद की जाएगी। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति बंदी के मामले में पूरा परीक्षण कर सिफारिश महानिदेशक जेल एवं सुधारार्थक सेवाएं को भेजेगी। यहां परीक्षण के बाद रिहाई से 15 दिन पहले राय के साथ शासन को सिफारिश भेजी जाएगी। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर रिहाई की जाएगी।

● जितेंद्र तिवारी

मप्र में बच्चियों से रेप और उनकी हत्या के दरिंदों को अदालत ने तो फांसी की सजा सुनाई लेकिन 25 साल में एक को भी फंदे पर नहीं लटकाया गया। इस दौरान कुल 42 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा-भाजपा की वजह से जनता न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा बोली-कांग्रेस को ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए।

बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार से मप्र सिहर रहा है। हाल ही में भोपाल के बिलाबोंग स्कूल की बस में 3 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना से सब सकते में हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर कड़ी नाराजगी और चिंता जताई थी। उन्होंने कहा- भोपाल में मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समझ नहीं आता कि और कैसे कठिन कदम उठाए जाएं। बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं में अधिकांश रिश्तेदार अपने होते हैं। ऐसे मामलों में सजा तो हो जाती है लेकिन फांसी होने में पता नहीं कितना समय लग जाता है। विधायिका और न्यायपालिका को कठोर सजा जल्द देने पर विचार की जरूरत है।

मप्र में बच्चियों से रेप और हत्या समेत जघन्य अपराधों में 42 दोषियों को अदालत फांसी की सजा सुना चुकी है। ये अलग-अलग जेलों में बंद हैं। लेकिन अब तक फंदे पर किसी को नहीं लटकाया जा सका। मप्र हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील जगदीश गुप्ता ने कहा कि फांसी के मामलों में सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट की अपील हाईकोर्ट में की जाती है। कई बार हाईकोर्ट में केस होने की वजह से सजा लंबित रहती है। केसों की भरमार की वजह से भी ऐसे मामलों की सुनवाई में देरी होती है। हाईकोर्ट में यदि फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। उन्होंने कहा- सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामले लंबी कतार में लगे रहते हैं। व्यवस्था के कारण ही मामले लंबित पड़े रहते हैं। इसके बाद भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई जाती है। वहां पर भी ऐसे मामले पेंडिंग रहते हैं। उन्होंने कहा- हमारा सिस्टम और व्यवस्था को कठोर करने की जरूरत है। सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिस्टम शार्प होगा तभी दोषियों को फांसी मिलेगी।

मप्र में पिछले 25 साल से प्रदेश में किसी दोषी को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सका है। प्रदेश में आखिरी बार फांसी की सजा 1997 में जबलपुर जेल में कामता तिवारी को दी गई थी। वो भी बच्चियों से रेप और हत्या का दोषी था। इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अविनाश बुंदेला ने कहा कि कोई भी दोषी फांसी की सजा या फिर दूसरे अपराध में सजा काट रहा

मप्र में कैडर मैनेजमेंट कुछ इस तरह गड़बड़ा गया है कि कलेक्टरों के लिए सीधी भर्ती और प्रमोटी आईएएस में रार छिड़ गई है। आलम यह है कि वर्तमान समय में करीब 6 दर्जन से अधिक आईएएस (सीधी भर्ती और प्रमोटी) को कलेक्टरों का इंतजार है। इनमें से अधिकांश अपने संपर्कों के माध्यम से कलेक्टर बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। सभावना जताई जा रही है कि इस बार सरकार चुनावी रणनीति के तहत एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करेगी और अपने पसंद के अफसरों को कलेक्टरों से नवाजेगी। जिसमें 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों की लॉटरी लग सकती है।

प्र में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की जमावट करने जा रही है। खासकर मैदान में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पदस्थापना महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि सरकार अपने विश्वसनीय आईएएस अफसरों को जिलों की कमान सौंपेगी। जिनमें प्रमोटी आईएएस अधिकारियों की संख्या बढ़ सकती है। चुनावी साल से पहले होने वाली जमावट में महत्वपूर्ण जिलों की कमान पाने के लिए आईएएस अधिकारियों में जमकर लॉबिंग हो रही है। इस जमावट में सरकार 2014 बैच के एक-दो अफसरों को जिले में पदस्थ कर सकती है। लेकिन 2015, 2016, 2017 और 2018 बैच के जो आईएएस अधिकारी कलेक्टरों करने के लिए पात्र बन गए हैं, उन्हें अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) के नियमानुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में चयनित उम्मीदवार को कलेक्टर बनने के लिए 103 सप्ताह यानी दो साल की ट्रेनिंग अनिवार्य है। यानी एक आईएएस दो साल बाद कलेक्टर बन सकता है, लेकिन मप्र में वर्तमान समय में 2013 बैच के सीधी भर्ती के आईएएस ही कलेक्टर बन पाए हैं। वहीं प्रमोटी आईएएस का अभी नंबर नहीं लगा है। हालांकि इससे पूर्व के भी कई बैच के कई प्रमोटी आईएएस अभी कलेक्टरों की आस लगाए हुए हैं। अगर सीधी भर्ती के आईएएस की बात करें तो डीओपीटी के नियमानुसार, वर्तमान समय में 2014 बैच के 16, 2015 बैच के 12, 2016 बैच के 10 और 2017 बैच के 13, 2018 बैच के 10 अधिकारी कलेक्टर बनने के लिए पात्र हो गए हैं। कलेक्टरों के लिए वर्ष 2013 में एसएस व नान एसएस से आईएएस पद पर प्रमोटी होने वाले अफसरों को भी आने वाले समय का इंतजार है। वर्ष 2014 में आईएएस बने 20 अफसरों में से एक को भी अभी तक कलेक्टरों नहीं मिली है, जबकि इन्हें वरिष्ठता वर्ष 2006 व 2007 की मिली है।

एक आईएएस अगर जीवन में कलेक्टर न बन पाए और आईपीएस एसपी न बन पाए तो



कलेक्टरों के लिए 6 दर्जन लाईन में

वेट एंड वॉच की स्थिति में प्रमोटी आईएएस

सीधी भर्ती से आए 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 बैच के आईएएस अधिकारी कलेक्टरों पाने के लिए जोर आजमाईश कर रहे हैं, वहीं प्रमोटी अफसर अभी सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। सीधी भर्ती वाले अफसरों में शासन ने अब तक वर्ष 2013 बैच अफसरों को कलेक्टरों दे दी है। प्रदेशभर में इन दिनों सीधी भर्ती वाले अफसरों का जिलों में दबदबा है। सरकार ने प्रमोटी अफसरों के बजाय सीधी भर्ती वाले युवा आईएएस अफसरों पर भरोसा जताया है। कलेक्टरों की पदस्थापना में सीधी भर्ती के अफसरों की संख्या ज्यादा है। इसके विपरीत प्रमोटी अफसरों को कलेक्टरों कम मिली है। सूत्रों का कहना है कि प्रमोटी अफसरों को अब चुनाव का समय आने का इंतजार है। सरकार चुनाव के समय प्रमोटी अफसरों को फील्ड में ज्यादा पदस्थापना देती है। इसे देखते हुए प्रमोटी अफसर कुछ माह तक इंतजार करके फिर दो से ढाई साल की कलेक्टरों करने के लिए प्रयास करने पर जोर दे रहे हैं।

मानना चाहिए कि जीवन व्यर्थ गया। यही दोनों पद ऐसे हैं जो एक रिक्की बाबू को भले पूरी नौकरी में मात्र कुछ साल के लिए ही मिलें वह अपने पूरे जीवन की साध पूरी कर लेता है। कलेक्टर या एसपी न बने फिर चाहे चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी अथवा डीजीपी भले बन जाए मगर न तो वह रुतबा प्राप्त हो पाता है न पैसा। आईएएस बनने के बाद जिले की चाह न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। पिछली डीपीसी में आईएएस बने कई अफसरों का कमिश्नर और कलेक्टर बनने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आईएएस बनने के बाद ज्यादातर अफसरों की कलेक्टर बनने की चाह होती है, लेकिन सभी अफसरों का यह सपना पूरा नहीं हुआ है। जहां तक मप्र की बात है तो यहां के 52 जिलों में से 19 जिलों की कमान फिलहाल प्रमोटी अफसरों के पास है, जबकि कई अफसरों को कलेक्टर बनने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया है, वहीं 33 जिलों की कमान सीधी भर्ती वालों के पास है।

2013 बैच की आईएएस अधिकारी रजनी सिंह को झाबुआ कलेक्टर बनाए जाने के साथ ही 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों के कलेक्टर बनने का रास्ता खुल गया है। रजनी सिंह 2013 बैच की सीधी भर्ती की आखिरी आईएएस अधिकारी हैं। अब सरकार 2014 बैच के सीधी भर्ती वाले 16 आईएएस अफसरों को

कलेक्टर बनाएगी। गौरतलब है कि राज्य शासन ने गत दिनों कलेक्टर झाबुआ सोमेश मिश्रा को हटा दिया है। उनके स्थान पर वर्ष 2013 बैच की आईएएस अधिकारी रजनी सिंह को कलेक्टर झाबुआ पदस्थ किया गया है। कलेक्टर के रूप में रजनी सिंह की यह पहली पोस्टिंग है। वे 2013 बैच सीधी भर्ती की आखिरी आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें अब तक जिले की कमान नहीं मिल पाई थी। अब वे भी कलेक्टर बन गई हैं। रजनी के पति राघवेंद्र कुमार सिंह अलीराजपुर कलेक्टर हैं। इसके साथ ही प्रदेश में वर्ष 2013 बैच के सीधी भर्ती के सभी आईएएस अधिकारियों की कलेक्टर के रूप में पदस्थापना की जा चुकी है।

प्रदेश में जहां 2013 बैच के सीधी भर्ती वाले सभी 17 आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर बना दिया गया है, वहीं इस बैच के एक भी प्रमोटी को अभी तक कलेक्टर नहीं बनाया गया है। प्रदेश में वर्ष 2013 बैच के 10 प्रमोटी अधिकारी हैं। इन अफसरों में विकास मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, मीनाक्षी सिंह, कैलाश वानखेड़े, अमर बहादुर सिंह, मनीषा सेंतिया, नीरज कुमार वशिष्ठ, किशोर कान्याल, रूही खान और पवन कुमार जैन शामिल हैं। वहीं वर्ष 2013 बैच के सीधी भर्ती के आईएएस प्रियंक मिश्रा कटनी, अमनबीर सिंह बैस बैतूल, ऋषि गर्ग हरदा, मयंक अग्रवाल नीमच, सोनिया मीना अनूपपुर, सतीश कुमार एस भिंड, फ्रेंक नोबल ए, गुना, एस कृष्ण चैतन्य दमोह, अनूप कुमार सिंह खंडवा, हर्ष दीक्षित राजगढ़, संदीप जीआर छतरपुर, गिरीश कुमार मिश्रा बालाघाट, उमा माहेश्वरी आर अशोकनगर, शिवम वर्मा श्योपुर, राघवेंद्र सिंह अलीराजपुर और रजनी सिंह झाबुआ की कलेक्टर हैं। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अब वर्ष 2014 बैच के सीधी भर्ती के आईएएस अफसरों को जिलों की कमान देने की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2014 बैच के सीधी भर्ती के 16 आईएएस अधिकारी हैं। ये अधिकारी वर्तमान में जिला पंचायत सीईओ, एडीशनल कलेक्टर, सीईओ स्मार्ट सिटी, नगर निगम आयुक्त, नगर निगम उपायुक्त आदि के पदों पर पदस्थ हैं।



इस साल के अंत तक संभावित प्रशासनिक सर्जरी में वर्ष 2008 बैच के कई आईएएस अधिकारी जो एक बार कलेक्टर रह चुके हैं, वे फिर से कलेक्टरी पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। दरअसल, प्रमोटी अफसरों को महत्व देने के कारण ही मप्र में कैडर मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है। हो यह रहा है कि प्रदेश में प्रमोटी आईएएस चार से पांच जिलों में कलेक्टरी करने के बाद मंत्रालय पहुंच रहे हैं। इस कारण कलेक्टर बनने वाले अफसरों की लंबी कतार लग जाती है। ऐसे में सरकार चिन्ह-चिन्ह कर रेवड़ी बांटती है। इस कारण किसी आईएएस को कुछ माह के लिए ही कलेक्टरी मिल पाती है तो कुछ सालों साल राज करते हैं। यह पहला मौका है जब 52 में से केवल 19 जिलों में ही प्रमोटी आईएएस के पास जिलों की कमान है। वहीं सीधी भर्ती के आईएएस अफसरों की संख्या 33 है। हालांकि 10 संभागों में से 6 संभागों में कमिश्नर प्रमोटी आईएएस ही हैं। ऐसे में सीधी भर्ती के आईएएस परेशान हो रहे हैं। लेकिन यह सबके साथ नहीं है। कई प्रमोटी आईएएस तो कलेक्टरी के इंतजार में रिटायर तक हो गए। कुछ चुनिंदा अफसरों को ही राज्य सरकार की कृपा मिल रही है। बाकी तो जिलों में पहुंचे बिना ही रिटायर हो रहे हैं। मप्र कैडर के सीधी भर्ती से आए एक सीनियर

अफसर कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे प्रदेश में काबिल आईएएस अफसरों का टोटा पड़ गया है। प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हालात के चलते काबिल अफसरों को मौका नहीं दिया जा रहा है। आज हालत यह है कि सीधी भर्ती वाले आईएएस की लंबी कतार लगती जा रही है और जिलों के कलेक्टर और आयुक्त पद पर प्रमोटी हुए आईएएस अफसर तैनात हैं। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में नौकरशाही पर सत्ता का दखल लगातार बढ़ा है। इसके चलते कुछ चुनिंदा अफसरों की चांदी हो गई है। मप्र में नौकरशाहों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ सत्ता के साथ भी संतुलन बनाए रखना पड़ता है। जो इस कला में पारंगत नहीं होते, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रमोटी आईएएस अफसर और सीधी भर्ती के आईएएस अफसरों के बीच एक द्वंद्व लगातार चलता रहा है। वैसे भी सीधी भर्ती के अफसरों के मुकाबले प्रमोटी आईएएस अफसरों की साख आम लोगों के बीच कम होती है। मामला सिर्फ आईएएस अफसरों तक ही सीमित नहीं है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति आईपीएस अफसरों को लेकर भी है। लेकिन सरकार की नजर में प्रमोटी सरकार के प्रति अधिक वफादार होते हैं।

● सुनील सिंह

चुनावी साल में प्रमोटी बनेंगे आख के तारे

प्रदेश के शासन और प्रशासन की समझ रखने वाले अफसरों का दावा है कि आज भले ही 29 जिलों में सीधी भर्ती वाले आईएएस कलेक्टर बने हैं, लेकिन चुनावी साल में प्रमोटी ही सरकार की आख के तारे बनेंगे। वर्तमान में सरकार ने कैडर मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए सीधी भर्ती वालों को अधिक संख्या में कलेक्टर बनाया है। चुनावी साल में सरकार प्रमोटी अफसरों पर थोकबंद मेहरबान होगी। दरअसल, सरकार का मानना है कि प्रदेश के बड़े हाकिम (सीधी भर्ती के आईएएस) किसी काम के नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री के टॉप टेन अफसरों में भले ही सीधी भर्ती के आईएएस की भरमार है। अपना दम दिखाने में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रमोटी आईएएस भी पीछे नहीं रहते। यहीं कारण है कि सरकार के चहेते कलेक्टर-कमिश्नरों की प्रदेश में कमी नहीं है। एक ही जिले में कलेक्टर नहीं, बल्कि तीन-चार जिलों में कलेक्टरी कर सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर मुख्यमंत्री के भी खास बन जाते हैं। इसी का नतीजा है कि आज भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, शहडोल और चंबल जैसे महत्वपूर्ण संभागों में कमिश्नरी ही नहीं, बल्कि 21 जिलों में कलेक्टरी भी संभाल रहे हैं। आने वाले समय में यह तस्वीर और बदलेगी तथा फील्ड में सीधी भर्ती के आईएएस की अपेक्षा प्रमोटी आईएएस अफसरों पर ज्यादा दबदाब देखने को मिलेगा।

जि स प्रदेश की सरकार से लेकर विपक्ष तक में अधिकांश नेता छात्र राजनीति से आए हैं, उस प्रदेश में एक-दो साल से ही नहीं बल्कि करीब दो दशक से छात्रसंघ चुनाव ही नहीं कराए जा रहे हैं। बीच में अधिक दबाव बना तो प्रत्यक्ष की जगह एक-दो बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से जरूर चुनाव कराए गए हैं। इसके बाद से सरकार फिर इस मामले में उपेक्षा का रुख अपनाए हुए हैं, लिहाजा अब एक बार फिर भाजपा के छात्र संगठन माने जाने वाले अभाविप व कांग्रेस के एनएसयूआई ने सरकार से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग को लेकर मोर्चा शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस मांग को लेकर यह दोनों ही छात्र संगठन एक साथ खड़े नजर आना शुरू हो गए हैं। उधर, लगभग अधिकांश उच्च शिक्षा के छात्र भी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने के पक्ष में हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि उनके प्रतिनिधि नहीं होने से समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पाता। छात्रों का कहना है कि राजनीतिक कारणों से 2017 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं।

उनका कहना है कि जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रसंघ चुनाव कराने की घोषणा नहीं करता है तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। छात्र नेताओं ने छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत करवाने की मांग की है। 2017 के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। पहले डिपार्टमेंट स्तर पर या क्लास के स्तर पर सीआर यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। फिर चुने हुए सीआर छात्रसंघ की बॉडी को चुनते हैं। इसके विपरीत प्रत्यक्ष प्रक्रिया में सभी छात्र सीधे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय प्रमुख जैसे पदों के लिए वोट करते हैं। प्रदेश में पांच साल पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव हुए थे। वहीं प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए हुए 19 साल हो गए हैं। लंबे समय से छात्र संगठन प्रदेश के कॉलेजों में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।

इस साल भी सत्र आधा हो चुका है, लिहाजा छात्रसंघ चुनाव होना असंभव दिख रहा है। इस सत्र में भी चुनाव नहीं कराने के पीछे सरकार ने कोरोना का हवाला दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि कोरोना का अभी तीसरा दौर चल रहा है। कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस बारे में बात कर कोई फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी आठ यूनिवर्सिटी हैं। 1327 प्राइवेट और सरकारी कॉलेज हैं। छात्रसंघ चुनाव नहीं होने से छात्र निराश नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कॉलेजों में 2017 में अप्रत्यक्ष प्रणाली से छात्रसंघ चुनाव कराए गए थे। उस समय छात्र संगठनों ने राज्य सरकार से चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मांग की थी। तब इसे खारिज कर दिया गया था। प्रत्यक्ष प्रणाली से आखिरी बार 2003 में छात्रसंघ चुनाव



कब होंगे छात्रसंघ चुनाव ?

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली के बीच उलझी राजनीति

दरअसल चर्चा ये है कि हाल ही में एबीवीपी व एनएसयूआई दोनों ने ही राज्य सरकार से छात्रसंघ चुनाव करवाने की मांग की है। दोनों ही चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के अनुसार करवाना चाहते हैं। ये मांग वर्ष 2017 में हुए चुनाव के वक्त भी उठी थी। लेकिन चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए। अब एनएसयूआई इस मांग के लिए सिग्नेचर कैम्पेन चला रही है। तो वहीं एबीवीपी भी पार्टी के नेताओं को मनाने का प्रयास कर रही है। दरअसल वर्ष 2003 तक चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही हुए उसके बाद 19 सालों से इस पर रोक लगा रखी है। बात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रणाली में अंतर की करें तो प्रत्यक्ष में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, सहित अन्य पदों के लिए खड़े हुए उम्मीदवारों को मतदान किया जाता है। प्रत्यक्ष में सभी पदों पर हुए मतदान के बाद टोटल कर ज्यादा मत मिलने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है, साथ ही अलग-अलग पद के लिए संबंधित कॉलेज नामांकन दाखिल करते हैं और चुने हुए पदाधिकारी ही कार्यकारिणी घोषित करते हैं। यहां सबकुछ प्रत्यक्ष प्रणाली के विपरीत होता है। इसी प्रक्रिया से चुनाव 19 सालों से करवाए जा रहे हैं। यहां हर एक क्लास से एक कक्षा प्रतिनिधि चुना जाता है। अब उसके लिए नामांकन करने वाले के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हो, वो मेरिट लिस्ट में हो, उस छात्र को पात्र बनाया जाता है। वो अपना सीआर बनाने के लिए अलग-अलग पदों के लिए जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व अन्य के लिए नामांकन भरकर चुनाव लड़ता है। जिस भी उम्मीदवार को ज्यादा सीआर के वोट मिले वो विजयी कहलाता है।

हुए थे। तब से अब तक लगातार छात्र संगठनों के नेता प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं।

छात्र नेताओं का कहना है कि चुनाव न होने की वजह से छात्रों को कई तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, जिनमें डिपार्टमेंट में बैठने की व्यवस्था नहीं होना, तकनीकी विभाग में प्लेसमेंट का अभाव, स्मार्ट क्लासों की कमी, पानी का उचित इंतजाम नहीं होना, दस्तावेज सेल में डिजिटलाइजेशन की कमी, लाइब्रेरी को 24 घंटे के लिए न खोलना, स्कॉलरशिप प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव शामिल है। उनका कहना है कि इस तरह की समस्याओं के निराकरण में दिक्कतें आना आम बात है। बीयू के अभाविप इकाई के अध्यक्ष प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें चुनाव कराने को लेकर अपनी बात रखी है। अब चुनाव होने चाहिए। लेकिन कोरोना का बहाना लेकर इसे टाला जा रहा है। उनका कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं तो छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं। उधर, एनएसयूआई नेता आशीष शर्मा ने कहा कि युवा नेतृत्व को आगे लाने के लिए चुनाव जरूरी हैं। भाजपा चुनाव न कराकर नए लीडरों की राजनीतिक हत्या करना चाहती है। हम प्रदर्शन करते हैं तो सरकार हम पर लाठीचार्ज करती है। एबीवीपी को चुनाव पर बात करनी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है। दरअसल राजस्थान में छात्रसंघ के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब मप्र में भी छात्रसंघ चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ इस मुद्दे को उठा चुका है और छात्रसंघ चुनाव को भी हुए 5 वर्ष होने आए हैं। गौरतलब है कि साल 2017 में प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए थे, उसके बाद कोविड के कारण चुनाव नहीं हो सके थे।

● सिद्धार्थ पांडे

भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता के बीच उच्चतम न्यायालय मनी लांड्रिंग से संबंधित कानून पीएमएलए के दो प्रविधानों पर फिर से विचार करने के लिए सहमत हो गया है। इसका कारण यह है कि कई दलों ने उसके उस फैसले से असहमति जताई है, जिसमें उसने इस कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मिली शक्तियों को वैध ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ कार्ति चिदंबरम ने जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, उसमें इस पर आपत्ति जताई गई है कि एक तो ईसीआईआर यानी प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट की प्रति नहीं दी जाती और दूसरे, यह जिम्मेदारी आरोपित की ही होती है कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। काले धन पर रोकथाम की अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धता के तहत पीएमएलए कानून 2002 में लाया गया था, जो 2005 में प्रभावी हुआ। इसके बाद उसमें कई संशोधन कर उसे कठोर बनाया गया। इनमें से एक संशोधन तब हुआ था, जब पी चिदंबरम गृहमंत्री थे। अब वह और उनके बेटे इस कानून की गिरफ्त में हैं। इस कानून में कुछ संशोधन मोदी सरकार के कार्यकाल में भी हुए, क्योंकि अवैध तरीके से की गई काली कमाई को सफेद करने और बैंकों से धोखाधड़ी करने के सिलसिले पर लगाम नहीं लग रही थी।

हाल के समय में ईडी और उसके साथ सीबीआई की सक्रियता जिस तरह बढ़ी है, उससे विपक्षी दलों को यह कहने का अवसर मिला है कि इन एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले दिनों सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले और ईडी ने खनन घोटाले को लेकर बिहार, झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में नेताओं और उनके करीबियों के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की। इसी तरह के एक छापे में ईडी को रांची में दो एके-47 राइफलें मिलीं।

इसके पहले शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की। इससे आक्रोशित आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर यह आरोप मढ़ा कि उसके विधायकों को तोड़ने के इरादे से छापेमारी की गई। आम आदमी पार्टी की मानें तो केंद्र सरकार को यह रास नहीं आया कि शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने स्कूली शिक्षा का जो कार्याकल्प किया, उसकी प्रशंसा न्यूयार्क टाइम्स ने की। उसका यह भी आरोप है कि उसके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। विपक्षी दल ऐसे आरोप तब से कुछ ज्यादा ही लगा रहे हैं, जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई। जैसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया, वैसा ही नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर राजद से



आसान नहीं भ्रष्टाचार पर लगाम

रैलियों में जो भीड़ बिना पैसे नहीं आती

विधायक-सांसद का चुनाव लड़ने वाले यही दावा करते हैं कि उन्होंने तय सीमा में धन खर्च किया, पर सच यह है कि वे कहीं अधिक पैसा खर्च करते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि अब रैलियों में जो भीड़ आती है, वह बिना पैसे नहीं आती। तमाम प्रत्याशी मतदाताओं को चोरी-छिपे पैसा बांटते हैं। अगर भ्रष्टाचार नियंत्रित करना है तो यह सब बंद करना होगा। इसके लिए सरकार को एक तो निजीकरण की तरफ बढ़ना होगा और दूसरे, ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और अदालतों से उनका निस्तारण जल्द हो। वर्षों और कई बार दशकों तक जांच और सुनवाई होते रहने का कोई मतलब नहीं। चूंकि भ्रष्टाचार के मामलों का निस्तारण बहुत देर से होता है इसलिए न तो भ्रष्ट तत्वों को कोई सही संदेश जाता है और न ही जनता को।

हाथ मिलाने के बाद लगाया। ऐसे आरोप नए नहीं। ये भारतीय राजनीति का हिस्सा हैं।

दिल्ली के शराब घोटाले, झारखंड के खनन घोटाले और लालू यादव के समय हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले का सच जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रधानमंत्री एक असें से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी भ्रष्टाचार को नासूर बताते हुए यह संकल्प लिया कि वह इसे मिटाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इससे यही स्पष्ट होता है कि उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कस ली है और इसीलिए ईडी और सीबीआई की सक्रियता बढ़ी है। इस सक्रियता के बीच यह तय है कि मोदी

सरकार को ऐसे आरोपों से दो-चार होना पड़ेगा कि विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। पता नहीं विपक्षी दलों के इस आरोप से जनता कितना सहमत होती है, पर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नेताओं और नौकरशाहों का भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है।

मोदी सरकार ने आम आदमी को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए तमाम सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के साथ डीबीटी के जरिए सीधे खाते में पैसे भेजने की जो व्यवस्था की है, उसका कुछ सकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इससे सरकारी भ्रष्टाचार पर पूरी तौर पर लगाम लग गई है। सरकारी ठेकों के आवंटन, टेंडर प्रक्रिया, नौकरियों की भर्तियों से लेकर रोजमर्रा के उन कामों में सुविधा शुल्क या कमीशनखोरी के रूप में भ्रष्टाचार कायम है, जिनमें आम आदमी या खास आदमी का सरकारी कर्मियों से संपर्क होता है। इस मामले में भाजपा शासित अथवा गैर भाजपा शासित राज्यों में आम जनता के अनुभव करीब-करीब एक जैसे हैं।

भ्रष्टाचार देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। भ्रष्टाचार से अर्जित धन सरकारी अफसरों और नेताओं की जेबों में जाता है। इसका अधिकांश हिस्सा चुनावों में खर्च होता है। जब तक चुनावी खर्च में पूर्ण पारदर्शिता नहीं आती, तब तक देश में भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। सरकार ने पार्टियों की फंडिंग के लिए चुनावी बांड के रूप में जो व्यवस्था की है, वह पारदर्शी नहीं कही जा सकती। इसका प्रमाण एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स नामक संस्था के इस आंकलन से मिलता है कि बीते 17 वर्षों में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक का चंदा अज्ञात स्रोतों से मिला। कोई भी प्रत्याशी चुनावी खर्च का सही-सही विवरण नहीं देता।

● बृजेश साहू

वर्तमान में प्रदेश में कोचिंग कारोबार 1330 करोड़ के पार हो चुका है। आश्चर्य यह है कि इनमें 703 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी उन बच्चों की है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बच्चों के लिए निजी स्कूलों की पढ़ाई काफी नहीं है, अगर है तो वे क्यों इस जाल को नहीं समझ रहे। देश में करीब 70 फीसदी बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं। मद्र में भी ऐसा ही हाल है। यहां प्राइवेट स्कूलों में पहली से 12वीं तक 67,18,948 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इनमें से 47,03,263 कोचिंग में भी पढ़ते हैं जो कोचिंग के नाम पर हर साल 703 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इसी तरह सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक 78,98,421 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें करीब 50 फीसदी बच्चे भी कोचिंग का सहारा लेते हैं जो सालाना करीब 627 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इस तरह प्रदेश में कुल 1330 करोड़ का कोचिंग कारोबार हो रहा है। कई जगहों पर तो स्कूल की तरफ से भी कोचिंग की सलाह दी जा रही है।

1330 करोड़ का कारोबार



दर से बढ़ रहा है। कोचिंग के कारोबार में इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी के पीछे स्कूली और उच्च शिक्षा में लगातार गिरावट को प्रमुख कारण माना जा रहा है। शिक्षाविदों का स्पष्ट कहना है कि कॉलेजों में पढ़ाई न होने की वजह से विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में जाने के लिए विवश हैं। बिना मानक के निजी संस्थान खोले जा रहे हैं तो सरकारी तथा अनुदान प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 70 फीसदी पद खाली हैं। जो शिक्षक हैं उनमें भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपना 100 फीसदी देने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में पूरी शिक्षा व्यवस्था पंगु हो गई है और इन परिस्थितियों में परीक्षा प्रारूप में बदलावों से कोचिंग के कारोबार पर अंकुश लगने के बजाय उल्टा बढ़ेगा।

शिक्षाविद् केबी पांडेय मानते हैं कि इस समय स्कूलों और कॉलेजों की जो स्थिति है उसमें विद्यार्थियों के सामने कोचिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। स्थिति यह है कि छात्र-छात्रा स्कूल और कॉलेजों के बजाय कोचिंग को तक्जो दे रहे हैं। यही वजह है कि स्कूलों में उपस्थिति घट रही है। कोचिंग के कारोबार पर अंकुश के लिए ही नहीं, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए भी शिक्षा में व्यापक सुधार की जरूरत है। इस पर चिंतन-मंथन जरूरी है। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं लेकिन अभी सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। प्रोफेसर एसपी गुप्ता का कहना है कि

निजी संस्थानों में गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं है। कई संस्थान सिर्फ डिग्री बांटने के लिए खुले हैं। पढ़ाई नहीं होती। सरकारी और अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों की शिक्षा में लगातार गिरावट आई है। शिक्षकों की कमी से स्थिति बिगड़ गई है। आज का दौर कंटैशन का है। प्रवेश से लेकर नौकरी के लिए परीक्षा देनी होती है। इसलिए छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग में जाना विवशता है। सरकार के साथ शिक्षा से जुड़े अन्य सभी लोगों को इस बारे में सोचना होगा।

कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बार तो इन्हें मान्यता देने पर विचार होने लगा था। प्रोफेसर केबी पांडेय कहते हैं, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई लगातार सवालियों के घेरे में है। इसकी वजह से विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में जाने के बाध्य हुए। ऐसे में एक वर्ग ऐसा सामने आया जो **कोचिंग संस्थानों** को मान्यता देने की वकालत कर रहा था। अच्छे कोचिंग संस्थान को मान्यता देकर उनके विद्यार्थियों को बोर्ड तथा यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। कोचिंग के बढ़ते कारोबार के पीछे भर्ती परीक्षाओं में उनकी संधमारी भी एक कारण है। चिंताजनक बात यह है कि कोचिंग का कारोबार करने वालों में एक वर्ग ऐसा है जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को हाईजैक करने में सक्षम है। कर्मचारी चयन आयोग, बैंक आदि संस्थाओं की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक तथा बड़े स्तर पर नकल के मामलों में कोचिंग संस्थानों की मुख्य भूमिका सामने आई है। वे मोटी रकम के एवज में नौकरी की गारंटी देते हैं। इससे भी इनमें काफी भीड़ है।

● श्याम सिंह सिकरवार

हमारी शिक्षा प्रणाली की गिरती गुणवत्ता के कारण कोचिंगों का बढ़ता दायरा

हर मां-बाप अपने बच्चे को आज के समय में स्कूल के साथ-साथ अलग से कोचिंग के लिए भी भेजते हैं, ताकि उसकी शिक्षा में कोई कमी ना रह जाए, आजकल यह धारणा बन गई है कि कोचिंग भेजना ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। परंतु क्या बच्चों के लिए अलग से कोचिंग लेना आवश्यक है? वे मां-बाप अपने बच्चों को कोचिंग कैसे दिलवाएं, जो उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भी बड़ी मुश्किल से ही भेज पाते हैं? क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या कोचिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, जिनके मां-बाप उन कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस भर सकते हैं? सरकार इस समस्या को लेकर कितनी गंभीर है और वो इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? असल में कोचिंग वाली मानसिकता वहां से शुरू होती है, जहां से विद्यार्थी के मन में प्रतियोगिता में पिछड़ जाने का डर शरू होता है। स्कूलों में जब शिक्षक परीक्षा में पास होने जितना ही पढ़ाते हैं, तब ये प्राइवेट कोचिंग वाले इश्तेहारों (विज्ञापनों) के जरिए बच्चों को कोचिंग की माया का ज्ञान देते हैं।

अंधेरे में आंगनबाड़ी केंद्र

सू बे में करीब 30 हजार आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं, जो इन दिनों में अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसकी वजह है कई केंद्रों को बिजली बिल जमा करने के लिए बजट का नहीं दिया जाना। इसकी वजह से बिजली विभाग ने इन केंद्रों की बिजली काट दी है। बिजली के अभाव में बच्चों को न केवल बगैर पंखों के बल्कि कई जगहों पर तो कम रोशनी में भी बैठना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि यह स्थिति हाल ही में बनी है, बल्कि कई माह से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुल रही हैं।

शहडोल जिले के जुड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र की बिजली अप्रैल 2022 से कटी हुई है। यही नहीं इस केंद्र के बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए बाणसागर के अतिरिक्त तहसीलदार (वसूली) विद्युत न्यायालय ने वसूली का नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी तरह अनूपपुर जिले की बहेराबंध आंगनवाड़ी केंद्र की बिजली बिल की बकाया राशि वसूली के लिए हाल ही में कार्यकर्ता को लोक अदालत में आने का समन जारी कर दिया गया है। इस केंद्र के बिजली बिल की राशि 7,800 रुपए है। इस तरह की समस्या लगभग प्रदेश के हर जिले में बनी हुई है।

जहां पर कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर बिजली कनेक्शन नहीं काटने दिया है वहां पर भी अब बिजली कनेक्शन कटने का खतरा बन गया है। इसी दौरान बिजली कंपनियों ने कनेक्शन की राशि भी बढ़ा दी है। करीब 30 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली नहीं है। इनमें से 20 हजार केंद्रों में **जल जीवन मिशन के माध्यम से** बिजली कनेक्शन कराने की सहमति दी गई है, जबकि महिला बाल विकास विभाग को 10 हजार केंद्रों में कनेक्शन कराना है।

खास बात तो यह है कि इन केंद्रों में बिजली के लिए सरकार द्वारा विभाग को बजट भी आवंटित किया जा चुका है, लेकिन विभाग बीते छह माह से इस मद की राशि को जारी ही नहीं कर रहा है। इसकी वजह से जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली के कनेक्शन हो चुके थे, उनमें बिजली बिल भुगतान की समस्या बनी हुई है। बिलों का भुगतान नहीं होने की वजह से कई जिलों में बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटने के नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। यह हालात तब बने हुए जबकि करीब तीन माह पहले मुख्यमंत्री हर आंगनवाड़ी केंद्र में जल्द बिजली कनेक्शन कराने के निर्देश दे चुके हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित 97 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों में पहले बिजली कनेक्शन का कोई प्रावधान ही नहीं था। इसी साल इसके लिए प्रावधान के लिए पहल शुरू की गई। इसके तहत जानकारी जुटाई गई तो



अफसरों की आंगनबाड़ी भी बदहाल

प्रदेश में माननीयों और अफसरों द्वारा गोद ली गई आंगनबाड़ियों का भी बुरा हाल है। 6 नंबर स्टॉप, शिवाजी नगर में अकुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास स्थित आंगनबाड़ी को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गोद लिया है। मगर कलेक्टर ने पिछले छह महीने में आंगनबाड़ी में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ही नहीं लिया। यदि जायजा लेते तो शायद कलेक्टर को पता चलता कि आंगनबाड़ी की क्या हालत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यशोदा तिवारी ने बताया कि बच्चों की लंबाई मापने वाला उपकरण तो टूटा पड़ा ही हुआ है। साथ ही पोषण आहार में खाने और नाश्ते की गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर की है। ना फल आते हैं ना ही दूध। खाने की क्वालिटी अच्छी ना होने से बच्चे उसे खाते ही नहीं हैं। उसके कारण बच्चों की उपस्थिति भी कम है। एक आंगनबाड़ी केंद्र 767 में पीने के पानी की समस्या नजर आई। आंगनबाड़ी में पानी का कनेक्शन ही नहीं है। पानी बेहद दूर यादव मोहल्ले से लाना पड़ता है। इस केंद्र को सहारा साक्षरता नाम के एनजीओ के शिवराज कुशवाहा ने गोद लिया हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जब पूछा गया कि क्या गोद लेने के बाद आंगनबाड़ी को कोई भी फायदा हुआ तो उनका जवाब था- नहीं। आंगनबाड़ी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है।

पता चला कि सूबे की करीब पचास हजार उन केंद्रों में ही बिजली व्यवस्था है जो किराए के भवनों में या फिर ग्राम पंचायत, स्कूल भवन या अन्य सरकारी भवनों में संचालित हैं। शेष करीब 50 हजार केंद्रों में बिजली का अभाव है। इसके बाद इसके लिए योजना तैयार की गई। जिसके लिए जल जीवन मिशन के तहत इस साल पहले 31,000 केंद्रों में बिजली कनेक्शन कराने की सहमति दी गई, लेकिन अब इसे कम कर 20 हजार केंद्र तक सीमित कर दिया गया। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले साल 10 हजार केंद्रों में बिजली कनेक्शन के लिए बजट मांगा है। इसके लिए विभाग ने इस वित्तीय बजट में पहले एक कनेक्शन के 3 हजार रुपए के मान से बजट मांगा। इस बजट से 9 हजार केंद्रों में कनेक्शन होना था, लेकिन बिजली कंपनियों ने उन केंद्रों में कनेक्शन की दर अधिक कर दी है। जो बिजली खंभों से काफी दूर हैं। इसको लेकर वित्त विभाग से और बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जो बीते छह

माह से अटका हुआ है। अब विभाग को पहले अनुपूरक अनुमान में राशि मिलने का इंतजार है।

यही नहीं प्रदेश की आंगनबाड़ियों में वजन और ऊंचाई मापने वाले ढाई लाख में से डेढ़ लाख उपकरण खराब पड़े हैं। और आखिर क्यों कुपोषण के मामले में मप्र पूरे देश में नंबर एक पर है? पर उसकी एक मुख्य वजह यह भी मानी जा सकती है कि सरकार आंगनबाड़ियों में जनभागीदारी यानी जनता की सहभागिता चाहती है। जिसके लिए सरकार ने कुछ वक्त पहले एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी योजना को बाकायदा दोबारा शुरू किया। इसमें तय किया गया था कि जिले के प्रमुख लोग जैसे कलेक्टर, विधायक, सांसद या मंत्री अपने-अपने क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी को गोद लेंगे और आंगनबाड़ी का कायाकल्प कर आम लोगों के सामने नजीर पेश करेंगे। लेकिन सरकारी अफसरों और नेताओं में ही इस योजना को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आता।

● राजेश बोरकर

देश के भाल पर मप्र ने एक और इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों ने कुलाचें भरना शुरू कर दिया है। चीतों को छोड़े जाने की तस्वीर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में

छाई हुई है। इसके साथ ही

प्रदेश के पिछड़े और

आदिवासी बाहुल्य

जिला श्योपुर में

पर्यटन की

संभावनाएं बढ़

गई हैं। यानी अब

देश ही नहीं

बल्कि विदेश के

लोग भी श्योपुर

आएंगे। पर्यटन की

संभावनाओं को देखते

हुए श्योपुर की तस्वीर

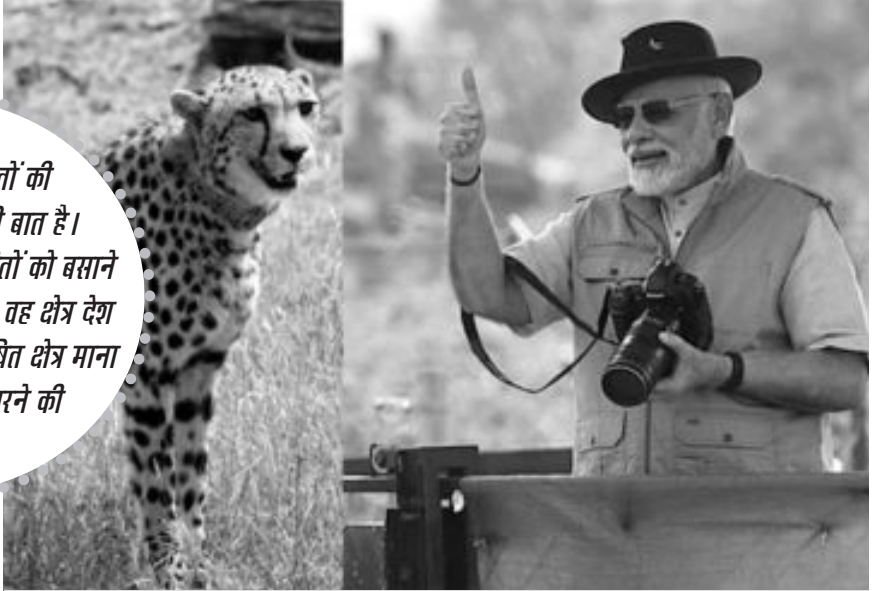
बदलने के लिए सरकार के साथ

ही कारपोरेट घराने भी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन इनके ये सारे प्रयास तभी रंग लाएंगे, जब श्योपुर की तकदीर भी बदलेगी।

गौरतलब है कि अभी तक श्योपुर की पहचान प्रदेश के सबसे पिछड़े, गरीब और कुपोषित जिले के रूप में होती रही है। आदिवासी बाहुल्य जिले में चारों तरफ गरीबी के चिन्ह देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर देशी और विदेशी पर्यटक चीतों की कुलाचें देखने श्योपुर आएंगे तो सबसे अधिक उन्हें इस जिले की बदहाली, गरीबी और कुपोषण देखने को मिलेगा। यानी अभी तक मप्र में ही अपनी गरीबी और बदहाली के लिए बदनाम इस जिले की बात देश और विदेशों में होने लगेगी। कूनो पालपुर आने वाले पर्यटक लौटते समय चीतों की बात करें या न करें श्योपुर की बदहाली की गाथा सबसे पहले लोगों को सुनाएंगे। इसलिए सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए कि जिले की पर्यटन तस्वीर बदलने के साथ ही यहां के लोगों की तकदीर भी बदले।

रातोंरात चंबल का आदिवासी बाहुल्य जिला श्योपुर विश्व पटल पर चीतों की नई बसाहट के रूप में पहचान बना चुका है। 70 साल बाद जिले के कूनो नेशनल पार्क में अप्रीकी चीते कुलाचें भरने लगे हैं। पूरे देश में जितनी खुशी इन अप्रीकन चीतों को लेकर है उससे ज्यादा खुशी श्योपुर जिले के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से हुई है। इस जिले में इतिहास में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा। इससे लोगों को उम्मीद जगी है कि कुपोषण के लिए बदनाम श्योपुर की किस्मत बदलने की कोशिश की जाएगी। श्योपुर जिले की पहचान कुपोषण से होती है क्योंकि मप्र में सबसे ज्यादा कुपोषण के मामले श्योपुर जिले से ही आते हैं। इस जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है।

तस्वीर नहीं तकदीर भी बदलो सरकार



देश में 70 साल बाद चीतों की वापसी वाकई गौरव की बात है। लेकिन जिस क्षेत्र में इन चीतों को बसाने की कवायद की जा रही है, वह क्षेत्र देश का सबसे पिछड़े और कुपोषित क्षेत्र माना जाता है। उसे भी सुधारने की जरूरत है।

श्योपुर की गरीबी न बन जाए जगहंसायी

बताया गया है कि चीता प्रोजेक्ट के बाद अब होटल कारोबार की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। जिसके तहत ताज, टाटा, ओबेरॉय जैसे बड़े समूह भी श्योपुर में होटल और रिसॉर्ट बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। पर्यटन बढ़ने की दिशा में सेसईपुरा और कूनो के आसपास के इलाके में तो होटल व रिसॉर्ट बनेंगे ही, वहीं कराहल, श्योपुर, सामरसा आदि क्षेत्रों में भी होटल रिसॉर्ट बनेंगे। चीता प्रोजेक्ट आने के बाद जहां निजी होटल कारोबारी कूनो और उसके आसपास के इलाकों के साथ ही जिला मुख्यालय पर होटल व रिसॉर्ट बनाने की कवायद में जुट गए हैं, वहीं पर्यटन विकास निगम और पर्यटन बोर्ड भी कूनो के आसपास एक बड़ा रिसॉर्ट बनाने की संभावना तलाश रहा है। बताया गया है कि इसके लिए जमीन देखी जा रही है। इन तमाम संभावनाओं के बीच यह आशंका जताई जा रही है कि श्योपुर की गरीबी मप्र की जगहंसायी का कारण न बन जाए। इसकी वजह यह है कि जिले में सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार योजनाएं तो बना देती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए अब जब श्योपुर चीतों के कारण विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है तो केंद्र और राज्य सरकार को चाहिए कि वे इस जिले के लोगों की तकदीर बदलने के लिए ठोस नीति बनाएं।

लगातार कुपोषित बच्चों की मौत के मामले पूरे देशभर में सुर्खियों में रहते हैं। प्रशासन और सरकार लगातार यहां कुपोषण को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है।

कूनो नेशनल पार्क में चीते आने से सबसे ज्यादा उम्मीद रोजगार पर टिकी हुई है। इस श्योपुर जिले में कोई भी बड़ा उद्योग और रोजगार नहीं है। इस जिले के ज्यादातर लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य या अन्य जिलों में भटकते रहते हैं। माना जा रहा है कि अब होटल इंडस्ट्री का भी नया हब बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में चीता आने के बाद अब होटल कारोबार पनपना तय है। यही वजह है कि अब देश के बड़े होटल समूह भी यहां न केवल संभावनाएं तलाश रहे हैं, बल्कि जमीन भी देखना

शुरू कर दिया है। यही नहीं कुछ जगह होटल निर्माण तो शुरू भी हो गए हैं। वर्ष 1980 में स्थापित हुए कूनो वन्यप्राणी अभयारण्य को वर्ष 2018 में कूनो नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया। हालांकि यहां 27 सालों तक एशियाई सिंहों की राह देखी गई, लेकिन अब यहां चीता बसाए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, लिहाजा पर्यटकों को ठहरने के लिए सर्वसुविधायुक्त होटल और रिसॉर्ट की आवश्यकता होगी। यही वजह है कि होटल कारोबार का नया हब श्योपुर जिले में बनना तय है। इसी के चलते सेसईपुरा और कूनो के आसपास जमीनों के दामों में इजाफा हो गया है, वहीं श्योपुर जिला मुख्यालय पर भी जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं।

● कुमार विनोद

म प्र में सरकार उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों के लिए उद्यानिकी फसलों की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है।

दरअसल उद्यानिकी विभाग के अधिकारी न तो किसानों को सब्सिडी दे पा रहे हैं और न ही फंड खर्च कर पा रहे हैं। यह खुलासा कृषि विकास समिति ने अपनी रिपोर्ट 2021-22 में किया है। यह रिपोर्ट हाल ही में विधानसभा पटल पर रखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार मप्र में उद्यानिकी फसलों जैसे केला, आम, आंवला, संतरा, अनार, मसालों में धनिया, लहसुन, मिर्च और फूलों की खेती के लिए किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का 100 फीसदी लाभ नहीं मिल रहा है। वैसे केंद्र और राज्य की दो दर्जन से ज्यादा योजनाएं संचालित हैं, लेकिन किसानों को अधिकांश योजनाओं की जानकारी ही नहीं है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में आम, संतरा, अमरूद, आंवला, पपीता, केला, अनार, धनिया, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन सहित फूलों की खेती जैसे कट फलोंवर, बल्बस तथा लूज फलोंवर का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। इन फसलों की खेती करने वाले करीब 5000 किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी देने का टारगेट तय किया गया था, लेकिन फायदा 400 को भी नहीं हुआ है। कृषि विकास समिति ने अफसरों की लापरवाही को परिलक्षित करते हुए कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। हितग्राहियों के लिए योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं दिए जाने के कारण उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण है?, क्या कर्मचारियों, अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है? इसके जवाब में कहा गया है कि विभाग में पोर्टल पर कृषक आवेदन की पारदर्शी प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इसमें शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक हित को प्रभावित करने की कोई भूमिका नहीं रहती। समिति का सवाल था कि हितग्राहियों के लिए प्रचार-प्रसार के लिए कौन-कौन से माध्यमों का उपयोग किया जाता है। प्रदेश में तीन साल में विभिन्न योजनाओं पर कितना बजट जारी किया और कितना खर्च किया गया है? जवाब में कहा गया कि विभाग ने विभिन्न योजनाओं के टारगेट और खर्च राशि का हिसाब समिति को बताया। लेकिन जितनी भी योजनाओं की डिटेल् दी गई, उनमें शत-प्रतिशत खर्च और किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रतिशत 40 से 50 प्रतिशत ही था। समिति का सवाल था कि क्या किसानों को पंचायत, ब्लॉक, तहसील स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने किसी विशेष अमले की नियुक्ति की गई है। क्या इन कार्यों की उच्च स्तर पर



किसानों को नहीं मिली सब्सिडी

फंड का उपयोग की नहीं हो पाया

एक तरफ किसान सब्सिडी की आस लगाए बैठे हैं वहीं दूसरी तरफ उद्यानिकी विभाग के भी आंकड़े बताते हैं कि मेन में एकीकृत बागवानी विकास को लेकर केंद्र से मिलने वाले फंड का उपयोग उद्यानिकी विभाग नहीं कर पा रहा है। इसके तहत प्रदेश में आम, संतरा, अमरूद, आंवला, पपीता, केला, अनार, धनिया, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन सहित पुष्प की खेती जैसे कट फलोंवर, बल्बस तथा लूज फलोंवर का उत्पादन दोगुना किया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार से 60 फीसदी और राज्य से 40 फीसदी अंश राशि खर्च की जाती है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बीते 5 सालों में 337 करोड़ रुपए का आवंटन मप्र को मिला था, लेकिन इसमें से उद्यानिकी विभाग सिर्फ 169 करोड़ रुपए ही खर्च कर सका है। यदि टारगेट के हिसाब से किसानों को लाभ दिया जाता तो हर साल 4 से 5 हजार किसानों को फायदा मिलता।

समीक्षा की जाती है? जवाब में कहा गया कि राज्य स्तर पर प्रत्येक गुरुवार को वीसी के माध्यम से समीक्षा की जाती है। पिछले तीन साल में प्रचार-प्रसार पर करीब 1 करोड़ की राशि खर्च की गई है। 1 लाख 20 हजार हितग्राहियों को सब्सिडी का लाभ दिया गया।

एकीकृत बागवानी विकास के तहत योजना के लिए 40 जिलों में विशेष फोकस किया जाना था। विभाग के अनुसार भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, खंडवा, मंडला, डिंडोरी, बुरहानपुर, बड़वानी, रीवा, सतना, हरदा, राजगढ़, गुना, नीमच, ग्वालियर, छतरपुर, सीहोर, विदिशा,

सीधी, अलीराजपुर, सिंगरौली, अशोकनगर, रायसेन, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया तथा आगर-मालवा में किसानों को प्रशिक्षण देकर इन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाना था। लेकिन न तो किसानों को प्रशिक्षण मिला और न ही उन्हें योजना के बारे में जानकारी है। किसानों का कहना है कि उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास के तहत फसलों का उत्पादन बढ़ाने और सब्सिडी दिए जाने की हमें कोई जानकारी नहीं है। कृषि विकास समिति के सभापति बहादुरसिंह चौहान का कहना है कि समिति चाहती है कि इसका लाभ किसानों को देने ठोस रणनीति बनाई जाए। उद्यानिकी फसलों की नवीन तकनीक से कृषकों को समय-समय पर अवगत कराया जाए। फल एवं सब्जी प्रशिक्षण केंद्रों में वृद्धि की जाए।

सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 5 साल पहले निर्धारित किया था, लेकिन आज तक न तो फसलों का उत्पादन बढ़ा और न ही आय बढ़ी। इसके पीछे उद्यानिकी विभाग के अफसरों की लापरवाही सबसे बड़ी वजह बनी है। विदिशा निवासी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने 11 एकड़ में मसाला उत्पादन से जुड़ी फसलें लगाई थीं। सरकारी सहायता यानि सब्सिडी लेने के लिए आवेदन भी किया, लेकिन मेरी फसल का उत्पादन बढ़ा न आय में दोगुनी वृद्धि हुई। सरकार से सब्सिडी भी नहीं मिली। किसान अनूप सिंह ने बताया कि उन्हें उद्यानिकी से संबंधित किसी योजना की जानकारी ही नहीं है। यह हाल अकेले किसान विनोद और अनूप के साथ नहीं है बल्कि प्रदेश के हजारों किसान 5 साल में अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाए और न ही आय में बढ़ोत्तरी हुई, जबकि बढ़ती महंगाई से उनकी कमर और टूट रही है।

● लोकेंद्र शर्मा



संघ का कौम जोड़ी अभियान

मुस्लिम कट्टरपंथियों से लड़ने के लिए आउटरीच का हिस्सा है मोहन भागवत का मस्जिद दौरा

भागवत का उमर इलियासी से मुलाकात करना हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयासों के लिए विशेष

भारत तेजी से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बनने के बाद से भारत के प्रति विदेशियों का नजरिया बदल रहा है। ऐसे में देश के अंदर कई बदलाव की जरूरत है। इनमें सबसे पहला है हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत करना। दरअसल, भारत में पिछले कुछ सालों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। इससे विदेशों में भारत की छवि धूमिल हो रही है। इसको देखते हुए संघ ने कौम जोड़ी अभियान शुरू किया है, जिसका मुसलमानों ने भी समर्थन किया है।

● राजेंद्र आगल

भारत हमेशा से ही शांति, सद्भाव, प्रेम और धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता रहा है। यही कारण है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ ही अन्य संप्रदाय के लोग एकता के बंधन में बंधे हुए हैं। हालांकि कभी-कभार हिंदू और

मुस्लिम संप्रदाय के बीच टकराव होता रहता है। पिछले कुछ सालों के दौरान इन दोनों समुदायों के बीच एक-दूसरे को लेकर शंका का माहौल निर्मित हुआ है। इसका फायदा उठाने के लिए विश्व की तमाम आतंकी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। इस कारण देश में कई अप्रिय घटनाएं भी घटित हुई हैं। यह अप्रियता देश के लिए

घातक न हो जाए इसको देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कौम जोड़ी अभियान शुरू किया है। माना जा रहा है कि इस अभियान के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की रणनीति है। इस अभियान को हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम समाज ने भी हाथों-हाथ लिया है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत हमेशा से ही हिंदू और मुस्लिम को एक मानते हैं। वे कई मंचों से कह चुके हैं कि दोनों का डीएनए एक है। अब इसी दिशा में दोनों समुदायों को एकता के धागे में पिरोने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले महीने 22 अगस्त को सरसंघचालक मोहन भागवत ने पांच मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। उसके ठीक एक महीने बाद 22 सितंबर को वह दिल्ली की एक मस्जिद में गए और वहां मजार पर फूल चढ़ाए। यह मस्जिद दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है और इस मस्जिद में मौलाना जमील अहमद इलियासी की मजार है, जिन्हें वह श्रद्धांजलि देने गए थे। यह जानना जरूरी है कि मौलाना जमील इलियासी कौन थे, जिनकी मजार पर फूल चढ़ाना सरसंघचालक ने इतना महत्वपूर्ण माना। मौलाना इलियासी खुले विचारों के मुस्लिम स्कॉलर थे। उन्होंने दुनियाभर के अनेक धर्मों के बुद्धिजीवियों के साथ मेल मुलाकात करके धार्मिक सौहार्द के लिए काम किया था। यहां तक कि वह यहूदी धर्म गुरुओं से मिलने इजराइल भी गए थे।

भारत में उनकी भूमिका कौमी एकता की थी। कौमी एकता और हिंदू-मुस्लिम सौहार्द के लिए उनकी ईंदिरा गांधी से लेकर अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से मुलाकातें होती रही हैं, जिनमें राजीव गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। यहां तक कि कट्टर हिंदूवादी माने जाने वाले मुरली मनोहर जोशी जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो मुस्लिम शिक्षा में सुधारों के लिए उनके साथ कई मुलाकातें हुई थीं। मौलाना जमील अहमद के प्रयासों से वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था। भारत में उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यह रही कि उन्होंने मस्जिदों के इमामों का अखिल भारतीय संगठन खड़ा किया जिसका अध्यक्ष अब उनका बेटा इमाम उमर इलियासी है। इस संगठन का देशभर की सभी मस्जिदों के इमामों के साथ नेटवर्क है। इसलिए मोहन भागवत का उनकी मजार पर फूल चढ़ाना और संगठन के मौजूदा अध्यक्ष उमर इलियासी से मुलाकात करना हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयासों के लिए विशेष मायने रखता है।

उमर इलियासी से मुलाकात करने सरसंघचालक अकेले नहीं गए थे। संघ के तीन बड़े नेता कृष्ण गोपाल, इंद्रेश कुमार और रामलाल भी उनके साथ थे। तीनों संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी हैं। इंद्रेश कुमार तो कई सालों से मुस्लिमों के बीच ही काम कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया था, जिसकी ब्रांच सारे देश में खुल चुकी है। इस संगठन में हजारों राष्ट्रवादी मुस्लिम शामिल हुए हैं। संघ नेतृत्व को मुस्लिमों



समझना होगा इस अंतर को

भागवत इमामों के पास कोई धर्म थोपने की नीयत से नहीं गए थे। वह धर्म और पंथ से बहुत ऊपर इंसान के इंसान से साम्य की बात बताने गए थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत भूमि के मुस्लिमों की पांच-सात पीढ़ियों के पहले की कहानी उनके हिंदू होने की ही है। यदि उनके कथन से डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी संतुष्ट न हुए होते तो उनकी प्रतिक्रिया राष्ट्रऋषि अथवा राष्ट्रपिता की बजाय बेहद औपचारिक किस्म की आती। इस निमंत्रण का दिया जाना जितना सुखद है, उतना ही सुखद है, इसे स्वीकारा जाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत की अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी से हुई भेंट देश की सामाजिक समरसता को बढ़ाने की दिशा में अहम घटनाक्रम है। इलियासी के आमंत्रण पर भागवत उनसे मिलने गए। अब राजनीतिक नजरिए से इसे जिसे जैसा देखना हो, देख सकता है। लेकिन दोनों के बीच बंद कमरे में करीब एक घंटे की लंबी चर्चा चली। यह तो अपने आप में बड़ी बात थी ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह रही कि चर्चा के बाद इमाम संगठन के प्रमुख ने मीडिया को बताया कि भागवत ने उनसे कहा है कि हिंदू और मुस्लिमों या अन्य धर्मों की उपासना पद्धति अलग हो सकती है, किंतु उनका डीएनए एक ही है। इमाम इस बात से इतना प्रभावित दिखे कि उन्होंने भागवत को राष्ट्रऋषि तथा राष्ट्रपिता जैसी संज्ञा भी दे दी। स्पष्ट है कि भागवत ने इमाम डॉ. इलियासी से बंद कमरे में भी वही कहा, जो संघ खुले रूप से हमेशा से कहता आ रहा है। भागवत की इस वैचारिक दृढ़ता और इमाम की इस उदारमना प्रतिक्रिया, दोनों का ही स्वागत किया जाना चाहिए। जिन लोगों को इस चर्चा से हैरत है, उनके लिए बात इतने में खतम की जा सकती है कि संघ को ठीक से समझना उनके लिए कठिन है।

के नजदीक लाने में इंद्रेश कुमार अहम भूमिका निभा रहे हैं।

यहां संघ के इतिहास में सबसे बड़ी घटना यह हुई है कि किसी मुस्लिम की मजार पर सरसंघचालक ने फूल चढ़ाए हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ पर चादर भेजने को भी संघ में अच्छा नहीं माना जाता था। आपको याद होगा कि 2006 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान में जाकर जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाए थे तो भाजपा और संघ परिवार में कितना बवाल खड़ा हो गया था। आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। बाद में एक तरह से संघ परिवार में वे पूरी तरह से दरकिनार हो गए। लेकिन अब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा और संघ की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो मोहन भागवत भी सबके मिलजुल कर रहने और कौमी एकता की बात कर रहे हैं।

एकता के लगातार प्रयास

सितंबर 2019 में भागवत ने दिल्ली में संघ कार्यालय में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदन से मुलाकात की थी। पिछले साल भी मोहन भागवत ने मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत की थी। इसी 30 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी दिल्ली में मुस्लिम धर्म गुरुओं की एक बैठक में हिस्सा लिया था। मोहन भागवत का मुसलमानों से संवाद देश की मजबूती के लिए या मकसद कुछ और? अजीत डोभाल भी मोहन भागवत से लगातार संपर्क में रहते हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं की जिस बैठक में अजीत डोभाल गए थे, उसमें मप्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर पीएफआई पर परिबंध लगाने की मांग की थी। यह संयोग ही था कि



भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गत दिनों कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग पहचान के मामले में हिंदू हैं। संघ के दर्शन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। शिलांग में एक सभा को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। भागवत ने कहा कि हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में और सिंधु नदी के तट के निवासियों को परंपरागत रूप से हिंदू कहा जाता है। इसे भारत भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम का प्रसार करने वाले मुगलों और ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले ब्रिटिश शासकों से भी पहले हिंदू अस्तित्व में थे। संघ की विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू शब्द उन सभी को शामिल करता है जो भारत माता के पुत्र हैं। भारतीय पूर्वजों के वंशज हैं और जो भारतीय संस्कृति के अनुसार रहते हैं। संघ सुप्रीमो ने कहा कि हिंदू बनने के लिए किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां हर कोई हिंदू है। भारत एक पश्चिमी अवधारणा वाला देश नहीं है। यह अनादि काल से एक सांस्कृतिक देश रहा है। वास्तव में यह एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है।

जिस समय मोहन भागवत अपने पदाधिकारियों के साथ मस्जिद में थे, उस समय देशभर में पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी हो रही थी और पीएफआई के नेताओं की धरपकड़ शुरू हो चुकी थी। (गौरतलब है कि 28 सितंबर को सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया)। स्पष्ट है कि संघ, भाजपा और मोदी सरकार उदारवादी मुसलमानों और कट्टरवादी मुसलमानों के साथ अलग-अलग तरीके से व्यवहार कर रही है, ताकि उसके बारे में बनी मुस्लिम विरोधी धारणा को तोड़ा जा सके। हाल ही में ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में शुरू होने पर मोहन भागवत का यह बयान हिंदुओं को आश्चर्यचकित कर देने वाला था कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। हाल ही के वर्षों में देश का हिंदू जागृत और उग्र हुआ है। वह संघ से इस तरह के बयानों की कल्पना नहीं करता। इससे हिंदुओं के एक वर्ग में संघ के प्रति गुस्सा भी पनपा लेकिन एक अन्य वर्ग में उनके इस बयान को हिंदुओं और मुसलमानों में सौहार्द बढ़ाने वाला कदम भी माना गया। उसी कड़ी में संघ प्रमुख ने मस्जिद में जाकर इमामों के ऑल इंडिया संगठन के साथ बातचीत का दरवाजा खोला है।

मोहन भागवत और संघ के अन्य पदाधिकारी

एक घंटे तक मस्जिद में रहे और मौलाना जमील अहमद इलियासी के दोनों बेटों इमाम उमर इलियासी और शोएब इलियासी से लंबी बातचीत की। संघ उमर इलियासी के माध्यम से पूरे मुस्लिम समाज के साथ बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। बंद कमरे में हुई इस बैठक के बाद शोएब इलियासी ने कहा कि मोहन भागवत का मस्जिद में आना मुल्क के लिए बड़ा संदेश है। यह मुसलमानों के लिए मोहब्बतों का पैगाम है। इसे इतना ही देखा जाना चाहिए। इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि मोहन भागवत मस्जिद क्यों गए? मुल्क के लिए ये सुखद परिस्थिति है। इससे मोहब्बत का एक पैगाम जाता है। शोएब ने यह भी कहा कि मोहन भागवत ऐसे नहीं हैं, जैसी कि उनकी छवि पेश की जाती है। उन्होंने श्रीमद्भागवत गीता पर लिखी उनकी किताब को देखा और सराहा।

स्वाभाविक है कि इससे कट्टरपंथी मुसलमानों और तथाकथित सेक्युलर दलों में खलबली मचेगी, जो मुसलमानों को संघ का डर दिखाकर अब तक राजनीतिक रोटियां सेंकते रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने संघ के स्वयंसेवकों की यूनिफार्म की निक्कर में आग लगाकर हिंदू-मुस्लिम के बीच दरार को चौड़ा करने का काम किया है, वहीं संघ बिना

किसी शोर-शराबे के मुस्लिम समुदाय से मिलकर भारतीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में लगा हुआ है।

सुनियोजित आउटरीच

भागवत का मस्जिद दौरा कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक 'सुनियोजित आउटरीच' प्रोग्राम का हिस्सा है, जो पिछले एक साल से मुस्लिम कट्टरपंथियों, अलगाववादियों से लड़ने और देश की रक्षा करने के लिए चलाया जा रहा है। भागवत ने अखिल भारतीय इमाम संगठन (एआईआईओ) के निमंत्रण पर दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसे का दौरा किया। दौरे के दौरान संघ प्रमुख ने संघ के पदाधिकारियों कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार के साथ कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद के अंदर उनके कार्यालय में एआईआईओ प्रमुख उमर अहमद इलियासी के साथ बैठक की। इसके बाद वह उत्तरी दिल्ली के आजादपुर स्थित मदरसा ताजवीदुल कुरान पहुंचे और वहां के छात्रों से बातचीत की। अगस्त में भागवत ने पांच मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, राष्ट्रीय लोक दल के नेता शाहिद सिद्दीकी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर जमीरउद्दीन शाह और व्यवसायी सईद शेरवानी से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, आउटरीच का मकसद अलगाववादियों और कट्टरपंथियों से लड़ना है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर का कहना है कि सरसंचालक लंबे समय से कहते रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए और वंश एक ही है। हमारे पूजा करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है कि मुस्लिम संगठन हमें आमंत्रित कर रहे हैं और हम सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। यह राष्ट्रहित में काम करेगा। पिछले साल जुलाई में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (संघ से संबद्ध) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा था कि भारत के हिंदू या मुसलमान एक ही डीएनए साझा करते हैं और देश में रहने वाले सभी समुदायों के पूर्वज एक जैसे हैं। एक साल बाद, इस साल जून में नागपुर में एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों से हर मस्जिद के नीचे 'शिवलिंग' की तलाश बंद करने को कहा। यह बयान ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के इस दावे कि देश में मंदिरों को तोड़कर कई मस्जिदों का निर्माण किया गया है, के बीच आया।

राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि मुस्लिमों के बीच पहुंच बनाने का यह प्रयास सिर्फ

‘प्रतीक’ के तौर पर न हो, बल्कि जमीनी स्तर पर लिए जाने फैसलों में भी नजर आना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुशीद का कहना है कि इनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि लगभग सभी बैठक बंद दरवाजे के पीछे की गई। जो लोग मोहन भागवत से मुझसे ज्यादा मिले हैं, उन्हें यह समझना होगा कि संघ की वैचारिक स्थिति सत्ताधारी पार्टी (भाजपा) की राजनीतिक लाइन के साथ है या नहीं। क्या वे तटस्थ, लचीले और बदलाव चाहने वाले हैं? इन मुद्दों पर समय आने पर ही कोई राय बनाई जा सकती है। वह आगे कहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि संघ की फिलहाल स्थिति क्या है? उनके रुख से हाल-फिलहाल तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जिसे संदर्भ के रूप में लिया जा सके। क्या ऐसा कोई उदाहरण है जब आरएसएस को अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर उन्हें सांत्वना देते देखा गया हो? अगर उनका मकसद समुदायों को विभाजित करने के प्रयासों को बंद करना है, तो इससे किसी को भी कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हमें इसे पूर्वाग्रहों से नहीं बल्कि सहजता के साथ देखे जाने की जरूरत है।

प्रयास जमीनी स्तर पर नजर आए

संघ के पदाधिकारियों ने भागवत की मस्जिद और मदरसा यात्राओं को ‘दोनों समुदायों के बीच संघर्ष’ को खत्म करने की दिशा में एक कदम बताया और मुसलमानों को भारतीयों की तरह महसूस करने और काम करने की बात कही। वहीं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों ने मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास नारे को रेखांकित करते हुए कहा कि भागवत का समान डीएनए वाला बयान संघ कैडर और हिंदुत्ववादी संगठनों की गतिविधियों में नजर आना चाहिए। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और बेंगलुरु स्थित जैन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड एजुकेशन के निदेशक संदीप शास्त्री ने कहा, ‘यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। इसे प्रतीकात्मक दौरों और बैठकों से आगे ले जाना होगा। मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने और उसके नतीजे जमीन पर नजर आने चाहिए। इन ‘प्रतीकात्मकता’ प्रयासों को ऐसे कामों के साथ मजबूत किए जाने की जरूरत है, जो नजर आए।’ संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि संघ लंबे समय से इस तरह के आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बना रहा है और इसे मुस्लिम समुदाय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा, ‘मुसलमान इस देश का हिस्सा हैं। हम उन लोगों का समर्थन नहीं करते हैं जो उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं। हम ऐसे फ्रिज तत्वों को खत्म करने की कोशिश



मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने में भागवत सफल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हमेशा ही अपने भाषणों में देश की प्रगति के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव के माहौल को पहली आवश्यकता बताया है। गौरतलब है कि विगत दिनों उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर दो टूक लहजे में कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की मानसिकता का हमें परित्याग करना चाहिए। भागवत ने मंदिर-मस्जिद विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया था। संघ प्रमुख ने धर्म संसद में साधु-संतों द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों से असहमति जताते हुए उसे हिंदुत्व के खिलाफ बताया था। संघ प्रमुख ने अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यहां तक कहा था कि संघ अब किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि देश में भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव निर्मित करने में सरसंघचालक मोहन भागवत के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इस दिशा में समय-समय पर मोहन भागवत ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसका मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने जिस तरह तहे दिल से स्वागत किया है उससे यही संदेश मिलता है कि मोहन भागवत हमेशा ही अपने भाषणों में जिस हिंदुत्व की चर्चा करते हैं वह सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। निश्चित रूप से संघ प्रमुख अपने विचारों से मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं।

करेंगे जो देश के माहौल को खराब करते हैं। लेकिन हमारे प्रयासों को मुस्लिम संगठनों और समुदाय के नेताओं की ओर से समान रूप से समर्थन मिलना चाहिए और उनकी तरफ से भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो ही हम आउटरीच को सफल कह सकते हैं।’ हालांकि, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि संघ की पहुंच ‘अच्छे मुस्लिम, बुरे मुस्लिम नैरेटिव’ पर ‘जनता को बहकाने’ के अलावा और कुछ नहीं है।

लोकतंत्र में संवाद महत्वपूर्ण

राजनीतिक और संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतंत्र में संवाद महत्वपूर्ण है। लेकिन मोहन भागवत से मिलने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों और इमामों के प्रतिनिधिमंडल में से कोई भी पूरे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। किसी भी मामले में हम एक समान चरित्र के नहीं हैं, और इन पांचों बुद्धिजीवियों की मुस्लिम बुद्धिजीवियों के अन्य सदस्यों ने आलोचना की है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या दोनों पक्षों ने बैठक के बाद अपनी स्थिति या रुख में बदलाव किया है। उनका कहना है कि क्या भागवत संघ के हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की एक इस्लामी साजिश के अस्तित्व के सिद्धांत को छोड़ने के लिए आगे आएंगे? एसवाई कुरेशी की किताब ने पिछले साल बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या पर संघ के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। क्या भागवत अपने उसी रुख पर कायम रहेंगे या फिर वह बदल गए हैं? क्या संघ अपने अभियान बंद करने जा रहा है या मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये एक ग्रे एरिया है। इस आउटरीच प्रोग्राम को लेकर सोच मिली-जुली है। भागवत को अपने खेमे में

कट्टरपंथियों को रोकना चाहिए। जब मुसलमानों पर हमला हो तो चुपचाप बैठे रहें और कहें कि 'ऐसा नहीं होना चाहिए' काफी नहीं है।' विशेषज्ञों के मुताबिक, मोहन भागवत और भाजपा सहित संघ परिवार के उन सभी नेताओं को जो पहले राजनीतिक मुद्दों पर बोलने वाले कई इमामों के आलोचक रहे हैं, उनसे मिलते हुए देखना विरोधाभासी लगा। उन्होंने कहा, 'यह जनता को बहकाने वाला एक और प्रयास है, जो अच्छे इमाम और बुरे इमाम की बाइनरी बना रहा है। जैसे उन्होंने अच्छे मुस्लिम और बुरे मुस्लिम नैरेटिव बनाया है।

भागवत की मुलाकात के मायने

विचारधाराओं के खेल में उलझी राजनीतिक पार्टियां, और राजनीतिक पार्टियों की शगूफे से निकली जनता के लिए नीतियां, समाज सुधार पर कम और खुद की ईंट मजबूत करने में लिए ज्यादा कारगर साबित होती हैं। क्योंकि जिस विचारधारा का सहारा लेकर पार्टियां हमसे हमारे वोट लेती हैं, दरअसल वो उनकी होती ही नहीं है। जैसे सवाल उठे कि भाजपा की विचारधारा क्या है? तो जुबान पर यही आएगा, जो संघ की विचारधारा है। और जब सवाल होगा कि संघ की विचारधारा क्या है? तो शायद जवाब होगा कि हिंदुत्व का प्रचार देश के कोने-कोने में करना? अब समझने वाली बात ये है कि जिस देश की जनसंख्या का 20 फीसदी हिस्सा मुसलमान हो, 2 प्रतिशत के करीब सिख हो, 2 प्रतिशत के करीब ही ईसाई हों, उस देश में अगर सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी, तो विकास के नाम पर क्या ही हाथ लगेगा। इसके बावजूद संघ ने अपना ये काम लगातार जारी रखा है, और उसको एक बेहतरीन जरिया मिला है भाजपा के रूप में। अब साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भाजपा तो अपना प्रचार कर ही रही है, लेकिन संघ की ओर से भी हर बार की तरह भाजपा के प्रचार के लिए बढ़िया प्लान तैयार कर लिया गया है। जिसकी शुरुआत संघ



प्रमुख मोहन भागवत ने कर भी दी है। कहने को तो मोहन भागवत इन दिनों बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है? हम वो जानने की कोशिश करेंगे।

साल 2025 में संघ के 100 बरस पूरे हो जाएंगे, ऐसे में पूरी उम्मीद है वहां एक प्लान तैयार हो रहा जो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए है। और इसके लिए किसी भी हालत में भाजपा का केंद्र की सत्ता में बने रहना बहुत जरूरी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, देश की जनता ने खुद देखा होगा, कि पिछले कुछ सालों में कैसे इस बात को भाजपा और संघ की ओर से बहुत मुखरता से उठाया गया है। आपने गलियों में, बाजार की दीवारों पर अक्सर लिखा देखा होगा, कई बार तो साधु संतों के कार्यक्रम में इसकी प्रतिज्ञा तक ले ली जाती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहन भागवत जिस तरह से अचानक सक्रिय हो गए हैं, वो एक तीर से दो निशाने यानी हिंदू राष्ट्र का सपना और भाजपा के लिए प्रचार दोनों कर रहे हैं। भाजपा के प्रचार के लिए मोहन भागवत को मुसलमानों से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? इसके लिए पहले उप्र चलते हैं, जहां चुनावों के वक्त योगी

आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था, कि हमारी लड़ाई 80 बना 20 की है। यानी 80 प्रतिशत हिंदू और 20 प्रतिशत मुसलमान। फिर जिस तरह से टारगेटेड बुल्डोजर चलाए गए, देश में हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़के, फिर भाजपा की प्रवक्ता ने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इन कार्रवाईयों और घटनाओं के बाद कहीं न कहीं देश का मुसलमान भाजपा से दूरी बना रहा है। जिसे मनाकर भाजपा के पक्ष में लाना ही होगा। यानी किसी भी हालत में पहले भाजपा को सत्ता में लेकर आना बेहद जरूरी है। इसके अलावा एक बार पहले भी मोहन भागवत कह चुके हैं कि हिंदू शब्द हमारी मातृभूमि, पूर्वज और संस्कृति की समृद्ध धरोहर के बराबर है और हर भारतीय हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। इस को बात को समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने के लिए हिंदुओं का बहुसंख्याक होना जरूरी है, जो देश में हैं, लेकिन 20 प्रतिशत मुसलमानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में लोगों के मन पूर्वजों, संस्कृति के प्रति कैसे एक तरह की वैचारिक सहमति बनाई जाए, ये भी संघ की तरफ से बड़ा मकसद होगा, ताकि आने वाले वक्त में जब संघ अपने मकसद की ओर बढ़े तो

पीएफआई पर लगा 5 साल का प्रतिबंध

देश में दंगा भड़काए जाने और टेरर फंडिंग सहित युवाओं को बरगलाने और देश के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ने के मिले सबूत के बाद केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को गैरकानूनी संस्था घोषित किया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पीएफआई अब देश में किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकती और न ही कोई कार्यक्रम कर सकती है। एक सप्ताह में संगठन के खिलाफ देशभर में हुई छापे की दो कार्रवाई में 350 से अधिक दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि यह संगठन देश के खिलाफ काम कर रहा था। गृह मंत्रालय ने देश विरोधी गतिविधियों के पुख्ता सबूत मिलने पर पीएफआई के साथ ही रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कार्टिसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्ग, नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन को भी 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। इसके बाद एनआईए ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करते हुए बताया था कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई ने युवाओं को लश्कर-ए-तैयबा, इस्लामिक स्टेट (आईएस) और अल-कायदा सहित आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं, ईडी ने कोर्ट को बताया था कि आरोपियों को पीएफआई के अन्य सदस्यों, हवाला, बैंकिंग चैनलों आदि के माध्यम से यह राशि मिली है। इस धन का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों और अपराधों को अंजाम देने में किया गया है। पीएफआई के पदाधिकारियों की साजिश के तहत सालों से विदेश से फंड ट्रांसफर गुप्त या अवैध चैनल के जरिए किया जा रहा था। गृह मंत्रालय के मुताबिक, जांच में पता चला है कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नेता रहे हैं और पीएफआई का संबंध जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश से भी रहा है।

ए कला चलो रे की नीति अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को राजनीतिक फोकस में ले आए हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा से ज्यादा केजरीवाल के बयान सुर्खियां बन रहे हैं।

वह सिर्फ चौंकाने और लुभाने वाले बयान ही नहीं देते। कुछ काम भी ऐसे करते हैं कि सुर्खियां बटोर लेते हैं। मीडिया को पता होता है कि उनके

काम में भी ड्रामा है और बयान में भी ड्रामा है। इसके बावजूद मीडिया उन्हीं को तक्जो देता है, क्योंकि अब जनता को भी राजनीतिक ड्रामेबाजी और विवादास्पद हरकतें ही आकर्षित करती हैं।

पिछले दिनों कांग्रेस ने आरएसएस की यूनिफार्म के अंग रहे खाकी नेकर में आग की फोटो ट्विटर पर डाल दी, तो मीडिया की सुर्खी बन गई। जबकि यह एक निम्न स्तर की भद्दी हरकत थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उस तस्वीर को रिट्वीट करते हुए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। इस एक हरकत ने जितनी सुर्खियां बटोरी, उतनी राहुल गांधी की पदयात्रा और बयानों ने नहीं बटोरी, जबकि महत्वपूर्ण पदयात्रा है। इसी तरह दिल्ली सरकार के घोटालों की खबरों ने उतनी सुर्खियां नहीं बटोरी, जितनी इस आरोप ने कि भाजपा आम आदमी पार्टी के विधायक खरीद रही है। दिल्ली सरकार के तीन-तीन घोटालों की सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन सुर्खियां बटोर रहे हैं केजरीवाल के बयान और उनकी हरकतें। गुजरात में हाल ही में उन्होंने श्री व्हीलर चालक के घर खाना खाने को उसी तरह पब्लिसिटी दिलवाई, जो पंजाब में और उससे पहले दिल्ली में कर चुके थे। सिर्फ उसे दोहराया ही नहीं, पब्लिसिटी के लिए पुलिस से भी भिड़ गए। पहली बार चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल ने विधायकों की खरीद फरोख्त होने का नाटक किया था। उस नाटक का एक प्रमुख पात्र आम आदमी पार्टी का वह कार्यकर्ता टीवी पर आकर बता चुका है कि उसी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को अरुण जेटली और गडकरी के नाम से फोन किया था। उसी आरोप को अब केजरीवाल ने चार विधायकों को सामने लाकर दिल्ली में दोबारा दोहराया है। लेकिन भाजपा की मांग के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। अब उसी नाटक को पंजाब में किया गया है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के दस विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर दी है। लेकिन पंजाब में एफआईआर दर्ज करवा दी, क्योंकि पंजाब पुलिस पंजाब सरकार के अधीन है। दोनों ही मामलों में समझने वाली बात यह है कि दोनों राज्यों में स्पीकर आम आदमी पार्टी का है। कानून के मुताबिक दलबदल या पार्टी तोड़ने के

राजनीतिक पैतरेबाजी में केजरीवाल सबसे तेज



दिल्ली की कमाई बंद तो पंजाब से इंतजाम

सीबीआई केजरीवाल के पीछे पड़ गई है। शराब नीति की जांच सीबीआई कर रही है। स्कूल निर्माण की जांच सीबीआई कर रही है, बसों की खरीद और उनकी मेंटेनेंस की जांच सीबीआई कर रही है। केजरीवाल के व्यक्तिगत प्लाट बिक्री में राजस्व चोरी की जांच चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। शराब घोटाले के संबंध में हुए दो स्टिंग ऑपरेशन में कुछ नई बातें सामने आ चुकी है। एक आरोपी अमित अरोड़ा ने स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया कि डीलर का कमिशन 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया था, लेकिन इसमें से 6 प्रतिशत आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा था। डीलर सिर्फ दो बनाए गए थे, इन दोनों से पहले एकमुश्त राशि ली गई थी। इसी तरह ठेकेदारों की जमानत राशि 5 करोड़ रुपए कर दी गई थी ताकि छोटा व्यापारी बीच में आ ही न सके। घोटाले का हंगामा मचने पर दिल्ली की शराब नीति तो वापस ले ली गई, लेकिन उन्हीं दोनों डीलरों को पंजाब में शराब सप्लाय का कारोबार दे दिया गया है। बाकी सारी नीति वही है, जो दिल्ली में अपनाई गई थी, अंतर सिर्फ यह है कि कमीशन 12 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत रखा गया है। यानी दिल्ली की कमाई बंद हुई तो पंजाब से इंतजाम किया गया है।

लिए दो-तिहाई विधायक चाहिए होते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और गोवा में कांग्रेस के दो तिहाई विधायक टूटे हैं। कर्नाटक और मद्र में जहां कांग्रेस के दो-तिहाई विधायक इकट्ठे नहीं हुए थे, वहां दलबदल करने वाले विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन की थी।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, जब तक 41 विधायक इकट्ठे नहीं होंगे, दलबदल नहीं हो सकता। इसी तरह पंजाब में 92 विधायक हैं, जब तक 62 विधायक इकट्ठे नहीं होते, दलबदल नहीं कर सकते। दोनों राज्यों में 20-20 विधायक भी इस्तीफा दे दें, तो भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं गिरने वाली, तो फिर

कोई 20-20-25-25 करोड़ देकर विधायक क्यों खरीदेगा, जैसा कि केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने साफ सुथरी छवि वाले लोगों को नेता बनाने का वायदा कर पार्टी बनाई थी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के 92 विधायकों में से 52 पर और 11 मंत्रियों में से 7 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। केजरीवाल आजकल गुजरात और हिमाचल में ही सबसे ज्यादा समय लगा रहे हैं, जहां वह मुफ्त सुविधाओं के बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों में उन्होंने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। यही वायदा उन्होंने दिल्ली और पंजाब में भी किया था। दिल्ली में यह वायदा निभाया भी, जिससे आकर्षित होकर पंजाब में उन्हें बंपर जीत मिली। लेकिन अब दिल्ली में क्या हो रहा है?

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने नया फरमान जारी किया है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली उसी को दी जाएगी, जो आवेदन करेगा। एक फार्म भी सर्कुलेट किया गया है, आवेदन सीधे मुख्यमंत्री के नाम देना होगा। ताकि वोटर को यह एहसास हो कि उसे केजरीवाल ने फ्री बिजली दी। उन आवेदनकर्ताओं की सूची बनाकर आम आदमी पार्टी अलग से संपर्क साधेगी और आवेदनकर्ताओं को बताएगी कि उसे फ्री बिजली आम आदमी पार्टी ने दी है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार सभी को फ्री बिजली देने का वायदा निभाने में विफल रही है। चुनाव में सभी घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली का वायदा किया था, लेकिन चुनाव बाद इतनी शर्तें लगा दीं कि 30 प्रतिशत घरों को भी फ्री बिजली नहीं मिली। दिल्ली के अस्पतालों और स्कूलों का जो प्रचार हिमाचल और गुजरात में किया जा रहा है, वह भी केजरीवाल की कलाकारी ही है। अस्पताल एक भी नया नहीं बना है और गत 15 सितंबर को भी जब दूरदर्शन की टीम एक स्कूल की शूटिंग करने गई तो स्कूल में उपस्थित दिल्ली सरकार से जुड़े लोगों ने दूरदर्शन का कैमरा छीनकर तोड़ दिया, जो कई लाख रुपए का था। अगर स्कूलों की हालत विश्वस्तरीय हो गई है, तो दूरदर्शन का कैमरा तोड़ने की क्या वजह थी?

● अक्स ब्यूरो

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली इस यात्रा से राहुल गांधी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। लेकिन यह यात्रा 2024 में कांग्रेस की किस्मत बदल पाएगी इस पर असमंजस है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस अभी भी नेहरू-गांधी परिवार की छाया से बाहर नहीं निकल पाई है। वहीं पार्टी आज पूरी तरह छिन्न-भिन्न है।



दिल्ली अभी दूर है

सिविल सोसाइटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश

केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा में भीड़ उमड़ भी रही है, लेकिन इस बात का अभी भी संशय है कि वे यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि आज कांग्रेस पूरी तरह बिखरी हुई है। उसे समेटना आसान नहीं है। आलम यह है कि पार्टी के कई बड़े नेता आज बाहर हो गए हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का हश्र क्या होगा, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस के लिए दिल्ली अभी दूर है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस वो हर मकसद हासिल करने की कोशिश कर रही है जो चुनौतियों पर काबू पाने में मददगार साबित हों। हाल फिलहाल देखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से विपक्षी खेमे को इकट्ठा करने की भी काफी कोशिशें हुई हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ये सब हुआ लेकिन हालात प्रतिकूल होने की वजह से सारे प्रयास बेकार गए। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस नए सिरे से विपक्षी दलों के नेताओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है।

भारत जोड़ो यात्रा के हीरो तो राहुल गांधी ही हैं, बशर्ते पूरी यात्रा के दौरान वो सबके साथ बने भी रहें। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती लोगों का

कांग्रेस ने सिविल सोसाइटी के करीब 150 लोगों से संपर्क कर समर्थन मांगा था और ये भी उसकी उपलब्धि है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। योगेंद्र यादव ने तो कांग्रेस की यात्रा को भी अरविंद केजरीवाल के रामलीला आंदोलन की तरह हाथोंहाथ लिया है और मेधा पाटकर, तुषार गांधी, अली अनवर और डॉ. सुनीलम जैसे लोगों ने भी सपोर्ट वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। किसान आंदोलन के दौरान काफी सक्रिय होने के साथ-साथ ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली हिंसा जैसे वाक्यों को लेकर निशाने पर रहे योगेंद्र यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। योगेंद्र यादव ने लिखा भी है, देश को एक पुल की जरूरत है। एक ऐसे राजनीतिक पुल की जो विपक्षी राजनीतिक दलों को जमीनी आंदोलनों से जोड़े... भारत के लोकतंत्र को फिर से जगाने-जिलाने और अपने गणराज्य को दोबारा हासिल करने की संभावना इसी राजनीतिक नवाचार पर निर्भर है, यहीं से निकलेगा देश का सच्चा प्रतिपक्ष। पिछली कड़ियों को जोड़कर समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस ने विपक्ष में होते हुए सिविल सोसाइटी के लोगों का ये पैनाल करीब-करीब वैसे ही बनाया है, जैसे यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई थी।

पार्टी से भरोसा उठ जाना भी है और इसे फिर से हासिल करने के लिए ही वो लोगों तक पहुंचने के लिए सिविल सोसाइटी को माध्यम बनाने जा रही है। यात्रा से जुड़ी जो जानकारियां साझा की गई हैं, ध्यान से देखें तो कहीं कोई नई बात, नया आइडिया नजर नहीं आता और यही वजह है कि ये सारी कवायद पुरानी चीजों की नई पैकेजिंग ही लग रही है।

करीब दो दशक के अपने राजनीतिक कैरियर में राहुल गांधी कई पदयात्राएं कर चुके हैं। छोटी-छोटी भी और बड़ी भी। 2017 के उप विधानसभा चुनावों से पहले भी वो किसान यात्रा पर निकले थे। उसके पहले भी किसानों की समस्याओं को करीब से समझने के लिए वो यात्राएं कर चुके हैं। खास बात ये रही कि वो यूपीए की सरकार में भी वैसे ही यात्राएं करते रहे, जैसे मौजूदा मोदी सरकार के जमाने में और लोगों पर असर नहीं छोड़ पाने की एक वजह ये भी लगती है। भारत जोड़ो यात्रा की टेगलाइन है- मिले कदम, जुड़े वतन। 150 दिनों में साढ़े तीन हजार किलोमीटर का सफर पूरा करने वाली ये यात्रा 7 सितंबर को शाम 5 बजे कन्याकुमारी से शुरू हो गई है जो कश्मीर पहुंच कर खत्म होगी। ये यात्रा 12 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरने वाली है।

यह यात्रा एक तरह से राहुल गांधी को नए



कांग्रेस को भाजपा के विकल्प के तौर पर पेश करने कोशिश

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भाजपा के संपर्क फॉर समर्थन अभियान की झलक भी देखी जा सकती है। 2019 के आम चुनाव से पहले सीनियर भाजपा नेता अमित शाह ने ये मुहिम चलाई थी। मुहिम के तहत वो देशभर में घूम-घूमकर ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे थे जिनका समाज पर किसी न किसी तरीके से प्रभाव देखा जाता हो। ऐसे लोगों से मिलकर भाजपा नेता गुजारिश कर रहे थे कि वे लोगों को भाजपा को वोट देने के फायदे समझाएं और सुनिश्चित करें कि लोग भाजपा को वोट दें। तब तो अमित शाह एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के घर तक पहुंच गए थे। मुंबई में मातोश्री से लेकर पटना में नीतीश कुमार तक। अब ये कहानी इतिहास बन चुकी है। और कुछ हासिल हो न हो, भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के दिमाग में कुछ चीजें रजिस्टर तो होंगी ही। इस यात्रा के भी पब्लिसिटी पक्ष को देखें तो 2014 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के कैम्पेन में हर जगह कोशिश यही रहती थी कि उनके पहुंचने से पहले और रैली करके चले जाने के बाद भी उनका नाम, छवि और उनकी बातें लोगों के दिमाग में रजिस्टर जरूर हों। वैसे भी मोदी के कैम्पेन के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आइडिया पर ही तो कांग्रेस ने ये पूरा तामझाम तैयार किया है। मुद्दे की बात ये है और शक इस बात पर भी पहले से ही जताया जाने लगा है कि आखिर राहुल गांधी यात्रा में कितने दिन शामिल होंगे? और ये सवाल उठने की वजह कोई और नहीं, बल्कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ही है।

केरल में यह यात्रा 18 दिनों तक निकलेगी, वहीं 80 लोकसभा क्षेत्रों वाले उप्र में केवल दो दिन। पार्टी के रणनीतिकार जब तक किसी और योजना के साथ आगे नहीं आते, मसलन उप्र में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कोई समांतर मुहिम चलाई जाए, तब तक इसके पीछे का तर्क समझना मुश्किल है।

सिर से 'लांच' करने की कवायद दिखती है। इसीलिए वही इसके केंद्र में हैं और यह रणनीति उचित भी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल की मौजूदगी से ही यात्रा के प्रति इतनी दिलचस्पी जग रही है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि फिलहाल वही देशभर में पार्टी के लिए भीड़ जुटाने वाले सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि उन्हें स्वयं पर पूरा फोकस रखने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन इसके बावजूद वह इस अभियान के नेतृत्वकर्ता की औपचारिक भूमिका स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं दिखते। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यात्रा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले हो रही है, जिस चुनाव में उतरने के लिए राहुल ने अभी तक हामी नहीं भरी है। यह मानते हुए कि वह इस रुख पर अभी भी कायम हैं, तो राहुल के लिए छवि निर्माण की इतनी बड़ी कवायद के बाद नए अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी रूप से संभालना मुश्किल होगा। इस प्रकार के जन जुड़ाव वाले अभियानों के वास्तविक लाभ स्थानीय और राज्य संगठनों से जुड़े होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के नेता द्वारा सकारात्मक भावनाएं भुनाने का पहलू समाहित होता है। जैसा कि भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी की राम मंदिर रथयात्रा के साथ किया था। कांग्रेस के लिए मुश्किल यही है कि इस समय राज्यों में उसका सांगठनिक ढांचा लुंजपुंज अवस्था में है और क्षत्रप एक-दूसरे से लड़ने पर आमादा हैं। इसके भी कोई संकेत नहीं कि जिन क्षेत्रों से यह यात्रा गुजर रही है, वहां स्थानीय सांगठनिक मुद्दे सुलझ जाएंगे।

खासतौर से यह देखते हुए कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वयं नए अध्यक्ष के लंबित चुनाव में उलझाव से जूझ रहा है। इस प्रकार के व्यापक जनसंपर्क अभियान का पार्टियां चुनावी लाभ उठा सकती हैं, मगर भारत जोड़ो यात्रा का मतव्य कुछ अलग दिखता है। उसने गुजरात और हिमाचल जैसे उन राज्यों से स्वयं को दूर रखा है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं इसके कारण भी ज्ञात नहीं कि आखिर किस वजह से लोकसभा की 20 सीटों वाले राज्य

यह भी एक पहेली है कि इस यात्रा के आरंभ में तो राष्ट्रीय कद के नेताओं का जमावड़ा देखा गया, लेकिन बाद में वरिष्ठ एवं जनाधार वाले नेता नदारद दिख रहे हैं। शायद यह सुनियोजित रूप से किया गया हो, ताकि पूरा फोकस केवल राहुल पर रहे। पार्टी की ओर से जो फोटो जारी किए जा रहे हैं, उनमें भी राहुल ही आम लोगों से चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। यह भी उन्हें 'जन-नेता' के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हालांकि ऐसा करके नेतृत्व की एकता और गहराई को दर्शाने का बड़ा अवसर गंवा दिया गया। वहीं योगेंद्र यादव जैसे 'बाहरी' लोग इस यात्रा से जुड़कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस यही उम्मीद कर सकती है कि 150 दिनों तक चलने वाली 3,500 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी ही केंद्रीय भूमिका में रहें। अन्यथा यह अभियान पटरी से उतर जाएगा और दूसरे लोग मजमा लूट ले जाएंगे। कांग्रेस के इस अभियान की मंशा स्पष्ट है कि इसके माध्यम से वह अपनी अखिल भारतीय मौजूदगी दर्शा कर विपक्षी खेमे को यही संकेत देना चाहती है कि किसी भी गैर-भाजपा मोर्चे के लिए वह अपरिहार्य है। कांग्रेस का यह दावा मजबूत होगा या कमजोर, वह इस यात्रा की सफलता पर निर्भर करेगा। विशेषकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर है और उसका सांगठनिक ढांचा भी कमजोर है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल और के. चंद्रशेखर राव जैसे दो नेता कांग्रेस के साथ गठजोड़ को कतई तैयार नहीं दिखते। यही बात ममता बनर्जी के बारे में कही जा सकती है। केरल में यात्रा के लंबे पड़ाव से माकपा का भी मुंह बना हुआ है।

वहीं भाजपा हरसंभव तरीके से राहुल की किसी भी गलती को भुनाने के लिए तैयार है। उसने यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आलीशान कंटेनरों पर निशाना साधा। यात्रा के दौरान जिन लोगों से राहुल मिल रहे हैं, उन पर भी भाजपा की पैनी नजर है। जैसे एक विवादित पादरी से मुलाकात पर तुरंत राहुल को घेरा गया। कुडनकुलम परियोजना और स्ट्रलाइट-विरोधी प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार लोगों से उनकी मुलाकात को भाजपा ने खासा तूल दिया। भाजपा के इस रुख से तिलमिलाई कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश का हिस्सा रहे खाकी निकर को जलाते हुए एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट डाली। कुछ लोग मानते हैं कि यात्रा को ज्यादा तवज्जो देकर भाजपा राहुल की ही मदद करेगी। हालांकि यह इसी पर निर्भर करेगा कि यात्रा के माध्यम से राहुल क्या अपनी छवि ही निखारेंगे या पार्टी में नई जान डालेंगे। पार्टी में नए प्राणों का संचार इस लंबी यात्रा से कहीं अधिक आवश्यक है। वही कांग्रेस की असल चुनौती भी है। बहरहाल, यह यात्रा अभी शुरू हुई है, पर कांग्रेस के लिए 'दिल्ली अभी दूर' है।

● विपिन कंधारी

6

भाजपा को 2024 में चुनौती देने के लिए विपक्ष में एकता की लगातार कवायद चल रही है। कभी ममता बनर्जी, कभी केसीआर, तो कभी शरद पवार और नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी की भी कोशिश परवान नहीं चढ़ी है। ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली स्थिति न बन जाए। क्योंकि हर नेता की अपनी अलग नीति और रणनीति है। इससे विपक्ष में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी तक विपक्ष किसी ठोस रणनीति पर नहीं पहुंच पाया है। जिससे भाजपा में संतोष देखा जा रहा है।

9



भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। कभी कोई तो कभी कोई अपने नेतृत्व में संग्राम का ऐलान करता है। अभी हाल ही में हरियाणा में एक बड़ी रैली आयोजित की गई। जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हुए। सबकी एक ही हुंकार थी कि 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इस पर पेंच फंस रहा है।

जिन पर घर बनाने का जिम्मा हो, वही घर गिराने लगे तो उन लोगों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, जो घर बनने का इंतजार कर रहे हों। अपने देश में विपक्षी एकता का यही हाल है। ज्यादातर त्योहार साल में एक बार आते हैं, पर विपक्षी एकता का त्योहार हर पांच साल में एक बार आता है। आम चुनाव से पहले इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात। इस समय विपक्षी एकता का मौसम चल रहा है, पर बयार उलटी बह रही है। दल जुड़ने से ज्यादा बिखर रहे हैं।

विपक्षी एकता दो तरह की होती है। एक चुनाव से पहले की और दूसरी चुनाव के बाद की। चुनाव से पहले की एकता चुनावी मोर्चे पर सफल हो तो उसे जनादेश कहते हैं। चुनाव के बाद की एकता सत्ता के बंटवारे की होती है, पर सत्ता के लिए जनादेश को धता

ज्यादा जोगी मठ उजाड़

नीतीश बुलंद कर चुके हैं मेन फ्रंट का नारा

फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेन फ्रंट का नारा बुलंद कर चुके हैं। कुछ ऐसा ही नामकरण ममता बनर्जी पहले कर चुकी हैं। लेकिन बाकी दलों की ओर से चुप्पी है। पिछले सात-आठ वर्षों में कांग्रेस यह महसूस कर चुकी है कि उसे क्षेत्रीय दलों से अपनी सियासी जमीन वापस लेनी ही होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसकी खुलेआम घोषणा भी कर दी गई कि दोस्ती का अर्थ कमजोर कांग्रेस नहीं है। हालांकि बार-बार यह दोहराया जा रहा है कि यात्रा से सहयोगी दलों को घबराने की जरूरत नहीं लेकिन यह किसी से छिपा भी नहीं है कि कांग्रेस जो कुछ भी अर्जित करेगी वह क्षेत्रीय दलों से छीनकर ही। केरल में वामदलों की ओर से परोक्ष रूप से नाराजगी जताई जा चुकी है। उप्र में कांग्रेस की यात्रा का पड़ाव बहुत सीमित है लेकिन यह देखना रोचक होगा कि यात्रा के दौरान सपा और बसपा की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। जो भी हो यह तो तय है कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ कोई मुख्य गठबंधन बनता है तो कांग्रेस उसे यूपीए की छतरी के तले रखना चाहेगी।

बताने में राजनीतिक दल संकोच नहीं करते। नीतीश कुमार इसके चैंपियन हैं। वह गठबंधन बदलते रहते हैं, पर उनकी कुर्सी नहीं बदलती।

नीतीश कुमार इस समय विपक्षी एकता कराने निकले हैं। उनके पास अपना कोई सौदा नहीं है। वह दूसरे का सामान लेकर व्यापारी बने हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का सौदा कराने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। उन्होंने दिल्ली आकर कई नेताओं से मुलाकात की, पर लालू यादव के आशीर्वाद और सोनिया जी के सम्मान का पूरा ध्यान रखा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में पट नहीं रही। किसी को संदेह रहा हो तो उसे ममता बनर्जी ने एक बार फिर दूर कर दिया। नीतीश कुमार के दिल्ली से जाते ही उन्होंने कहा कि राजद, जदयू, तृणमूल कांग्रेस, सपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ चुनाव लड़ेंगे। यह बयान विपक्षी एकता कराने वाले सभी लोगों के लिए यह संदेश था कि कांग्रेस मंजूर नहीं। दो दिन बाद ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का बयान आ गया कि कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी के भारत लौटते ही उनसे मिलने जाएंगे। मतलब दोनों ने ममता बनर्जी को झिड़क दिया।

हेमंत सोरेन क्या बोल सकते हैं? वह तो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। अखिलेश यादव तो सतत् गठबंधन के साथी की तलाश में रहते ही हैं। उधर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। जो 18 दिन केरल में रहेगी, जहां वाम मोर्चे का राज है। वाम मोर्चे ने कहा है कि

कांग्रेस में आरएसएस की चुनौती का जवाब देने का साहस नहीं है। इसलिए यात्रा गुजरात नहीं जा रही और उग्र में चंद दिन ही रहेगी। इसका जवाब यात्रा के कर्णधार जयराम रमेश ने यह कहकर दिया कि केरल में माकपा भाजपा की ए टीम है। याद रहे ये दोनों दल सवा साल पहले बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं और विपक्षी एका के प्रयासों में शामिल रहे हैं।

विपक्षी एकता के अश्वमेघ घोड़े को लेकर निकले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव लगता है निराश हो गए हैं। उन्होंने अब अपना राष्ट्रीय दल बनाने की घोषणा कर दी है। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी अपने अधिवेशन में विपक्षी एकता का ब्लू प्रिंट पेश करेगी, पर उसकी कोई सुगबुगाहट सुनाई नहीं दी। समस्या यह है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना तो सब चाहते हैं, पर एक-दूसरे की नीयत को शंका की दृष्टि से देखते हैं। यदि पिछले 27 साल में 23 साल भाजपा के साथ रहने वाले नीतीश कुमार भी भाजपा विरोधी होने का दावा करें तो कोई कैसे भरोसा करेगा?

विपक्षी एकता में एक समस्या यह भी है कि जो जोर-जोर से कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हैं, वही सबसे तेज दौड़ रहा है। जैसे पंगत में खाना खाने वाले कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। हमेशा बगल वाले को देने के लिए आवाज लगाते हैं। उनकी नीयत का पता तब चलता है, जब परोसने वाला आ जाता है। भाजपा विरोधी दलों के नेताओं के अहं का भार उनके शरीर के वजन से भी ज्यादा है। कोई अपने को किसी से कम मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी एकता का इतिहास देखें तो चुनाव से पहले या तो एकता होती नहीं, होती है तो सफल नहीं होती और सफल हो भी गई तो चलती नहीं।

आजादी के बाद पहला बड़ा विपक्षी गठबंधन बना 1971 में। वह चुनाव के मैदान में धराशायी हो गया। उसके बाद साल 1977 में जनता पार्टी के रूप में विपक्षी एकता हुई, जो चुनाव में कामयाब रही, पर चली नहीं। वही हथ्र 1989 में बने जनता दल का हुआ। चुनाव बाद बने गठबंधन भी तभी चले, जब उनकी धुरी कोई राष्ट्रीय पार्टी बनी। बहुत से लोगों को चिंता है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा का वर्चस्व स्थापित हो रहा है और उसका कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मौजूदा विपक्षी दलों के पास विकल्प का अभाव है। मतदाता ने जिन दलों को राज्यों में सत्ता सौंपी, उनमें से ज्यादातर को उस राज्य में भी राष्ट्रीय राजनीति के लायक नहीं समझा। इसलिए विधानसभा चुनाव में भाजपा विरोधी जिस पार्टी को जिताया, उसे लोकसभा में किनारे कर दिया। तो मतदाता के मन में कोई भ्रम नहीं है कि किसे राज्य की बागडोर सौंपनी है और किसे देश की?



सभी क्षेत्रीय दल मान चुके हैं कांग्रेस का नेतृत्व

यूपीए एक और यूपीए दो का नेतृत्व कांग्रेस कर चुकी है और यूपीए तीन बनता है तो स्पष्ट है कि सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस का नेतृत्व मान चुके हैं। दूसरी तरफ गठबंधन में कांग्रेस को रखने की वकालत कर रहे नीतीश कुमार मेन फ्रंट की बात कर रहे हैं इसका कोई खाका अभी घोषित नहीं किया गया है। वहीं खुद नीतीश, वाम नेता येचुरी, राकांपा नेता शरद पवार जैसे लोगों ने बार-बार कहा है कि अभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यह भी ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी अपने-अपने राज्य में कांग्रेस को बराबरी का हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। केरल की स्थिति और विकट है जहां कांग्रेस वामदल को तीसरा हिस्सा देने के लिए भी तैयार नहीं होगी। इसी बीच नीतीश की सक्रियता बढ़ी है। इस बीच वे हरियाणा के फतेहाबाद में इनलो के मंच भी दिखे। मजे की बात यह है कि क्षेत्रीय दलों में तीन अहम नेता ममता, के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी हुई है। बल्कि समय-समय पर विरोध भी जताया जाता रहा है।

विपक्षी दलों का सारा जोर हमेशा अंकगणित पर रहता है। पहले कांग्रेस और अब भाजपा विरोधी गिनती करते हैं कि वे सब मिल जाएं तो सत्तारूढ़ दल को हरा देंगे। आखिर इतने लंबे समय से राजनीति करने वालों को यह साधारण सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि चुनाव वोट प्रतिशत के आंकड़ों को जोड़ने से नहीं, जनता से जुड़ने और जोड़ने से जीते जाते हैं। मोदी की सफलता और विपक्ष की विफलता के बीच यही अंतर है। सत्ता में आठ साल रहने के बाद भी मोदी लोगों से जुड़ने और उन्हें जोड़ने का अभियान उसी गति से चला रहे हैं। विपक्षी एकता सत्यनारायण की कथा जैसी हो गई है। कथा में सब जुड़ते हैं और खत्म होते ही अपने-अपने घर चले जाते हैं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले एकता की बातें और उसके बाद सर फुटौबल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला।

विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास और तेज होते दिख रहे हैं। भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक करने के अभियान के तहत दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं। यद्यपि उनका यही कहना है कि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं, लेकिन उनके समर्थक-सहयोगी उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बता रहे हैं। बीते दिनों पटना में ऐसे पोस्टर दिखे, जिन पर लिखा था-प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। क्या दिखेगा, यह स्पष्ट नहीं, लेकिन कोई भी

समझ सकता है कि क्या दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के समय विपक्षी एकता को भंग करने वाली ममता बनर्जी फिर से विपक्ष को एक करने में जुट गई हैं। हाल में उन्होंने कहा कि वह नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अन्य मित्रों के साथ मिलकर भाजपा को बेदखल करेंगी। उन्होंने अन्य मित्रों का नाम लेने से परहेज किया। क्यों किया, यह तो ज्ञात नहीं, लेकिन वह अतीत में कांग्रेस को साथ लिए बिना विपक्ष को एक करने की कोशिश कर चुकी हैं। भले ही ममता कांग्रेस को साथ न लेना चाहती हों, लेकिन वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि नीतीश, तेजस्वी और हेमंत तो कांग्रेस के साथ हैं। जिस तरह ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ नहीं लेना चाहती, उसी तरह केंसीआर यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी। उन्होंने पिछले दिनों यह कहकर चौंकाया कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनने पर देशभर के किसानों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जाएगा। आखिर उन्होंने यह घोषणा किस अधिकार से की? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि अभी तक किसी भी भाजपा विरोधी नेता ने यह नहीं कहा है कि वे उन्हें इसके लिए अधिकृत कर रहे हैं कि वह अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का एजेंडा तय करें।

● इन्द्र कुमार

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही 2023 के नवंबर-दिसंबर में है, लेकिन राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। पिछले दो माह से सूबे के मुखिया भूपेश बघेल राज्य की 90 विधानसभा सीटों की दौरा कर वहां सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा भी बघेल को मात देने में जुट गई है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा के नेताओं को विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के कमजोर बूथ की पहचान कर उसे दुरुस्त करने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद सुनील सोनी कहते हैं कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर संसदीय क्षेत्रों के कमजोर बूथों की पहचान कर उन्हें मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह हमारी पार्टी की रूटीन प्रक्रिया है। भाजपा 24 घंटे 12 माह काम करने वाली पार्टी है। यहां इस तरह के कार्यक्रम हर दिन चलते रहते हैं। पिछले एक माह से मैं अपने क्षेत्र के कमजोर बूथों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहा हूँ और स्थानीय लोगों से बात कर रहा हूँ। इस दौरान लोगों को केंद्र मोदी सरकार की योजनाओं के बारे भी बताया जा रहा है।

मोदी के सहारे मिशन-2023

हाल ही में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बैठक ली थी। इसमें प्रदेश के संघ से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए थे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि ऐसे राज्य जहां भाजपा की सरकार नहीं है या फिर वहां भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, उन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाई गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के सूत्रों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साल 2023 के नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। पिछले चुनावों के कड़वे अनुभवों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व अभी से चुनावी मोड में आ गया है। पार्टी ने सभी सांसदों और विधायकों को कमजोर बूथ को मजबूत करने का निर्देश दिया है। इसकी रिपोर्ट हर माह प्रदेश भाजपा कार्यालय को दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष इसकी समीक्षा करेंगे। इस रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व और संघ के नेताओं को भी सौंपी जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि लगातार 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी 2018 की हार को भुलाते हुए 2023 में सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। पार्टी की यह कवायद उसे संगठनात्मक रूप से मजबूती देगी, जिसका लाभ आने वाले दिनों में मिल सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के



भाजपा धान और धर्म को बनाएगी अपना प्रमुख हथियार

जानकारों का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता भाजपा से कांग्रेस की तरफ चले गए। इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बघेल ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं और राज्य के एक अन्य प्रमुख वर्ग कुर्मी से आते हैं। 2023 के चुनाव में प्रदेश में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के उद्देश्य से एक मजबूत ओबीसी चेहरे को कमान सौंपी गई है। भाजपा ने प्रदेश के मुखिया का चेहरा क्या बदला पार्टी, आरएसएस और इसके आनुषंगिक संगठनों की 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या भूमिका होगी, इस पर विस्तार से विचार-मंथन कर रणनीति करती नजर आने लगी। भाजपा वोटरों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में धान और धर्म को अपना प्रमुख हथियार बनाकर चल रही है। पार्टी धर्मांतरण और धान को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन कर चुकी है। इसके अलावा राज्य में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, खाद आपूर्ति की समस्या, अधोषिष्ठ बिजली कटौती, आदि मुद्दों को समय-समय पर उठाती रही है। सत्ता से बेदखल होने के तीन वर्ष बाद हुए नगरीय निकाय के चुनाव में उसे खासी सफलता नहीं मिल पाई। लगभग तीन वर्ष के अंतराल के बाद हुए इस महत्वपूर्ण चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को एक बार फिर से साफ कर डाला।

सहारे राज्य की सत्ता में वापसी की कवायद पार्टी कर रही है। यह कार्यक्रम इसलिए भी तेजी से चलाया जा रहा है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों 90 विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं। वे लगातार कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच ले जा रहे हैं। कई अहम योजनाएं प्रदेशवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय भी हैं। जबकि कुछ योजनाओं को केंद्र सरकार से पुरस्कार भी मिल चुका है। ऐसे में भाजपा के पास दोहरी चुनौती है। पहली कि बघेल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना और दूसरा मोदी सरकार के काम और योजनाएं को आम लोगों तक पहुंचाना, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिल सके। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

भाजपा भले ही अभी से मिशन 2023 में जुट गई हो, मगर छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस इसे बेफिजूल मेहनत करार दे रही है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भाजपा अभी कितना भी दम लगा ले, कोई भी योजना बना ले, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है। इस बार भी जनता उनका ही साथ देगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा मोर्चा मुख्यमंत्री बघेल ने संभाल रखा है। वे लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है।

पिछले चुनाव में मप्र के साथ छत्तीसगढ़ से बेदखल हुई भाजपा को इस बार यहां से काफी उम्मीद है। इस उम्मीद के चलते पार्टी ने चौतरफा सर्जरी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत उसने बॉटम्स अप एप्रोच की जगह टॉप-टु-बॉटम एप्रोच के साथ की। भाजपा ने सबसे पहले अपना चेहरा बदला। पहले प्रदेश अध्यक्ष हटाए गए, फिर नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया गया। अब भाजपा 2023 का चुनाव पहली बार बने सांसद अरुण साव की अगुवाई में लड़ने जा रही है। पार्टी की सोच है कि कांग्रेस के हावी होते छत्तीसगढ़ियावाद का जवाब अरुण साव हो सकते हैं। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि चेहरे बदलने के बावजूद भाजपा को कुछ हासिल नहीं होने वाला। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया कहते हैं, 'केवल अध्यक्ष बदलने से कोई काम नहीं चलेगा। चार साल में चार अध्यक्ष बदल रहे हैं तो संगठन की क्या स्थिति है यह समझ सकते हैं।' साव मूल रूप से तेली हैं जो छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख ओबीसी वर्ग है। पिछले चुनाव में भाजपा के समर्थक समझे जाने वाले राज्य के साहू मतदाता स्थानांतरित हो गए थे जिसकी वजह से भाजपा को 10 साल के बाद प्रदेश से सत्ता गंवानी पड़ी।

● रायपुर से टीपी सिंह

महाराष्ट्र में 22 जून को शिवसेना में हुई बगावत के बाद भाजपा के सहयोग से बनी एकनाथ शिंदे की सरकार को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन सरकार की स्थिरता को लेकर भाजपा असहज है और अपने दम पर सरकार को स्थिर करने की रणनीति बनाने में जुटी है। उल्लेखनीय है कि अभी तक

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शिंदे गुट से मात्र 9 विधायक ही मंत्री बने हैं। ऐसे में, अभी भी एकनाथ शिंदे के समर्थक 31 विधायक अपने लिए मंत्री पद या महत्वपूर्ण बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। शिंदे ने अपने साथ शिवसेना छोड़कर आए सभी विधायकों को महत्वपूर्ण पद देने का भरोसा दिया था, लेकिन शिंदे के मुख्यमंत्री पद पा लेने के बाद उनके लिए सभी विधायकों को एडजस्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार के पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल अब तक बन चुका है। इसके अलावा शिंदे सरकार ज्यादा से ज्यादा 23 अन्य विधायकों को मंत्री बना सकती है। जबकि अकेले शिंदे गुट के ही 31 विधायक मंत्री पद पाने की उम्मीद कर रहे हैं। भाजपा ने एकनाथ शिंदे से साफ कह दिया है कि आपको मुख्यमंत्री पद देने के बाद आपके सभी विधायकों को एडजस्ट करना संभव नहीं है।

एकनाथ इस बात को समझते हैं लेकिन विधायकों में इस बात को लेकर नाराजगी है। विधायकों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में दो साल से भी कम का समय बचा है, ऐसे में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारी में देरी होती है तो वह अपने क्षेत्र में कैसे काम कर पाएंगे और चुनाव कैसे जीतेंगे? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं लेकिन उनके गुट के कई विधायकों का अभी भी भाजपा के साथ सामंजस्य नहीं हो पाया है और अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्हें भाजपा के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विधायक अपने क्षेत्र में अपने आपको अकेला पा रहे हैं और राकांपा, कांग्रेस, शिवसेना के साथ भाजपा के स्थानीय नेताओं के भी विरोध

शिंदे गुट पर निर्भरता खत्म करने में जुटी भाजपा



का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह से शिंदे गुट के विधायकों के अंदर नाराजगी भी देखी जा रही है।

महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि एकनाथ शिंदे के साथ आए कई विधायक अब वापस उद्धव ठाकरे के पास लौट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ना तय है। शिंदे गुट का दावा है कि उसके पास शिवसेना के 40 विधायकों का समर्थन है। यदि 40 में से चार विधायक भी बगावत करके उद्धव ठाकरे के खेमे में चले जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और वह दलबदल कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। बता दें कि शिवसेना के कुल 54 विधायक हैं। ऐसे में दो तिहाई बहुमत रखना यानी 37 विधायकों का समर्थन बनाए रखना एकनाथ शिंदे के लिए बेहद जरूरी है। विधायकों की नाराजगी की वजह से भी एकनाथ शिंदे कैबिनेट का दूसरा विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। शिंदे गुट के विधायकों में पनप रहे असंतोष को भाजपा भांप रही है, इसलिए भाजपा ने सरकार बचाने के लिए शिंदे पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खबर है कि भाजपा ने कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायकों को अपने साथ आने के लिए मना लिया है और कांग्रेस के ये विधायक जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं और सरकार को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जून में हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया था और शिंदे और फडणवीस सरकार के बहुमत परीक्षण के समय भी कांग्रेस के 10 विधायकों ने

गैर हाजिर रहकर भाजपा को राहत पहुंचाई थी।

एकनाथ शिंदे के दम पर महाराष्ट्र सरकार में वापसी कर चुकी भाजपा अब किसी भी कीमत पर सरकार को गंवाना नहीं चाहती। इसलिए भाजपा महाराष्ट्र में अपनी सरकार के लिए शिंदे पर निर्भरता कम करने और अपने दम पर सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में नीतीश के पलटने से सत्ता से बाहर हो चुकी भाजपा महाराष्ट्र में कांग्रेस और राकांपा में संध लगाकर अपनी सरकार सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक तरफ अपने विधायकों को बचाकर रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ भाजपा की शिंदे पर कम हो रही निर्भरता से भी निपटने की चुनौती है। एकनाथ शिंदे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाजपा उन्हें तभी तक कंधों पर बिठाएगी जब तक उनके दम पर सरकार है। शिंदे के विधायक कम होने और भाजपा के अपने दम पर पूर्ण बहुमत के दरवाजे पर पहुंचने की स्थिति में शिंदे के लिए शिवसेना के अलग गुट के रूप में बने रहना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे को भाजपा में विलय करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। शिवसेना पर दावेदारी को लेकर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास रहती है तो ऐसे में भी शिंदे के पास भाजपा में अपने गुट के विलय के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। भाजपा भी यही चाहती है और ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर रही है जिससे एकनाथ शिंदे के पास भाजपा में विलय के अलावा कोई विकल्प न बचे।

● बिन्दु माथुर

विधानसभा में शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों और 12 सांसदों को लेकर पार्टी विभाजित करने में सफल होने के बाद पार्टी पर भी शिंदे का कब्जा कर लेने के बाद शिंदे ने शिवसेना पर ही दावा कर दिया है। अतः शिवसेना को अपने पास रखने के लिए इस समय उद्धव ठाकरे ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हालांकि वैधानिक रूप से शिंदे गुट को अभी भी शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, लेकिन सत्ता में होने के कारण मिल रहे सभी लाभों और मनोवैज्ञानिक बढ़त के कारण वह बढ़त बनाए हुए है। फिलहाल उद्धव ठाकरे

इधर शिवसेना पर शिंदे का दावा

की एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वह याचिका है जिसमें शिंदे और 15 अन्य को पार्टी का आदेश न मानने के कारण अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। जहां तक चुनाव चिन्ह की बात है तो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत संख्या के आधार पर किसी भी गुट को मूल पार्टी के वैध उत्तराधिकारी की मान्यता देने का अधिकार चुनाव आयोग के पास सुरक्षित है। आयोग की कसौटी पर खरा न उतरने वाला गुट एक अलग चुनाव चिन्ह के साथ नई पार्टी के रूप में पंजीकृत हो सकता है।

अमित शाह के राजस्थान दौरे के बाद रेतीले राजस्थान की रपटीली राजनीति एक बार फिर परवान चढ़ने लगी है। विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी लगभग सवा साल बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ मुश्कें कसी जाने लगी हैं, तलवारें चमकाई जा रही हैं और सियासत के मैदान में रणभेरी गुंजने लगी है। जातिगत समीकरण संवारे जा रहे हैं तो इलाकाई सियासत के शहंशाहों को एक होने की सलाहें दी जा रही हैं।

भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर से सक्रियता दिखाने लगी हैं, तो गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, ओम प्रकाश माथुर, किरोड़ीलाल मीणा, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया सहित कई नेता मोदी-शाह की कृपा से मुख्यमंत्री बनने की आस में हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, रेल व संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए सुनील बंसल के समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में छुपा रुस्तम मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस में सचिन पायलट बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने की तर्ज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष बनने की राह में दुबले हुए जा रहे हैं। दो साल पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ही सरकार गिराने के षड्यंत्र में असफल होने के बावजूद पायलट को पता नहीं यह भरोसा क्यों है कि गहलोत के जाने पर मुख्यमंत्री वे ही बनेंगे।

बहरहाल, राजस्थान में राजनीति की ताजा तस्वीर यह है कि भाजपा चुनाव से सवा साल पहले ही यह आख्यान स्थापित करने के प्रयास में है कि अगली सरकार तो भाजपा की आ रही है। तर्क यह है कि राजस्थान में तो हर पांच साल में सरकार बदलती रहती है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि वह हारती हुई दिख रही है, और न ही भाजपा इतनी मजबूत कि एक झटके में उसे उखाड़कर फेंक दे। दरअसल, मोदी-शाह द्वारा वसुंधरा राजे को किनारे करके अनगिनत नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को हवा देने के कारण प्रदेश



आंतरिक गुटबाजी के शिकार

में भाजपा जबरदस्त बिखराव की शिकार हो चुकी है। माना कि गुटबाजी राजनीति का आवश्यक रंग है, और राजस्थान कांग्रेस में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी है, लेकिन उसके मुकाबले राजस्थान में भाजपा तो गुटबाजी की शिकार होकर बुरी तरह से बंटी हुई साफ दिख रही है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार हैं तो भाजपा में एक दर्जन से ज्यादा।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ताजा राजस्थान दौरे में इस गुटबाजी को दूर करने के जो प्रयास हुए उनकी सार्थकता तो आने वाला वक्त साबित करेगा, लेकिन राजस्थान भाजपा में अंदरूनी सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भाजपा में दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को किनारे करने की जो कोशिशें अब तक हुईं, उनकी पूरी तरह से दरकिनार करते हुए हर बार वसुंधरा राजे फिर से मुख्य तस्वीर में आती रही हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, गृहमंत्री शाह के दौरे में उनको जबरदस्त महत्व मिला। शाह ने उनके कार्यकाल में हुए कार्यों की जमकर तारीफ भी की। वसुंधरा ने भी अपने भाषण में अमित शाह को याद दिलाया कि सन् 2003 में वे जब पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनीं तो, उसके बाद 20 सालों में प्रदेश में कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई। इशारा साफ था कि मुख्यमंत्री चेहरे पर नेतृत्व को उनके

बारे में सोचना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल सहित प्रदेश भाजपा सतीश पूनिया, विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और उप नेता राजेंद्र राठौड़ इस दौरे में अमित शाह द्वारा वसुंधरा राजे को अप्रत्याशित महत्व दिए जाने से कुछ हैरान थे। निश्चित रूप से अमित शाह ने भी देखा ही होगा कि शेखावत के चुनाव क्षेत्र जोधपुर में ही पूनिया समर्थकों के पोस्टरों से शेखावत गायब थे, तो शेखावत के पोस्टरों से वसुंधरा और पूनिया दोनों ही फुर्र। तस्वीर साफ थी कि कड़वाहट बरकरार है। सो, अमित शाह ने दूसरे ही दिन यह भी साफ कह दिया कि कार्यकर्ताओं में प्रदेश में जो जबरदस्त जोश व उत्साह है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2023 में राजस्थान में मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। इसलिए सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। संदेश साफ था कि प्रदेश के किसी एक नेता को चुनाव की कमान नहीं सौंपी जाएगी, सब मिलकर काम करेंगे। और सीधा मतलब यही था कि भाजपा 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, और यह भी कि चुनाव अभियान की कमान भी राष्ट्रीय नेतृत्व के पास रहेगी।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

भाजपा में कई तो कांग्रेस में दो खेमे

उधर, भाजपा के कई खेमों के मुकाबले कांग्रेस में केवल दो ही खेमे हैं, एक पायलट का, तो दूसरा गहलोत का, और दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क। गहलोत के साथ लगभग 120 विधायक हैं, तो पायलट के साथ अब केवल चार। हालांकि, जून 2020 में जब वे अपनी ही सरकार पलटने निकले और महीने भर तक मानेसर के होटल में जाकर बैठे थे, तो दावा था कि उनके साथ 20 विधायक हैं। लेकिन एक-एक कर विधायक टूटते गए पर पायलट कुछ न कर पाए। उल्टे उन्हें उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसे दोनों महत्वपूर्ण पदों से पार्टी ने बर्खास्त कर दिया और तब से ही पायलट खुन्स में हैं कि कैसे वे गहलोत को अपनी ताकत दिखाएं। ताजा माहौल में जबसे राहुल गांधी ने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है और अशोक गहलोत के माथे अध्यक्ष पद का ताज पहनाने की चर्चा है, तब से ही पायलट समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। उन्हें लगने लगा है कि पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सीपी जोशी, महेश शर्मा, गोविंद सिंह डोटारसा जैसे कई नेता भी गहलोत के सहज उत्तराधिकारियों की सूची में हैं। फिर भी, ताकत दिखाने की कोशिश में 7 सितंबर को पायलट ने अपने जन्मदिन से पहले 6 सितंबर को जयपुर में जबरदस्त जलसा करके शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की। वैसे, पूर्वी राजस्थान के गुर्जर और मीणा युवक पायलट समर्थकों में बहुतायत में है, लेकिन राजस्थान के बड़े भू-भाग पर पायलट का कोई बहुत सियासी वर्चस्व नहीं है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उग्र में संचालित हो रहे मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया है। एसडीएम, बीएसए तथा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सर्वे में कुल ग्यारह बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठा कर 10 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट जिलों के डीएम को सौंपेंगे। डीएम को अपनी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को देनी है। माना जा रहा है कि योगी सरकार की नजर अवैध मदरसों में संचालित होने वाली गतिविधियों पर है। कई मदरसों का अतीत दागदार रहा है तथा कई आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उनका मदरसा कनेक्शन भी सामने आ चुका है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी सरकार मदरसों के सुदृढ़ीकरण के साथ अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए भी मदरसों के संचालकों और उनके फंडिंग तंत्र पर निगाह रखना जरूरी है।

योगी सरकार के इस फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार के इस फैसले को मुसलमानों को परेशान करने वाला तथा मिनी एनआरसी बताया है। वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने फैसले का विरोध करते हुए गत दिनों पहले गैर सरकारी इमदाद से चलने वाले मदरसा संचालकों की बैठक बुलाई थी। उग्र के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि मदरसों का सर्वे मॉडर्न एजुकेशन के लिए बेहद अहम कदम है। सर्वे से मदरसों का पूरा डाटा सरकार के पास होगा, जिससे भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। मदरसों में अच्छी शिक्षा एवं सुविधा के लिए मदरसा बोर्ड प्रदेशभर में लगातार काम कर रहा है।

मदरसों में शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्य करने की कवायद हो या महिला शिक्षकों की मैटरनिटी लीव, कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। पर यह भी सच है कि प्रदेश के कई मदरसे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए परेशानी का सबब रहे हैं। बीते एक दशक में जिस तेजी से अवैध मदरसे खुल रहे हैं, वह सरकार के साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता का कारण हैं। गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है और कौन इसे संचालित कर रहा है, सरकार के पास इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है।

भारत-नेपाल सीमा से लगे सीमावर्ती जिलों और पश्चिमी उग्र में जिस तेजी से अवैध मदरसे खुले हैं वह लंबे समय से उग्र सरकार की परेशानी का कारण रहे हैं। गोरखपुर के सांसद रहते योगी आदित्यनाथ भारत-नेपाल सीमावर्ती जिलों में खुलने वाले अवैध मदरसों को लेकर लंबे समय से सवाल उठाते आए हैं। बीते अगस्त माह में उग्र

अवैध मदरसों पर सरली



स्लीपिंग मॉड्यूल ने मदरसों को बनाया ठिकाना

इसी साल मार्च में एटीएस ने देवबंद से 19 साल के इनामुल हक को अरेस्ट किया, जो एक मदरसे के हॉस्टल में रह रहा था। मूलरूप से झारखंड के रहने वाले इनामुल पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने की योजना बनाने का आरोप था। कुछ साल पहले दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी एजाज शेख ने भी खुलासा किया था कि उसके तीन आतंकी साथी देवबंद में छात्र के रूप में रह रहे थे, जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। आईबी के इनपुट के अनुसार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन और इंडियन मुजाहिद्दीन की पश्चिमी उग्र तथा पूर्वांचल के कई जिलों में गहरी पैठ है। कई स्लीपिंग मॉड्यूल मदरसों को अपना ठिकाना बनाकर तालीम की आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मदरसों को आतंक का गढ़ बनाने की शुरुआत प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी ने की थी। अलीगढ़ से शुरू हुए इस संगठन ने इस्लामिक गतिविधियों की आड़ में मदरसों को टारगेट किया और दीनी तालीम के नाम पर आतंक का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया।

एटीएस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को कानपुर से गिरफ्तार किया था। जांच में सैफुल्लाह का लिंक इटावा के मदरसा अरबिया कुरानिया से मिला, जहां से उसने मार्च 2020 तक हिफ्ज की पढ़ाई की थी।

सहारनपुर से आतंकी नदीम की गिरफ्तारी हुई थी, उसी की निशानदेही पर सैफुल्लाह पकड़ा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि सैफुल्लाह आईएसआई के इशारे पर मदरसे में रहकर उग्र-

उत्तराखंड का नया मॉड्यूल तैयार कर बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। सहारनपुर का दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक दीनी तालीम के लिए दुनियाभर में विख्यात है। दारुल उलूम इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र है। इसके अलावा भी कई मदरसे यहां दीनी तालीम देते हैं, लेकिन बीते एक दशक में देवबंद के मदरसे आतंकी तैयार करने वाले केंद्र के रूप में कुख्यात हो चुके हैं।

एटीएस द्वारा पिछले सालों में पकड़े गए कई आतंकियों के देवबंद कनेक्शन मिल चुके हैं। फरवरी 2019 में पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शाहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ था कि यह देवबंद में तालीम लेने के बहाने पहुंचे थे और दहशतगर्द तैयार करने के काम में जुट गए। इन्हें पुलवामा हमले की जानकारी पहले से थी। दिसंबर 2018 में एनआईए ने अमरोहा में इस्लामिक स्टेट के नए मॉड्यूल हरकत उल-हर्ब-ए-इस्लाम का पर्दाफाश करते हुए 13 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया, जिनमें से ज्यादातर ने देवबंद के मदरसों में रहकर दीनी तालीम हासिल की थी। 2017 में मुजफ्फनगर से आतंकी संगठन अंसारुल्ला बांग्ला टीम का सक्रिय सदस्य अब्दुला अल मामून हो या फिर बंगाल पुलिस द्वारा दिल्ली से पकड़ा गया रजाउल रहमान, या फिर एटीएस द्वारा लखनऊ से पकड़े गए इमरान, रजीमुद्दीन, मोहम्मद फिरदौस, सभी का कनेक्शन देवबंद से किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ था। दिसंबर 2020 में प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य अब्दुला दानिश को दिल्ली पुलिस एवं उग्र एटीएस की टीम ने अलीगढ़ से पकड़ा। उसके ऊपर 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम ब्लॉस्ट की साजिश में शामिल होने का आरोप था। अब्दुला का आजमगढ़ में जामिया-तुल-फलाह मदरसा का लिंक सामने आया।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

सबको मालूम है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और उनके निशाने पर क्या है। बीते महीने बिहार में पार्टनर बदलकर उनके गैर भाजपाई सरकार का सरदार बन जाने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अब तक वो स्वयं

बार-बार ज्ञात तथ्य से इनकार किए जा रहे हैं कि वह विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देना चाहते हैं। दिल्ली दौरे के क्रम में वह गत दिनों पुराने साथी सीताराम येचुरी से मिलने दिल्ली के गोल मार्केट स्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय दफ्तर एके गोपालन भवन पहुंचे। बाहर निकलते वक्त पत्रकारों ने जब उनसे फिर पूछा कि क्या वह 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने बड़ी मासूमियत से इनकार किया, मैं कोई दावेदार नहीं हूँ। मेरी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लंबी मुलाकात कर आए थे। बैठक में मनीष सिसौदिया भी मौजूद थे जिन पर शराब नीति में घोटाले का आरोप है। विपक्ष को एकसूत्र में पिरोने के लिए निकले नीतीश कुमार को दिक्कत यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल सरकार पर भाजपा की तरह ही कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। ऐसे में वो केजरीवाल और कांग्रेस को एक साथ कैसे साधेंगे?

जहां तक केजरीवाल की बात है तो आप नेता केजरीवाल विपक्ष में एकला चलो की राह पर चलते हैं। भाजपा की तरह ही उनकी राजनीति भी गैरकांग्रेसवाद पर टिकी है। दिल्ली के बाद पंजाब में कांग्रेस को ही हराकर उन्होंने आप की सरकार बनाई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनाव में वह विपक्ष की कुर्सी से कांग्रेस पार्टी को बेदखल करने पर आमादा हैं। इस काम में बाकी विपक्षी दलों जैसा न तो उनमें भाजपा कार्यकर्ताओं से कोई खुला बैर है और न ही वह आरएसएस के खिलाफ कभी कोई बदजुबानी करते हैं। बल्कि अपनी जनसभाओं में भाजपा कार्यकर्ताओं से आप ज्वाइन करने का आह्वान करते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस उनको भाजपा की बी टीम कहकर संबोधित करती है। ऐसे में कांग्रेस के समर्थन से आगे बढ़ रहे नीतीश कुमार के लिए केजरीवाल सरीखे नेता को साथ पाना आसान काम नहीं है।

नीतीश कुमार का 'मिशन दिल्ली'



गैर भाजपा दलों को एकजुट करने की कवायद

अब भाजपा के साथ होने से हुए बौनेपन के अहसास को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से भाजपा विरोध का बीड़ा उठाया है। इस बार इसके लिए उनको हाशिए पर लगातार धकेली जा रही कांग्रेस पार्टी से खास मैडेट मिलने की बात कही जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के दिनों में भाजपा ने कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए गैर कांग्रेसी दलों को गोलबंद किया था। इसके लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का बीड़ा समाजवादी नेता जार्ज फर्नांडिस के कंधे पर दिया गया। ठीक उसी तरह की जिम्मेदारी फर्नांडिस के कथित शिष्य नीतीश कुमार की गैर भाजपा दलों को एकत्रित करने के लिए है। उनके प्रयास से भविष्य में संभव है कि संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन (यूपीए) के संयोजक की जिम्मेदारी उनको मिल जाए। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर जदयू के एक बड़े नेता बताते हैं कि बिहार में पाला बदलने से ऐन पहले नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आशवासन लेने के क्रम में फोन पर बात हुई थी। तब बात-बात में नीतीश कुमार ने दिल्ली में विपक्षी एकता का संयोजक बनने की इच्छा जताई थी। इसे लेकर कांग्रेस आश्वस्त हुई कि नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की दौड़ में राहुल गांधी के लिए चुनौती नहीं बनेंगे। लिहाजा, बिहार में उनको समर्थन देने में कोई हर्ज नहीं है। इधर विपक्षी एकता के लिए दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री की सक्रियता बढ़ने का सीधा लाभ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिलना है। इसी लाभ की उम्मीद में ही बिहार में फिर से नीतीश कुमार और लालू परिवार का गठबंधन बना है।

केजरीवाल स्वयं विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने की चाहत लिए हुए हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात से एक दिन पहले केजरीवाल चेन्नई के बहुचर्चित दौरे पर थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से उनकी बढ़ती करीबी विपक्ष की राजनीति में नया ध्रुव तैयार कर सकता है। हालांकि केजरीवाल से नीतीश कुमार का संबंध काफी पुराना है। आम आदमी पार्टी के गठन के दिनों में बिहार में जनता दल यू को आरंभिक झटका लगा था। 2014 में नीतीश सरकार में साफ छवि वाली मंत्री परवीन अमानुल्लाह ने एक झटके में इस्तीफा देकर आप ज्वाइन कर लिया था। इसे लेकर दोनों दलों में सुलह मशविरा हुआ। भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए अपने-अपने इलाके में बने रहने पर सहमति हुई। आप ने अपनी नेता परवीन अमानुल्लाह को पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़वाने और हरवाने के बाद बिहार में पार्टी के विस्तार के सभी कार्यक्रम पर रोक लगा दी।

बहरहाल नीतीश कुमार ने बहुचर्चित तीन दिवसीय दिल्ली दौरे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आप नेता केजरीवाल और सीपीएम महासचिव येचुरी के अलावा सीपीआई महासचिव डी.राजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व आरजेडी नेता शरद यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और आईएनएलडी प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला से दनादन मुलाकातों की हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से फोन पर बात की है। उनके इस दौरे में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। नीतीश कुमार के लिए यह काम नया नहीं है। ऐसी कोशिश उन्होंने 2013-14 में की थी। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के मुताबिक इस बार की रणनीति पिछली बार की गलतियों से मिले अनुभव के सीख पर आधारित है। इसके लिए जदयू ने पर्याप्त होमवर्क किया है। बीते लोकसभा चुनाव यानी 2019 में नीतीश कुमार भाजपा के पाले में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनसभाएं कर रहे थे। बदले में भाजपा ने उनको बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का चेहरा बनाए रखा। आज जिस तरह की भूमिका में नीतीश कुमार निकले हैं, ठीक उसी तरह 2019 में आंध्रप्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू भाजपा के खिलाफ सक्रिय थे। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद दिल्ली में डेरा जमाए रखते थे।

● विनोद बक्सरी

अतत: 28 महीने के लंबे तनाव और सैनिक अधिकारियों की बातचीत के 16 दौर के बाद भारत और चीन के बीच इस पर सहमति बनी कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा-हाट स्प्रिंग्स क्षेत्र में युद्ध की मुद्रा में डटी दोनों देशों की सेनाओं को वहां से हटा लिया जाए। ऐसा कर भी लिया गया। लद्दाख के इस क्षेत्र को पेट्रोल प्वाइंट-15 यानी 'पीपी-15' के नाम से जाना जाता है, जिस पर नियंत्रण को लेकर भारत और चीन की सेनाएं मई 2020 से एक-दूसरे के सामने खड़ी थीं। इस सहमति का लक्ष्य दोनों ओर के सैनिकों को अपने-अपने नियंत्रण वाले इलाके में पीछे भेजना और तनाव के दौरान खड़े किए गए सैन्य ढांचे को नष्ट करके दो से चार किमी चौड़ा ऐसा क्षेत्र बनाना है, जो बफर जोन यानी असैन्य क्षेत्र का काम करे।

इसका मतलब यह नहीं कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में चला आ रहा सैनिक तनाव अब खत्म हो गया है और अब 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का प्रीत राग शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलाकों में चीन की आक्रामकता अभी बरकरार है। पीपी-15 को लेकर बनी सहमति से पहले भारत-चीन में गलवन घाटी, पेंगांग-त्सो और गोगरा के पीपी-17ए के तीन स्थानों पर पैदा हुए सैनिक विवादों में सहमति हो चुकी है, लेकिन इन चार स्थानों पर सहमति के बावजूद दौलत बेग ओल्डी के देपसांग और डेमचोक सेक्टर के चार्डिंग नाला जंक्शन में चीन की आक्रामक कार्रवाई से पैदा हुए विवाद को अभी हल किया जाना बाकी है।

यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर वह चीनी सेना, जो दशकों से लद्दाख के भारतीय इलाकों पर गुपचुप कब्जा कर वहां जमे रहने की आदत बना चुकी थी, इस बार मई 2020 के बाद कब्जाए गए इलाकों को एक के बाद एक क्यों खाली कर रही है? इसका जवाब उन तीन बिंदुओं में है, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला बिंदु तो यह है कि चीनी राष्ट्रपति जैसे घरेलू राजनीतिक संकट में घिरे हुए हैं, उसमें भारत से हेकड़ी दिखाना उनके लिए बहुत महंगा सिद्ध हो सकता है। गलवन कांड और लद्दाख के दूसरे इलाकों में सैनिक कार्रवाई करते हुए शी को पूरी उम्मीद थी कि भारतीय सेना चीनी सेना के सामने टिक नहीं पाएगी और गलवन पर नियंत्रण पाने के बाद वह दौलत बेग ओल्डी के साथ सियाचिन पर भी कब्जा जमा लेंगे। इस तरह कराकोरम हाईवे को भारतीय सेना के खतरे से स्थाई निजात दिलाकर वह चीन में हीरो बनकर उभरेंगे। इस हीरोगीरी के बाद आजीवन राष्ट्रपति बनने और सर्वोच्च नेता हो जाने का उनका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन चीनी कांग्रेस के आगामी अधिवेशन को करीब आते देख, उन्हें इसी में गनीमत लगी कि लद्दाख के तनाव को ठंडा



चीन से सावधान रहना होगा

शंघाई सहयोग संगठन कितना सार्थक

उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन बीते दिनों चर्चा में रहा। उसकी सबसे खास झलकियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात बड़ी खास रही। उसमें मोदी ने पुतिन से कहा कि 'यह युद्ध का युग नहीं है!' प्रधानमंत्री का संकेत यूक्रेन को लेकर था। हालांकि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही नई दिल्ली का यही रुख है, लेकिन मोदी का सार्वजनिक रूप से इसे रेखांकित करना यह दर्शाता है कि रूस के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं और यह उसकी योजनाओं के अनुरूप दिशा में नहीं जा रहा। यूक्रेन युद्ध को लेकर न केवल भारत, बल्कि चीन की असहजता भी स्पष्ट दिखती है। स्वयं पुतिन यह स्वीकारोक्ति करते दिखे कि वह यूक्रेन युद्ध के मसले पर चीन के 'सवालों और चिंता' को समझते हैं, वह भी तब जबकि चीन ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा।

करके भारत से टकराव को मुद्दा न बनने दिया जाए। शी की दूसरी चिंता यह थी कि अगर सैनिक टकराव के कारण शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में कोई बड़ी अड़चन आती है तो उनकी भद पिटेंगी। साफ है कि भारत के साथ तनाव कम करना बहुत जरूरी हो चुका था। शी इसे लेकर पहले ही सदमें में थे कि चीन की गीदड़ भभकियों के आगे हर बार डर जाने वाली भारतीय सरकारों की परंपरा को मोदी ने पलट डाला। भारत की सेना ने न केवल चीनी सेना को लद्दाख के मोर्चे पर कड़ा जवाब दिया, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया के लगभग हर मंच पर यह कहकर चीन की फजीहत की कि जब तक वह अपनी सेनाएं पहले की स्थिति में नहीं ले जाता, तब तक भारत उसके साथ दूसरे किसी विषय पर बात नहीं करेगा। इसके चलते चीनी राष्ट्रपति को यह चिंता भी

सताने लगी थी कि उसके नेतृत्व वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में यदि प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लेने से मना कर दिया तो उनकी बहुत किरकिरी होगी। शायद इसलिए 17 जुलाई की 16वीं कोर कमान्डर बैठक के दो महीने बाद चीन को अचानक पीपी-15 पर सहमति बनाने की याद आई। चीन को रास्ते पर लाने वाला तीसरा बिंदु यह है कि गलवन कांड के बाद भारत ने जिस फुर्ती के साथ विश्व स्तर पर चीन के खिलाफ कूटनीतिक और सैनिक किलेबंदी शुरू की, उसने उसके लिए नई परेशानी पैदा कर दी थी।

अमेरिका की पहल पर क्वाड को फिर से सक्रिय करने के अभियान में भागीदारी के साथ भारत ने जापान, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और फिलिपींस समेत ऐसे कई देशों से अपने आर्थिक और सैनिक संबंध सुधारने का जो अभियान शुरू किया, उसने भी चीन की परेशानी बढ़ाई। भारत की इन देशों को नेतृत्व दे पाने की क्षमता को देखते हुए भी शी जिनपिंग को भारत का महत्व समझ आने लगा था। पीपी-15 पर समझौता यकीनन चीन के साथ सैनिक तनाव कम करने में उपयोगी है, क्योंकि आने वाले 5-10 साल भारत के लिए आर्थिक और सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ताजा सहमति का स्वागत करते हुए चीन की पुरानी करतूतों को भुलाना महंगा पड़ सकता है। हमारे नीति निर्माताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन के सभी फैसले तत्कालीन कठिनाई से निकलने और दीर्घकालीन फायदे पर केंद्रित रहते हैं और उनमें समझौतों के प्रति ईमानदारी या नैतिक जिम्मेदारी का लेशमात्र भी स्थान नहीं होता। मौके के मुताबिक पुरानी संधियों को कूड़ेदान में डालना चीन की आदत है। यह एक तथ्य है कि अकेले लद्दाख मोर्चे पर आज भी चीन के 60 हजार सैनिक तैनात हैं, जो कभी भी उसकी मंशा को बदल सकते हैं।

● ऋतेन्द्र माथुर

क्या ऋषि सुनक भारतीय मूल के नहीं होते, तो अपनी योग्यता के बूते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए होते? बहुत-से हलकों में यह सवाल रहे हैं कि रंगभेद ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच दीवार बन गया। सुनक या उनके समर्थकों ने अपनी हार से पहले या बाद में भले ऐसी कोई बात नहीं की; लेकिन जिस तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सुनक के खिलाफ कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर अभियान चलाया, रंगभेद समर्थक नेताओं को विरोध के लिए आगे किया और सुनक की छवि बिगाड़ने की कोशिश की, उससे सुनक की हार में रंगभेद को एक कारण मानने वालों की कमी नहीं है।

भारतीय मूल के उद्यमी और कंजरवेटिव पार्टी के दानदाता लॉर्ड रामी रोजर ने तो सितंबर के शुरू में ही एक वीडियो जारी करके कहा था कि अगर ऋषि सुनक चुनाव हार जाते हैं, तो ब्रिटेन को रंगभेदी देश के रूप देखा जा सकता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि यह आम चुनाव नहीं था, बल्कि सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी (ब्रिटेन की कुल आबादी का महज 0.25 फीसदी) के भीतर का चुनाव था। आम चुनाव होते, तो शायद लिज पर सुनक भारी पड़ते। वैसे लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच मुकाबला कड़ा रहा। दोनों में 20,927 वोटों का अंतर रहा। कंजर्वेटिव सांसदों की वोटिंग में सुनक शीर्ष पर बने हुए थे; लेकिन बाद में प्रतिनिधि समर्थन में वह पिछड़ गए। एक सर्वे कंपनी यूगोव ने अपने एक सर्वे में दावा किया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में स्विंग वोटर्स के बीच ऋषि सुनक ज्यादा लोकप्रिय हैं। सर्वे के मुताबिक, सुनक ऐसे मतदाताओं के बीच पसंदीदा हैं, जिन्होंने सन् 2019 के आम चुनाव में पहली बार कंजरवेटिव पार्टी को वोट दिया था।

हैरानी की बात है कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद लिज के हक में नहीं थे। सर्वे में हिस्सा लेने वाले गैर-कंजर्वेटिव लोग कह रहे थे कि लिज सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगी। ऋषि पार्टी सांसदों की पहली पसंद थे। हर सांसद उनकी काबिलियत से वाकिफ था। इसके बावजूद सुनक महंगाई कम करने और टैक्स रिलीफ के मुद्दों पर अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे। यह समझदार नेता की पहचान है। इसके बावजूद लिज जीत गईं। सुनक टोरी सदस्यों के बीच मतदान के दौरान प्रतिद्वंद्वी ट्रस से पिछड़ गए। मागरिट थैचर और टेरेसा मे के बाद लिज ट्रस (47) ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को जब इस्तीफा दिया था, तो उससे पहले उनके खिलाफ इस्तीफा देने वालों में पूर्व चांसलर ऋषि सुनक सबसे पहले नेता थे। जॉनसन इस बात को कभी नहीं भूले और अपने

रंगभेद का शिकार हुए सुनक



ऋषि की गहरी समझ की जरूरत

जीत के बाद अगर लिज के पहले भाषण को गौर से सुनें, तो जाहिर होता है कि ब्यापार और अर्थव्यवस्था के मास्टर कहे जाने वाले ऋषि सुनक की अपनी सत्ता में फायरब्रांड लिज को कितनी जरूरत होगी। लिज ने स्वीकार किया कि उन्हें ऋषि की गहरी समझ की जरूरत होगी। उन्होंने पार्टी में सुनक जैसे नेता के होने को खुशकिस्मती करार दिया। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान लिज ने सुनक की समझदारी पर एक से ज्यादा बार सवाल उठाए थे। उनकी जीत के बाद ब्रिटिश मीडिया में भी अब कहा जा रहा है कि क्या लिज फौरन टैक्स रिलीफ जैसा चुनावी वादा पूरा कर पाएंगी या अगला चुनाव जल्द होगा? चुनाव प्रचार के दौरान चतुर लिज ट्रस ने सुनक की काट बड़ी मुश्किल से खोजी। ब्रिटिश मीडिया में भी इसे लेकर खूब छपा। मशहूर अखबार 'द गार्डियन' ने एक रिपोर्ट में कहा कि सुनक वित्त मंत्री रहे। वह अर्थव्यवस्था की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने पूरे अभियान के दौरान यह साफ कहा कि टैक्स में कमी करने से अर्थव्यवस्था और लोगों के हालात बेहतर नहीं होंगे। इसके लिए दूसरे तरीकों से महंगाई पहले कम करनी होगी। इसके विपरीत ट्रस ने लोकलुभावन वादे किए और कहा कि प्रधानमंत्री बनते ही वह सबसे पहले टैक्स रिलीफ देंगी। महंगाई और गैस की कमी जैसे मुद्दों पर बाद में भी काम किया जा सकता है। सुनक ट्रस की इस अर्थव्यवस्था नीति के सख्त विरोध में बोले और इसे अर्थव्यवस्था को तबाह करने का रास्ता बताया। सुनक बीमारी का स्थायी इलाज खोजने की बात कर रहे थे। लिज ने कुछ वक्त तक इसे काबू में रखने की बात कही। सवाल यही है कि क्या लिज फौरन टैक्स रिलीफ का वादा पूरा कर पाएंगी?

समर्थकों को लगातार सुनक के खिलाफ सक्रिय रखा। जीत के बाद लिज ट्रस ने कहा- 'कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुनी जाने के बाद मुझे गर्व महसूस हो रहा है। देश के नेतृत्व के लिए मुझ पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद। इस मुश्किल समय में देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए मैं साहसिक कदम उठाऊंगी।' उधर ऋषि सुनक ने जीत पर ट्रस को बधाई दी और उनके साथ चलने का सभी कंजर्वेटिव सदस्यों का आह्वान किया। उन्होंने कहा- 'कंजर्वेटिव पार्टी एक परिवार है। अब हम नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस के पीछे एकजुट हैं; क्योंकि वह मुश्किल वक्त में देश की कमान संभालने जा रही हैं।'

लिज ट्रस को पाला बदलने में माहिर माना जाता रहा है। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत में लिज लिबरल डेमोक्रेट थीं और बाद में मौके के अनुसार कंजर्वेटिव हो गईं। यही नहीं, जब लिज कॉलेज में थीं, तो मोनार्की (राजशाही) की जबरदस्त विरोधी थीं। उनके पुराने भाषण इस बात के गवाह हैं। लेकिन बाद में पाला बदलकर लिज बकिंघम पैलेस और शाही खानदान की पक्षधर हो गईं और आखिर महारानी से ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एक और उदाहरण बोरिस जॉनसन के दौर में ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने (ब्रेक्जिट) का मुद्दा है। एक समय यूरोपीय यूनियन में रहने की वकालत करने वाली लिज बाद में ब्रेक्जिट की समर्थन बन गईं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब लिज ट्रस के सामने गंभीर किस्म की चुनौतियां हैं। उन्हें बिना देरी वादा निभाते हुए टैक्स रिलीफ और बिजली बिल में राहत देनी होगी। अर्थव्यवस्था को संतुलित करना होगा, नहीं तो ब्रिटेन को मंदी की चपेट में आने से कोई नहीं रोक पाएगा।

● कुमार विनोद

PRISM[®]
CEMENT

प्रिज़्म[®] चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.



- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको-फ्रेंडली
- कन्सिस्टेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM[®]

**चैम्पियन
सीमेंट**

प्लस

दूर की सोच[®]

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

म गवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से सवाल किया था कि क्या फर्क है निर्गुण और सगुण के उपासना में? कृष्ण ने गीता के अध्याय 12 में 'भक्ति योग' के बारे में बताया है। अर्जुन ने पूछा, 'जो भक्त आपके प्रेम में डूबे रहकर आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं, या फिर जो शाश्वत, अविनाशी और निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है।' भगवान श्रीकृष्ण बोले, 'जो लोग मुझमें अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा और भक्ति करते हैं तथा खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे परम भक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मन-बुद्धि से परे सर्वव्यापी, निराकार की आराधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सशरीर

जीव के लिए उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझमें लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ।'

जो अव्यक्त और निराकार होता है, उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। उसमें आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। चाहे आप निराकार में विश्वास करते हों, फिर भी जो नहीं है, उसके प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को विकसित करते हुए उसे बनाए रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो है, उसकी भक्ति करना आपके लिए ज्यादा आसान है। इसके साथ ही, वह कहते हैं, 'अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति कर सकता है, तो वह भी मुझे पा सकता है।' जब वह 'मैं' कहते हैं, तो वह किसी व्यक्ति के रूप में अपनी बात नहीं करते हैं, वह उस आयाम की बात करते हैं जिसमें साकार और निराकार दोनों शामिल होते हैं। 'यदि कोई वह रास्ता अपनाता है, तो वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है मगर उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी।' क्योंकि जो चीज नहीं है, उसमें मन लगाना आपके लिए मुश्किल है। अपनी भक्ति में लगातार स्थिर होने के लिए आपको एक आकार, एक रूप, एक नाम की जरूरत पड़ती है, जिससे आप जुड़ सकें।

'सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना कठिन है।' इसका मतलब है कि अगर आप शरीर और बुद्धि-विवेक युक्त जीव की तरह, अस्तित्व के एक निराकार आयाम की आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि रोज आपसे पूछेगी कि आप किसी मंजिल की तरफ बढ़ भी रहे हैं या

निर्गुण और सगुण के उपासना में फर्क



यू ही समय बर्बाद कर रहे हैं। जो शरीरहीन जीव हैं, उनके लिए संभावना मौजूद है क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि के साथ तर्क-वितर्क नहीं करना पड़ता- वे अपने झुकाव और प्रवृत्ति के मुताबिक चलते हैं। अगर वे आध्यात्म की तरफ झुके हुए हैं, तो वे आमतौर पर निराकार की ओर उन्मुख हो जाते हैं। यह उनका सोचा-समझा चयन नहीं होता, बल्कि उनका झुकाव होता है। इसलिए, अशरीरी जीवों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त मार्ग है क्योंकि वे पंचतत्वों की सीमाओं से परे होते हैं, बुद्धि और विवेक की सीमाओं से परे होते हैं।

मगर किसी सशरीर जीव के लिए अपनी भावनाओं को किसी ऐसी चीज में लगाना बेहतर होता है, जिससे आप जुड़ सकें। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनका ध्यान करने पर उन्हें प्राप्त करना ज्यादा आसान है। निराकार की खोज आपके भीतर एक दार्शनिक नाटक बन सकता है, जिसमें आप बिना आगे बढ़े वहीं के वहीं अटक रह सकते हैं। 'मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझमें लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूँ।' यह सिर्फ कृष्ण ने नहीं कहा है। हर पूर्ण आत्मज्ञानी जीव किसी न किसी रूप में यही कहता है। जब लोग मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि 'क्या मुझे इस जन्म में मुक्ति मिलेगी?' तो मैं उनसे कहता हूँ, 'आप सिर्फ मेरी बस में चढ़ जाइए। आपको झड़व नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ बस में बैठना है।' मगर आपका अहं ऐसा है, कि आप बस को

चलाना भी चाहते हैं। बहुत से लोग बैकसीट में बैठकर ड्राइविंग करते हैं। आम तौर पर वे सिर्फ ब्रेक लगाते हैं।

अगर आप किसी खास इंसान की मौजूदगी में हैं, तो आखिरी वक्त में आपकी मुक्ति आसान हो जाती है। सवाल यह है कि आप अपने बाकी जीवन को कितनी खूबसूरती से जीते हैं। चाहे आपने मूर्खतापूर्ण जीवन जिया हो, फिर भी किसी खास की मौजूदगी में आपकी चरम मुक्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। बस अपने जीवन के आखिरी पलों में आप सारा काम बिगाड़ न दें। अगर आखिरी पल में भी आपको जरूरी अक्ल नहीं आती है और आप गुस्सा, नफरत या लालसा की भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तो आपका अगला जन्म हो सकता है। वरना, एक बार आप मेरे साथ बैठने की गलती कर लें, तो जब आप मरेंगे तो वह अच्छे के लिए होगा। यहां पर भी वह यही कह

रहे हैं। अंग्रेजी में ये अनुवाद बिल्कुल सटीक नहीं हैं। वास्तव में वह कहते हैं, 'अगर कम से कम एक पल के लिए भी तुम्हारा ध्यान पूरी तरह मुझमें लगा हुआ है, तो तुम मुझे पा लोगे।'

वह अर्जुन से कहते हैं, 'युद्ध के परिणाम की चिंता मत करो। तुम यहां हो। तुम्हें लड़ना है। तुम जीतोगे या नहीं, यह तुम्हारी काबिलियत और बाकी चीजों पर निर्भर करता है। बस लड़ो और अच्छी तरह लड़ो। अगर तुम जीतते हो, तो राज्य का आनंद उठाओ। अगर तुम मर जाते हो, तो मैं तुम्हारा परम कल्याण सुनिश्चित करूंगा।' यहां पर भी वह यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जब बात बाहरी हालात की होती है, तो वह हर चीज सुनिश्चित नहीं कर सकते। आंतरिक हालात में पूरी गारंटी होती है। मगर वह कहते हैं, 'मैं यह पक्का करूंगा कि आपको आगे जन्म न लेना पड़े।' मेरे साथ भी यह सच है। मैं पक्का कर सकता हूँ कि आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े, मगर मैं यह पक्का नहीं कर सकता कि आपको कल नाश्ता मिल जाए। किसी तार्किक दिमाग को यह बात बेतुकी लग सकती है, 'अगर आप इतनी बड़ी चीज सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आप नाश्ता सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकते?' जीवन की हकीकत यही है। मैं आपके लिए कल का नाश्ता पक्का नहीं कर सकता, मगर मैं आपका परम कल्याण सुनिश्चित कर सकता हूँ। जब आंतरिक आयामों की बात आती है, तो मैं उसका पूरा जिम्मा ले सकता हूँ। जब बाहरी हालातों की बात आती है, तो कोई गारंटी नहीं होती, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है।

● ओम



मा नसी की शादी को 8 वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक गोद नहीं भरा। परिवार वाले अब उसे उलाहना देने लगे। पहले तो उसका पति निखिल परिवार वालों का विरोध करता था, लेकिन धीरे-धीरे निखिल भी अपनी मां-पिता की भांति मानसी को जली कटी सुनाने लगा।

1 दिन मानसी ने निखिल से कहा, चलो जरा हम लोग डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लेते हैं, कहीं किसी में कोई कमी तो नहीं। निखिल इस बात से काफी भड़क गया और बोला चलो मुझे पता है कि कमी तुम में ही होगी मुझ में कहीं से नहीं हो सकती। खैर डॉक्टर ने मानसी की जांच तो कर ली, जब निखिल की बारी आई तो उसने कहा मैं क्यों जांच कराऊं, जिस में कमी है उसने तो जांच करवा ली। खैर डॉक्टर ने शाम को रिपोर्ट देने की बात बताई और अंदर चली गई। जैसे ही शाम हुई मानसी डॉक्टर के पास गई और रिपोर्ट मांगी। डॉक्टर ने कहा- मानसी जी आपमें तो कोई कमी है ही नहीं, आप मेडिकली पूरी फिट हैं। लेकिन यह सुनकर मानसी बहुत दुखी हो गई, उसे पता था यह बात उसके पति को काफी दुख पहुंचाएगी। उसने डॉक्टर से कहा कि प्लीज आप रिपोर्ट को चेंज कर दीजिए। काफी जिरह के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट चेंज कर

दिया। मानसी शाम को मुंह बनाकर के अपने परिवार के पास आई और रिपोर्ट दिखा दी। फिर क्या था सब ने उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कि उसकी सास ने तो निखिल की दूसरी शादी तक की बात कर दी, और 1 दिन ऐसा आया जब उसकी दूसरी शादी भी हो गई। निखिल ने मानसी से कहा- तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं तुम कहीं और जगह तलाश करो। स्वाभिमानी मानसी ने घर छोड़ दिया काफी कोशिश के बाद उसे एक सरकारी कार्यालय में काम मिल गया।

करीब 10 वर्षों के बाद निखिल की मुलाकात एक बार फिर मानसी से हुई। निखिल मानसी से कुछ कहता तब तक एक बच्चा दौड़ता हुआ मानसी के पास आया और कहा मम्मी जल्दी चलो पापा ने तुम्हें बुलाया है। अब निखिल को इस बात का अहसास हुआ कि जिसे उसने बाँझ कहकर घर से निकाला था दरअसल वो पूर्णतया ठीक थी कमी तो निखिल में थी तभी तो दूसरी शादी के उपरांत भी वह बाप नहीं बन पाया। निखिल अपराध बोध से ग्रसित दौड़कर मानसी के पास जाना चाहा उससे माफी मांगी चाही लेकिन तब तक मानसी अपने बच्चे और पति के साथ वहां से रवाना हो चुकी थी।

- सविता सिंह हर्षिता

लहराया में आसमान में



लहराया में आसमान में,
मानव बहक गया।

मेरी छाया में सौगंधें,
खाकर करता वादे,
मुंह में राम बगल में छूरी,
नेक न रहे इरादे,
लोकतंत्र को गाली,
कंधे टांग दुनाली,
आंगन महक गया।

छांव तिरंगे की वह सोता,
देश समूचा कुनबा,
अंधे बांट रहे रेवड़ियां,
ढूँढ़ रहा घर पुरबा,
पहन भक्त का चोला,
हर ओर देश में डोला,
दानव लहक गया।

गंगा, गाय, तिरंगा, जपता,
उल्लू सीधा करता,
परदे में गो-मांस चीरता,
नहीं राम से डरता,
कैसी यह आजादी,
तन आंखों में वादी,
आनन चहक गया।

- डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'

चा रों तरफ प्लास्टिक की छोटी-छोटी बोतलें पड़ी हैं। थर्माकोल की प्लेट और ग्लासेस भी। बीच-बीच में झूठा खाना बिखरा है। भिन-भिन करते मच्छर। भौंकते श्वान। पत्तल से बोतले उठाते, कोल्ड ड्रिंक का बचा कूचा घूंट बड़े मजे से पीते, कचरे से पेट की आग बुझाते बच्चे। मटमैले कपड़े। बदहाल जिंदगी। जानवरों से बदतर। राज कब से देख रहा था। सोच रहा था, अमर चाचा जैसे किसी पालनहार की नजर पड़ जाए तो इन अभागों की भी संवर जाएगी जिंदगी। और किसी गलत व्यक्ति की बातों में आकर गलत संगत में आ गए तो बर्बाद हो जाती जिंदगी। राज को अमर चाचा ने गोद लिया है। अगर अमर चाचा उसे अपना न मानते, वह भी आज चोरी छिपे नशे की दवाइयां बेच रहा होता या शराब की बोतल

संकल्प!



गंतव्य पर पहुंचाता होता। पांच-दस रुपयों के लिए झुग्गी-झोपड़ियों में बच्चे छोटा-बड़ा कुछ भी काम कर लेते हैं। अमर चाचा उससे काम करवाते हैं, पर दुकान में। व्यापार के गुरु भी सिखाते हैं। पढ़ाई के लिए ट्यूशन भी लगाया है। अच्छा ईसान, बड़ा आदमी बन अमर चाचा को खूब खुशियां देगा वह। इन अनाथ बेघर बच्चों के लिए भी घर जैसा आश्रम बनवाएगा। खूब पढ़ाएगा। अमर चाचा पुकार रहे थे, चलो, देर हो रही है। मन ही मन ठान लिया था उसने, शाम को बच्चों से मिलने जरूर आऊंगा। उनकी भी जिंदगी संवर जाए, कोशिश करूंगा। दृढ़ संकल्प करते हुए राज अमर चाचा के साथ चल दिया। प्रभु परमात्मा से अर्चना करते हुए, हे प्रभु, अमर चाचा जैसे देवदूत धरती पर भेजते रहिए।

ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से करीब एक महीने पहले मेजबान टीम के खिलाफ मैच में टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। माना जा रहा था कि एशिया कप में बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैचों की घरेलू सीरीज में टीम इंडिया अपनी गलतियों को सुधार लेगी। लेकिन, पहले ही टी20 मैच में टीम इंडिया के शेरों ने ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक दिए। वैसे, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 208 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। इसके बावजूद गेंदबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते मैच नहीं बचाया जा सका। ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन की 61 रनों की अर्धशतकीय पारी और मैथ्यू वेड की 21 गेंद में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। फील्डिंग के मामले में भी टीम इंडिया का हाथ तंग रहा। और, टीम ने मैच में तीन कैच टपकाए। इस स्थिति में सवाल उठना लाजिमी है कि ऐसे प्रदर्शन के साथ टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप कैसे जीतेगी?

बीते दिनों टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने टीम में हीरो कल्चर को लेकर सवाल खड़े किए थे। गौतम गंभीर ने कहा था कि टीम में मॉन्सटर मत तैयार कीजिए। किसी खिलाड़ी को नहीं केवल भारतीय क्रिकेट को मॉन्सटर होना चाहिए। किसी को पूजने की वजह से अन्य खिलाड़ियों के मौके खत्म हो जाते हैं। इसकी परछाईं में कोई आगे नहीं बढ़ता है। टीम इंडिया में पहले महेंद्र सिंह धोनी और अब विराट कोहली के साथ यही किया जा रहा है। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया-अफगानिस्तान के मैच का उदाहरण देते हुए कहा था कि जब विराट कोहली ने शतक बनाया, तब किसी ने भुवनेश्वर कुमार के पांच विकेट लेने पर चर्चा नहीं की। हमें इस हीरो कल्चर को बंद करना होगा।

हालिया मैच के नतीजे पर गौर किया जाए, तो गौतम गंभीर की बात सौ फीसदी खरी साबित होती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज विराट कोहली बुरी तरह से फ्लॉप रहे। और, रोहित-विराट की ये जोड़ी टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाजों में शामिल है। एशिया कप के दौरान विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब मैंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी, तो मुझे केवल महेंद्र सिंह धोनी ने मैसेज किया था। ये दिखाने के लिए काफी है कि टीम इंडिया का ये स्टार बल्लेबाज अभी तक हीरो कल्चर को पीछे नहीं छोड़ सका है। वहीं, रोहित शर्मा की बात की जाए, तो ऐसा लगता है कि उन पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा कर लिया गया है। रोहित पर कप्तानी के साथ प्रदर्शन करने का दबाव साफ

छोड़ना होगा हीरो कल्चर



इधर कैच छूटा और उधर मैच छूटा

क्रिकेट में कहा जाता है कि इधर कैच छूटा और उधर मैच छूटा। वैसे, टीम इंडिया बेहतरीन फील्डिंग के लिए जानी जाती है। लेकिन, इस मैच में खिलाड़ियों ने बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया ने मैच में एक या दो नहीं बल्कि तीन कैच छोड़ दिए। इनमें से तीसरा कैच ऐसे मौके पर छूटा, जो मैच का रुख बदल सकता था। 18वें ओवर में टीम इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले मैथ्यू वेड का कैच हर्षल पटेल ने छोड़ दिया। उससे पहले अक्षर पटेल ने 8वें ओवर में कैमरून ग्रीन और 9वें ओवर में केएल राहुल ने स्टीव स्मिथ का कैच छोड़ जीवनदान दिया।

नजर आता है।

वैसे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली के सस्ते में आउट होने के पीछे प्रदर्शन का दबाव एक बड़ी वजह होगी। क्योंकि, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने इसी मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन, ये विडंबना ही है कि इन खिलाड़ियों पर चर्चा की जगह विराट कोहली और रोहित शर्मा पर बात की जा रही है। दरअसल, रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए अच्छा प्रदर्शन करना है। और, विराट कोहली को कप्तानी छोड़कर अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना है। लेकिन, दोनों खिलाड़ियों के बीच इन सबसे इतर एक अलग तरह की राजनीति नजर आती है। जिसका हल इन दोनों खिलाड़ियों को ही खोजना होगा।

इससे इतर रोहित शर्मा का व्यवहार मैदान पर अजीब सा नजर आता है। जहां महेंद्र सिंह धोनी

कप्तानी के दौरान कैप्टन कूल और विराट कोहली कप्तानी के दौरान आक्रामक रवैया अपनाते थे। वहीं, रोहित शर्मा की कप्तानी में कुछ ज्यादा ही आक्रामकता दिखाई पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में तो रोहित ने बीच मैदान ही अपना पारा खो दिया। और, दिनेश कार्तिक का गला पकड़ लिया। हालांकि, ये बात मजाक में आई-गई हो गई। लेकिन, रोहित शर्मा को ऐसे व्यवहार से छुटकारा पाना होगा। माना कि गलती दिनेश कार्तिक की थी। और, कार्तिक ने मैच के दौरान नजदीकी मामलों पर अपील नहीं की। लेकिन, इसकी वजह से रोहित का गुस्सा इस तरह से मैदान पर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए था।

एशिया कप से बाहर होने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की उनके प्रयोगों को लेकर जमकर आलोचना हुई थी। क्योंकि, एशिया कप रोहित शर्मा के इन्हीं प्रयोगों की भेंट चढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले ही मैच में रोहित शर्मा ने फिर से एक बेहतरीन प्रयोग कर डाला। मोहाली की हाई स्कोरिंग पिच पर रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को बेंच पर बैठाए रखा। और, उनकी जगह उमेश यादव को टीम में जगह दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में छह गेंदबाज थे। जिनमें से केवल अक्षर पटेल ही बेहतरीन गेंदबाजी कर सके। और, 4.20 की इकोनॉमी से महज 17 रन देकर तीन विकेट भी लिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बाकी के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 52, उमेश यादव ने दो ओवर में 27, युजवेंद्र चहल ने 3.2 ओवर में एक विकेट लेकर 42, हर्षल पटेल ने चार ओवर में 49 और हार्दिक पांड्या ने दो ओवर में 22 रन लुटाए।

● आशीष नेमा



पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। राजू को 10 अगस्त को जिम करते हुए हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान राजू की हालत स्थिर हुई, लेकिन फिर बिगड़ गई। एक महीने से ज्यादा समय तक वैटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार कॉमेडियन ने दम तोड़ दिया।

अमिताभ की दीवार देख हीरो बनने मुंबई आए थे राजू श्रीवास्तव



सूटिंग के दिनों में बने ऑटो ड्राइवर, सवारी ने ही दिलाया था इंडस्ट्री में पहला काम

राजू श्रीवास्तव देश के सबसे पॉपुलर और पसंदीदा कॉमेडियन में से एक थे। कभी इन्होंने रियलिटी शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर लोगों को गुदगुदाया, तो कहीं फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन किया। राजू भले ही एक सफल सेलेब रहे, लेकिन इनका शुरुआती कैरियर उतार-चढ़ाव भरा रहा।



राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन में इन्हें सत्य प्रकाश नाम मिला था, जो आगे जाकर राजू श्रीवास्तव बन गए। इनके पिता रमेश चंद्र

श्रीवास्तव एक सरकारी कर्मचारी थे और शौकिया तौर पर कविताएं लिखा करते थे। छुट्टियों में पिता कवि सम्मेलन का हिस्सा बना करते थे, जिन्हें बलाई काका नाम से पहचाना जाता था। पिता से राजू को भी लोगों का मनोरंजन करने का गुर विरासत में मिला। बचपन से ही राजू घर आए मेहमानों के सामने मिमिक्री करते और स्कूल में टीचर की भी नकल उतारकर लोगों को खूब हंसाते। कई टीचर उन्हें बदतमीज कहते हुए सजा देते थे, लेकिन एक टीचर ऐसे भी थे जिन्होंने इन्हें बढ़ावा दिया और कॉमेडी में कैरियर बनाने की सलाह दी। लोगों ने राजू को लोकल क्रिकेट मैच में कमेंट्री करने की सलाह दी। इससे ये अपने हुनर को कॉन्फिडेंट के साथ लोगों के सामने पेश करने लगे। ये बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे, लेकिन असल में इनकी प्रेरणा अमिताभ बच्चन थे। बिग बी की फिल्म दीवार देखने के बाद राजू ने एक्टर बनने का फैसला किया।



कॉमेडियन बनने का सपना लेकर पहुंचे थे मुंबई
राजू बचपन से ही एक्टिंग और कॉमेडी में हाथ आजमाना चाहते थे, जिसके लिए वो 1982 में लखनऊ छोड़कर सपनों के शहर मुंबई चले आए। यहां ना रहने को घर था ना खाने के पैसे। घर से भेजे गए पैसे जब कम पड़ने लगे तो राजू ऑटो ड्राइवर बन गए। राजू अपनी सवारी को भी हंसाते थे। मुंबई में राजू को करीब 4-5 सालों तक संघर्ष करना पड़ा था।

सवारी ने दिलाया था कॉमेडी में पहला ब्रेक

एक दिन एक सवारी ने राजू के स्टाइल से इंप्रेस होकर उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस देने को कहा। राजू मान गए और परफॉर्मेंस दी, जिसके लिए सिर्फ 50 रुपए मिले थे। इसके बाद राजू लगातार स्टेज शो करने लगे।



अमिताभ बच्चन की तरह दिखने पर मिली पहचान



स्टेज शो करते हुए राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की भी नकल उतारा करते थे। यहीं से लोगों ने उनके लुक की तुलना अमिताभ बच्चन से करना शुरू कर दी।



कैसे बने गजोधर भइया... राजू श्रीवास्तव का घर उन्नाव के बीघापुर गांव में था। राजू बचपन में मामा के घर जाया करते थे। उस समय बाल कटवाने एक नाई के पास जाया करते थे जिसका नाम गजोधर था। उस नाई के सीने में गिटार का टैटू था। वो कहता था कि जब सीने में खुजली करता हूं तो गिटार बजता है। वो नाई इतना मजाकिया था कि राजू की जुबान पर सालों तक उसका नाम रहा। जब वो कॉमेडियन बने तो राजू ने उसके नाम का इस्तेमाल किया।

गोध से मालूम हुआ कि दरअसल देश को अब लोकपाल जी की जरूरत ही नहीं थी। केवल कुर्सियां बदल जाने भर से ही भ्रष्टाचार भय से कांपने लगा था। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। भ्रष्टाचार के यूँ एकदम से गायब हो जाने के बाद बेचारी ईमानदारी अकेली रह गई।

बात उन दिनों की है जब देश क्रांति की चपेट में था। सड़कों पर बेरोक-टोक क्रांति बह रही थी। गड्डे भी क्रांति से पट गए थे। वे सड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुक्त हो जाने को तैयार थे। भ्रष्टाचार था कि कुंडली मारकर ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। आम परेशान था कि खास की सारी सप्लाई-लाइन कैसे रोकी जाए! ऐसे कठिन समय में क्रांति कुमार अवतरित हुए। आम और अवाम एक हो गए। जल्द ही अंधेरा छंट गया।

कुर्सी दिखने लगी। उनकी सहयात्री ईमानदारी भ्रष्टाचार से मिलने को आतुर हो उठी, जिससे वह उसका गला दबा सके, पर इसमें एक मुश्किल थी। वह हवाई चप्पल से बंधी हुई थी। कुर्सी उसकी पकड़ से बहुत दूर थी। वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक मजबूत जूते की दरकार थी। उसने इधर-उधर से कई आरोप इकट्ठे किए। उन्हीं को जूता बनाकर नियमित रूप से उछालना शुरू कर दिया। दिन में दस बार लोकपाल का मंत्रजाप भी शुरू हो गया। राजपथ जनपथ में बदल गया। देखते-ही-देखते बदलाव की आग लग गई।

कुर्सी का फर्नीचर पुराना था, सुलग उठा। क्रांति की ताप से भ्रष्टाचार भाग खड़ा हुआ। अभी आरोप हवा में ही तैर रहे थे, पर कुर्सी उनकी जद में आ गई। ईमानदारी के साथ वे कुर्सी पर बैठ गए। वह चारों तरफ पसरना चाहते थे, पर कुर्सी में लगे दो हथैले उनकी इस राह का रोड़ा बन गए। उन्होंने एक झटके में लात मारकर दोनों हथैले उखाड़ फेंके। यह काम इतनी कुशलता से किया गया कि लोकतंत्र को तनिक भी चोट नहीं पहुंची। पूरी पारदर्शिता के साथ उन्होंने अपना मुक्ति-पथ साफ किया। इसके बाद वह सुकून से फैल गए और लोकपाल को एक गठरी में बांधकर रख दिया, ताकि वे प्रदूषित हवा-पानी के संसर्ग से बचे रहें। देश के आम और खास लोकपाल जी का नाम तक भूल गए।

शोध से मालूम हुआ कि दरअसल देश को अब लोकपाल जी की जरूरत ही नहीं थी। केवल कुर्सियां बदल जाने भर से ही भ्रष्टाचार भय से कांपने लगा था। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। भ्रष्टाचार के यूँ एकदम से गायब हो जाने के बाद बेचारी ईमानदारी अकेली रह गई। सरकार का संसर्ग पाकर वह अब कट्टर हो चुकी थी। कट्टरता को लेकर क्रांति कुमार इतने ईमानदार निकले कि देशभक्त भी हुए तो एकदम कट्टर। अब देश में दो तरह के ही देशभक्त पाए जा रहे थे। एक असली, दूसरे कट्टर। इनके अलावा जो

भाग खड़ा हुआ भ्रष्टाचार



भी बचे थे, वे देशद्रोही हो सकते थे या संदिग्ध नागरिक।

देश को तब तक अच्छे दिनों की लत लग चुकी थी। तभी घटनाक्रम में जबरदस्त मोड़ आ गया। आपातकाल से आजिज आए लोगों ने पहले तो भक्तिकाल की घोषणा की, फिर एक-एक कर सबकी निशानदेही शुरू हो गई। महंगाई और बेरोजगारी जैसी बातें खटकने लगीं। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों ने शंख और घड़ियाल बजाने शुरू कर दिए। इससे दोतरफा फायदा हुआ। महंगाई ने आत्महत्या कर ली और बेरोजगारी से लड़ने के लिए अग्निवीर आ गए। इस बीच क्रांति कुमार को लगा कि अचानक उनका ताप कम होने लगा है। वे देशभक्ति को सिलेबस में ले आए। इसे याद करना जरूरी बना दिया गया।

इसे देख नव-राष्ट्रवादी उछल-कूद करने लगे। यह बात खरे राष्ट्रवादियों को अखर गई। इससे वे उबल पड़े। उनके तरकश में अभी भी

कई मास्टर-स्ट्रोक बचे थे। सहसा सबकुछ अमृतमय हो उठा। उन्होंने विरोधियों पर तोते और कबूतर छोड़ दिए। वे जगह-जगह सुरक्षा और शांति का संदेश वितरित करने लगे। इससे प्रभावित हो लाभार्थियों ने तुरत-फुरत राष्ट्रवाद की शपथ ले ली। जो बचे, वे पिंजरे में बंद हो गए। उधर ईमानदार सुरापान में व्यस्त थे और इधर पांच ट्रिलियन के कटोरे में सुधा-पान होने लगा।

मेरी आंखों के सामने इतनी अच्छी फिल्म चल रही थी कि तभी पर्दा फाड़कर अच्छे दिनों की पुकार लगाने वाले और क्रांति कुमार दोनों एक साथ प्रकट हो गए। मैं उधर लपकने ही जा रहा था कि श्रीमती जी मुझे झिंझोड़ने लगीं-कितनी बार कहा है कि दिन में सनीमा मत देखा करो। बड़ी देर से पता नहीं क्या अंट-शंट बक रहे हो! अपना घर देखो। कितने दिन से टपक रहा है। इसे जोड़ लो फिर देश जोड़ लेना।

● प्रमोद दीक्षित 'मलय'



**For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us**

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA₂ and HbF

Flexible

to solve more testing needs

Comprehensive

B-thalassemia and
diabetes testing

Easy

for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or HbA₂/FIA_{1c} testing using primary tube sampling—so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, it's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress—and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

 C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5  Email : shbple@rediffmail.com
 Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687



SMILES TO A MILLION ENERGY SECURITY TO A BILLION



MCL

MAHANADI COALFIELDS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)

Corporate Office: At/Po.- Jagruti Vihar, Burla, Sambalpur, Odisha-768 020

www.mahanadicoal.in



mahanadicoal



mahanadicoal